



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 8—अप्रैल 14, 2007, शनिवार/चैत्र 18—चैत्र 24, 1929
No. 15] NEW DELHI, APRIL 8—APRIL 14, 2007, SATURDAY/CHAITRA 18—CHAITRA 24, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 986.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “कार्गिल फॉर लेटर एक्सप्रेस, सी एम डी ए टी रावरा II, तृतीय तल, गांधी इरविन रोड, एगमोरा, चेन्नई” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी:

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहां इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात; फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;

- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारित की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2004-05 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था में क्रियाकलाप वैध नहीं है अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं.-23/2007 फा. सं. 197/143/2006-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 6th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 986.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Council for Leather Exports, CMDAT Tower II, 3rd Floor, Gandhi Irwin Road, Egmore, Chennai" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:

- the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- the Institution will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2004-05 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 23/2007/F. No. 197/143/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 987.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, एस सी ओ 89-90, सेक्टर 34 ए, सब सिटी सेन्टर, चंडीगढ़-160022” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी:-

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2006-07 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उममें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 31/2007/फा. सं. 197/79/2006-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 15th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 987.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Punjab Infrastructure Development Board, SCO 89-90, Sector 34-A, Sub City Centre, Chandigarh-160022" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely :—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) the Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2006-07 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 31/2007/F. No. 197/79/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 988.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि "श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य, महासंस्थानम् दक्षिणमन्य, श्री शारदा पीठम् शृंगेरी-577139" (इसके बाद "संस्था" कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :—

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहां इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से पंचाल पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वच्छक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;

- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अधिस्तम्भ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
 - (घ) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
 - (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
 - (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की करार्थ्यता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक् रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2005-06 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था में क्रियाकलाप वैध नहीं है अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 32/2007/फा. सं. 197/132/2006-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 15th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 988.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (v) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasanasthanam Dakshinamnya Sri Sharada Peetham, Sringeri-577139" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely :—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Years 2005-06 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 32/2007/F. No. 197/132/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 989.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा “दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन, नई दिल्ली” को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (i) कर निर्धारिती अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन उक्त खंड (23) द्वारा यथा संशोधित धारा 11 की उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अनुसार पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के लिए जिसे बोर्ड द्वारा उक्त खंड (23) के तीसरे उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचित किया जा सकता है, धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (ज्वेल-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;
- (iii) कर निर्धारिती किसी संगठन अथवा इससे संबद्ध किसी संस्था के अनुदान को छोड़कर, अपनी आय के किसी हिस्से को किसी भी तरीके से अपने सदस्यों को वितरित नहीं करेगा;
- (iv) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

[अधिसूचना सं. 50/2007/फा. सं. 196/14/2002-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 15th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 989.—In exercise of powers conferred by the clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “Delhi Lawn Tennis Association, New Delhi” for the purpose of the said clause for the assessment years 2000-2001 to 2002-2003, subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-sections (2) and (3) of Section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provisions to the aforesaid clause (23) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and
- (iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 50/2007/F. No. 196/14/2002-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 990.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा “दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन, नई दिल्ली” को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्

- (i) कर निर्धारिती अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन उक्त खंड (23) द्वारा यथा संशोधित धारा 11 की उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अनुसार पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के लिए जिसे बोर्ड द्वारा उक्त खंड (23) के तीसरे उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचित किया जा सकता है, धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (ज्वेयर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;
- (iii) कर निर्धारिती किसी संगठन अथवा इससे संबद्ध किसी संस्था को अनुदान को छोड़कर, अपनी आय के किसी हिस्से को किसी भी तरीके से अपने सदस्यों को वितरित नहीं करेगा;
- (iv) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

[अधिसूचना सं. 51/2007/फा. सं. 196/14/2002-आयकर नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 15th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 990.—In exercise of powers conferred by the clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies “Delhi Lawn Tennis Association, New Delhi” for the purpose of the said clause for the assessment years 1997-1998 to 1999-2000, subject to the following conditions, namely:

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-section (2) and (3) of Section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provisions to the aforesaid clause (23) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and
- (iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 51/2007/F. No. 196/14/2002-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 991.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा “दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन, नई दिल्ली” को कर निर्धारण वर्ष 1990-1991 से 1992-1993 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्

- (i) कर निर्धारिती अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन उक्त खंड (23) द्वारा यथा संशोधित धारा 11 की उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अनुसार पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के लिए जिसे बोर्ड द्वारा उक्त खंड (23) के तीसरे उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचित किया जा सकता है, धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेंवर-जवाहरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;
- (iii) कर निर्धारिती किसी संगठन अथवा इससे संबद्ध किसी संस्था को अनुदान को छोड़कर, अपनी आय के किसी हिस्से को किसी भी तरीके से अपने सदस्यों को वितरित नहीं करेगा;
- (iv) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

[अधिसूचना सं. 52/2007/फा. सं. 196/14/2002-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 15th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 991.—In exercise of powers conferred by the clause (23) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Delhi Lawn Tennis Association, New Delhi" for the purpose of the said clause for the assessment years 1990-1991 to 1992-93, subject to the following conditions, namely:

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate it for application, in consonance with the provisions of sub-section (2) and (3) of Section 11 as modified by the said clause (23) for such accumulation wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture or any other article as may be notified by the Board under the third provisions to the aforesaid clause (23) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) the assessee will not distribute any part of its income in any manner to its members except as grants to any association or institution affiliated to it; and
- (iv) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

[Notification No. 52/2007/F. No. 196/14/2002-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 992.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि "कैसर, एड एंड रिसर्च फाउंडेशन, बाईकुल्ला म्यूनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, भूतल, कमरा सं. 15-18, एम एम जोशी मार्ग, 'एस' ब्रिज के पास, बाईकुल्ला (पश्चिम), मुम्बई-400011" (इसके बाद "संस्था" कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी:

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2007-08 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 55/2007/फा. सं. 197/108/2006-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 992.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Cancer Aid & Research Foundation, Byculla Municipal School Building, Gr. Floor, R.M. No. 15-18, N.M. Joshi Marg, Near 'S' Bridge, Byculla (West), Mumbai-400011" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely :—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2007-08 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 55/2007/F. No. 197/108/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 993.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “सिटी मिशन ऑफ इंडिया, सी एम आई चिल्ड्रेन्स होम, पुष्प विहार कालोनी, एस.बी. रोड, अम्बेबाडी, पो.बा. नं. 8249, दहिसर, मुम्बई-400068, महाराष्ट्र मुम्बई” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी:

नामत:

(क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;

(ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;

(घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगी;

(ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

(च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरे प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2006-07 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था में क्रियाकलाप वैध नहीं है अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 56/2007/फा. सं. 197/99/2006-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 993.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "City Mission of India, CMI Childrens Home, Pushpa Vihar Colony, S.V. Road, Ambewadi, P.B. No. 8249, Dahisar, Mumbai-400068, Maharashtra Mumbai" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) the Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such Recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2006-07 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 56/2007/F. No. 197/99/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2007

(आयकर)

क्र.आ. 994.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि "सी आर वाई-चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू, 189/ए, आनन्द एस्टेट, सेन गुरुजी मार्ग, मुम्बई-400011" (इसके बाद "संस्था" कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी;

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करेगा;

- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरे प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की काराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2006-07 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 57/2007/फा. सं. 197/2/2007-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 994.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "CRY-Child Relief and You, 189/A, Anand Estate, Sane Guruji Marg, Mumbai-400011" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) the Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2006-07 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 57/2007/F. No. 197/02/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 995.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “नेशनल कल्चर फण्ड, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग, दूसरा तल, ‘बी’ विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली-110001” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी, नामतः :—

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
 - (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
 - (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
 - (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगी;
 - (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
 - (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2003-04 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 58/2007/फा. सं. 197/133/2006-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 995.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of “National Culture Fund, Ministry of Tourism & Culture, Department of Culture, 2nd Floor, “B” Wing, Janpath Bhavan, Janpath, New Delhi-11 0001 (hereinafter the “Institution”) shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely :—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives;
- (f) the Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below Sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2003-04 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 58/2007/F. No. 197/133/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 996.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “संत निरंकारी मंडल, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली-110009” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :-

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय का संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगी;

- (ड) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2007-08 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं है अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 59/2007/फा. सं. 197/09/2006-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 27th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 996.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (v) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Sant Nirankari Mandal, Sant Nirankari Colony, Delhi- 110009" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2007-08 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 59/2007/F.No. 197/09/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 997.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “दि ट्रिब्यून ट्रस्ट, चंडीगढ़, सेक्टर 29सी, चंडीगढ़” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी, नामतः:

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
 - (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
 - (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
 - (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगी;
 - (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
 - (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2007-08 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 60/2007/फा. सं. 197/67/2006-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 27th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 997.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf “The Tribune Trust, Chandigarh, Sector 29C, Chandigarh” (hereinafter the “Institution”) shall not be included in the total income of such person as assessable subject to the following conditions :—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contribution and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;

- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below Sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2007-08 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 60/2007/F.No. 197/67/2006-ITA-II]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 998.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “ द चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, सी.एस.आई. सेंटर, संख्या 5, व्हाइट रोड, पो. बा. सं. 688, चेन्नई-600014 ” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी, नामतः :-

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (ज्वेल-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2007-08 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं है अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

5. यह अधिसूचना दिनांक 21-11-2006 की पूर्व अधिसूचना सं. 354/2006 के अधिक्रमण में है।

[अधिसूचना सं. 62/2007/फा. सं. 197/113/2006-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 998.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (v) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "The Church of South India Trust Association, CSI Centre, No. 5, Whites Road, P. B. No. 688, Chennai-600014" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely :—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below Sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2007-08 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

5. This notification is in super-cession on the earlier notification No. 354/2006 dated 21-11-2006.

[Notification No. 62/2007/F. No. 197/113/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2007

(आयकर)

क्र.आ. 999.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि "चेन विमेन डेवलपमेंट सोसायटी, चेन टाउन, जिला मोन, नागालैंड" (इसके बाद "संस्था" कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी, नामतः :—

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्तरात् उस उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
 - (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
 - (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
 - (घ) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के सम्मुख दाखिल करेगी;
 - (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों के धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएगी।
 - (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक् रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2006-07 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 63/2007/फा. सं. 197/04/2007-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 999.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Chen Women Development Society, Chen town, Mon District, Nagaland" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.

- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2006-07 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 63/2007/F. No. 197/04/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2007

(आयकर)

का.आ. 1000.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “श्री ब्रह्मतंत्र स्वतंत्र परकलस्वामी मठ, क्रिष्णविलास रोड (जे. एम. पैलेस के समीप), देवराज मोहल्ला, मैसूर-570024” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :-

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होती चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 1997-98 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 64/2007/फा. सं. 197/14/2007-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1000.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (v) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Sri Bramhatantra Swatantra Parakalaswamy Mutt, Krishavilas Road (Near J. M. Palace), Devaraja Mohalla, Mysore-570024" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) the Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub section (2) of section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 1997-98 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 64/2007/F. No. 197/14/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1001.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि, मैसर्स बेलांकनी इन्फार्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 43 इलेक्ट्रोनिक्स सिटी, फेस-II, हॉसूर रोड, बंगलौर-560100 में है जो एस वाई सं. 43,44 पार्ट तथा 46 पार्ट, बंगलौर, कर्नाटक-560 100 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 5-12-2006 के पत्र सं. 15/155/2005-आई डी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स वेलांकनी इन्फार्मेशन सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड बंगलौर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स वेलांकनी इन्फार्मेशन सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड बंगलौर द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है :

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : मैसर्स वेलांकनी इन्फार्मेशन सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड बंगलौर
- (ii) प्रस्तावित स्थान : एस वाई सं. 43, 44 पार्ट एंड 46 पार्ट कर्नाटक-560100
- (iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल : 87382.12 वर्ग मीटर
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी संहिता		विवरण		
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी
क	2 एवं 3	--	--	--
ख	4	--	--	--
ग	7	75	--	--
घ	8	89	892	--
ङ	8	89	893	--
च	8	89	894	--
छ	8	89	895	--

- (v) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत : 96.44%
- (vi) वाणिज्य उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत : 3.56%
- (vii) औद्योगिक यूनिटों की प्रस्तावित संख्या : 08 यूनिटें
- (viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में) : 117.07 करोड़
- (ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में) : 107.52 करोड़
- (x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में) : 116.28 करोड़
- (xi) औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि : फरवरी, 2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित विकास अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा, धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण भी शामिल हैं, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स वेलांकनी इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध हो जायेगा और मैसर्स वेलांकनी इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर ऐसी अवैधता की प्रतिक्रिया किसी के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु है जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है।

10. यदि मैसर्स वेलांकनी इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स वेलांकनी इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 68/2007/फा. सं. 178/24/2007-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 21st March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1001.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Velankani Information Systems Private Limited, having Registered Office at 43 Electronics City, Phase-II, Hosur Road, Bangalore-560 100, is developing an Industrial Park at Sy No. 43, 44 Part and 46 Part, Bangalore, Karnataka- 560 100;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/155/2005-ID dated 5-12-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-1A of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Velankani Information Systems Private Limited, Bangalore, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Velankani Information Systems Private Limited, Bangalore.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : M/s. Velankani Information Systems Private Limited,
- (ii) Proposed location : Sy No. 43, 44 Part and 46 Part, Bangalore, Karnataka-560100
- (iii) Area of Industrial Park : 87382.12 Square Meters
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code

NIC Code					Description
S.No.	Section	Division	Group	Class	
A	2 & 3	—	—	—	Manufacturing
B	4	—	—	—	Electricity Gas and Water
C	7 75	—	—	—	Communication services
D	8	89	892	—	Data processing, software development and computer consultancy services.
E	8	89	893	—	Business and management Consultancy activities
F	8	89	894	—	Architectural and engineering and other technical consultancy activities
G	8	89	895	—	Technical testing and analysis services.

- (v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use : 96.44%
- (vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use : 3.56%
- (vii) Minimum number of industrial units : 08 Units
- (viii) Total investments proposed (Amount in Rupees) : 117.07 crores
- (ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees) : 107.52 crores
- (x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees) : 116.28 crores
- (xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park : February, 2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more State or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Velankani Information Systems Private Limited, Bangalore, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80-IA of the Income tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Velankani Information Systems Private Limited, Bangalore, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Velankani Information Systems Private Limited, Bangalore, transfers the operation and maintenance of the Industrial park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Velankani Information Systems Private Limited, Bangalore, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 68/2007/F.No.178/24/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1002.-जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354(अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि, मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 में है, जो इंडस्ट्रियल एरिया रायसिंह नगर, रीको लिमिटेड, जिला-श्रीगंगानगर, राजस्थान-313003 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 13-12-2005 के पत्र सं. 15/145/05-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचलित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- (ii) प्रस्तावित स्थान : इंडस्ट्रियल एरिया राधासिंह नगर, रीको लिमिटेड, जिला-श्रीगंगानगर, राजस्थान-313003
- (iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल : 61.77 एकड़
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप :

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

क्रम सं.	अनुभाग	एन आई सी संहिता			विवरण
		प्रभाग	समूह	श्रेणी	
क	2 और 3	--	--	--	विनिर्माण
	(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत			: 99.13%
	(vi)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत			: 00.87%
	(vii)	औद्योगिक यूनिटों की प्रस्तावित संख्या			: 30 यूनिटें
	(viii)	प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)			: 276.02 लाख
	(ix)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में)			: शून्य
	(x)	अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में)			: 241.63 लाख
	(xi)	औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि			: 31-3-2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित विकास अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. संरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवररेज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण भी शामिल हैं, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होगा तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध हो जाएगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी अवैधता की प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

- (i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।
- (ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु हो जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 69/2007/फा. सं. 178/11/2006-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1002.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing an Industrial Park at Industrial Area Raisingh Nagar, RIICO Limited, District-Sriganganagar, Rajasthan-313003;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/145/05-IP&ID dated 13-12-2005 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Rajasthan State Industrial Department & Investment Corporation Limited, Jaipur.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited
- (ii) Proposed location : Industrial Area Raisingh Nagar, RUICO Limited, District-Sanganagar, Rajasthan-313003
- (iii) Area of Industrial Park : 6077 Acres
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code

NIC Code					Description
Sl. No.	Section	Division	Group	Class	
A	2&3	—	—	—	Manufacturing

- (v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use : 99.13%
- (vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use : 00.87%
- (vii) Minimum number of industrial units : 30 Units
- (viii) Total investments proposed (Amount in Rupees) : 276.02 lakhs
- (ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees) : Nil
- (x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees) : 241.63 lakhs
- (xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park : 31-3-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the Industrial park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee

undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 69/2007/F. No. 178/11/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1003.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि, मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 में है, जो रीको लिमिटेड, 1/ए झोटवाड़ा एक्स्टेंशन-1 (सरनाडूंगर) जयपुर-302005 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 4-5-2006 के पत्र सं. 15/93/05-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम | : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड |
| (ii) प्रस्तावित स्थान | : रीको लिमिटेड, 1/ए, झोटवाड़ा एक्स्टेंशन-1 (सरनाडूंगर) जयपुर-302 005 |
| (iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल | : 144.36 एकड़ |
| (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप | : |

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी संहिता		विवरण
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग
क	2 और 3	समूह
		श्रेणी
		विनिर्माण
(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत	: 100%
(vi)	वाणिज्य उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत	: शून्य
(vii)	औद्योगिक यूनिटों की प्रस्तावित संख्या	: 261 यूनिटें
(viii)	प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)	: 10,50,20,000

- (ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में) : शून्य
- (x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में) : 9,01,49,000/-
- (xi) औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि : 31-3-2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित विकास अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेंज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 में उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण भी शामिल हैं, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों का औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 डी क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 डी क की उप-धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध हो जाएगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी अवैधता की किसी प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु है जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निर्धारित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट को संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 70/2007/फा. सं. 178/113/2006-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1003.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing an Industrial Park at RIICO Limited, 1/A Jhotwara Extension-I, (Sarnadungar), Jaipur-302 005;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/93/05-IP&ID dated 4-5-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited
- (ii) Proposed location : RIICO Limited, 1/A Jhotwara Extension-I, (Sarnadungar), Jaipur-302 005
- (iii) Area of Industrial Park : 144.36 Acres
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC Code					
S. No.	NIC Code				Description
	Section	Division	Group	Class	
A	2&3	—	—	—	Manufacturing

- (v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use : 100%
- (vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use : Nil
- (vii) Minimum number of industrial units : 261 Units
- (viii) Total investments proposed (Amount in Rupees) : 10,50,20,000
- (ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees) : Nil
- (x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees) : 9,01,49,000
- (xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park : 31-3-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (3) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the available industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purposes of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80-IA of the Income tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if—

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the industrial park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 70/2007/F. No. 178/113/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1004.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1997 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिभूषण की है;

और जबकि, मैसर्स डाइनामिक कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि. लक्ष्मी साइबर पार्क, 8-2-682, एवेन्यू-1 (रोड नं. 12), बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 034 लक्ष्मी बिल्डिंग, 1-8-448/1, एसपी रोड तालुका एंड जिला हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500 034 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 5-12-2006 के पत्र सं. 15/172/2005-आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स डाइनामिक कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., हैदराबाद द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स डाइनामिक कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., हैदराबाद द्वारा औद्योगिक पार्क को गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : डाइनामिक कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.,
- (ii) प्रस्तावित स्थान : लक्ष्मी बिल्डिंग, 1-8-448/1, एस पी रोड तालुका एंड जिला-सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश-500 034
- (iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल : 24297.50 वर्ग फीट
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी संहिता		विवरण		
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी
क	7	75	—	—
ख	8	89	892	—
ग	8	89	893	—
घ	8	89	894	—
ङ	8	89	895	—

- (v) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत : 90.60%
- (vi) वाणिज्य उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत : 9.40%
- (vii) औद्योगिक यूनिटों की प्रस्तावित संख्या : 03 यूनिटें
- (viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपये में) : 3.20 करोड़
- (ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपये में) : 2.00 करोड़
- (x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपये में) : 3.00 करोड़
- (xi) औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि : अप्रैल, 2005

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. संरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेंज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण भी शामिल हैं, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स डाइनामिक कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., हैदराबाद उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध हो जाएगा और मैसर्स डाइनामिक कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., हैदराबाद ऐसी किसी अवैधता की किसी प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु है जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है।

10. यदि मैसर्स डाइनामिक कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., हैदराबाद (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपयुक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपयुक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स डाइनामिक कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि., हैदराबाद औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 71/2007/फा. सं. 178/15/2007-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1004.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Dynamic Constructions Private Limited, Laxmi Cyber Centre, 8-2-682, Avenue-1 (Road No. 12), Banjara Hills, Hyderabad-500 034, is developing an Industrial Park at Laxmi Building, 1-8-448/1, S. P. Road, Taluka and District-Secunderabad, Andhra Pradesh-5000 34;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/172/05-ID dated 5-12-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Dynamic Constructions Private Limited, Hyderabad, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Dynamic Constructions Private Limited, Hyderabad.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Dynamic Constructions Private Limited,
(ii) Proposed location : Laxmi Building, 1-8-448/1, S. P. Road, Taluka & District Secunderabad, Andhra Pradesh-500034
(iii) Area of Industrial Park : 24297.50 Square Feet
(iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC Code

		NIC Code			Description
S. No.	Section	Division	Group	Class	
A	7	75	—	—	Communication Services.
B	8	89	892	—	Data Processing, software development and computer consultancy services.
C	8	89	893	—	Business and management consultancy activities.
D	8	89	894	—	Architectural and engineering and other technical consultancy activities.
E	8	89	895	—	Technical testing and analysis services.

- (v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use : 90.60%
(vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use : 9.40%
(vii) Minimum number of industrial units : 03 Units
(viii) Total investments proposed (Amount in Rupees) : 3.20 crores
(ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees) : 2.00 crores
(x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees) : 3.00 crores
(xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park : April, 2005

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more State or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Dynamic Constructions Private Limited, Hyderabad, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80-IA of the Income tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Dynamic Constructions Private Limited, Hyderabad, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Dynamic Constructions Private Limited, Hyderabad, transfers the operation and maintenance of the Industrial Park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-110002 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Dynamic Constructions Private Limited, Hyderabad, to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, shall invalidate the approval of the Industrial Park.

[Notification No. 71/2007/F. No. 178/15/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2007

(आयकर)

का.आ. 1005.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 14) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि, मैसर्स जी अमरेंदर रेड्डी, लक्ष्मी साइबर सेंटर, 8-2-682, एवेन्यू-1 (रोड नं. 12) बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 034 8-2-681/3 और 3ए, लक्ष्मी साइबर सेंटर, रोड नं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500 034 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम और शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 5-12-2006 के पत्र सं. 15/164/05-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स जी अमरेंदर रेड्डी, हैदराबाद द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स जी अमरेंदर रेड्डी, हैदराबाद द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : जी अमरेंदर रेड्डी, हैदराबाद
- (ii) प्रस्तावित स्थान : 8-2-682/3 और 3ए, लक्ष्मी साइबर सेंटर, रोड नं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500 034
- (iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल : 75,918 वर्ग मीटर

(iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप					
एन आई सी संहिता					विवरण
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी	
क	7	75	—	—	संचार सेवाएं
ख	8	89	892	—	डाटा प्रोसेसिंग, साफ्टवेयर विकास तथा कम्प्यूटर कन्सल्टेंसी सेवाएं
ग	8	89	893	—	कारोबार तथा प्रबंधन कंसल्टेंसी कार्यकलाप
घ	8	89	894	—	वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरी एवं अन्य तकनीकी कंसल्टेंसी कार्यकलाप
ङ	8	89	895	—	तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण सेवाएं

(v) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत

: 90.13%

(vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत

: 9.87%

(vii) औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या

: 03 यूनिटें

(viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)

: 10.48 करोड़

(ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में)

: 6.00 करोड़

(x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में)

: 10.00 करोड़

(xi) औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि

: अप्रैल, 2005

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित विकास अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. संरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण भी शामिल हैं, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स जी. अमरेंदर रेड्डी, हैदराबाद उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन वैध रहेगा और मैसर्स जी. अमरेंदर रेड्डी, हैदराबाद ऐसी किसी प्रतिक्रिया की अवैधता के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु है जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है।

10. यदि मैसर्स जी अमरेंदर रेड्डी, हैदराबाद (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती

उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स जी. अमरेंदर रेड्डी, हैदराबाद औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 72/2007/फा. सं. 178/16/2007-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1005.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. G. Amarender Reddy, Laxmi Cyber Centre, 8-2-682, Avenue-1 (Road No. 12), Banjara Hills, Hyderabad-500 034, is developing an Industrial Park at 8-2-681/3 & 3A, Laxmi Cyber Centre, Road No. 12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh-500034;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/164/05-ID dated 5-12-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. G. Amarender Reddy, Hyderabad, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. G. Amarender Reddy, Hyderabad.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : G. Amarender Reddy
- (ii) Proposed location : 8-2-681/3 & 3A, Laxmi Cyber Centre, Road No. 12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh-500 034
- (iii) Area of Industrial Park : 75,918 Square Feet
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code					
		NIC Code			Description
S.No.	Section	Division	Group	Class	
A	7	75	—	—	Communication Services.
B	8	89	892	—	Data Processing, software development and computer consultancy services.
C	8	89	893	—	Business and management consultancy activities.
D	8	89	894	—	Architectural and engineering and other technical consultancy activities.
E	8	89	895	—	Technical testing and analysis services.

(v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use	:	90.13%
(vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use	:	9.87%
(vii) Minimum number of industrial units	:	03 Units
(viii) Total investments proposed (Amount in Rupees)	:	10.48 crores
(ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees)	:	6.00 crores
(x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees)	:	10.00 crores
(xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park	:	April, 2005

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. G. Amarender Reddy, Hyderabad, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80IA of the Income tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. G. Amarender Reddy, Hyderabad, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the Industrial Park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. G. Amarender Reddy, Hyderabad, transfers the operation and maintenance of the Industrial park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. G. Amarender Reddy, Hyderabad, to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Industrial Park.

[Notification No. 72/2007/F. No. 178/16/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1006.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां उसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354(अ) के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि, मैसर्स दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज़ लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-6, भनोट कार्नर, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली में है जो ग्राम-बन्ताखेड़ी, तहसील-रुड़की, जिला-हरिद्वार, उत्तरांचल-247 667 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियम शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 10-8-2006 के पत्र सं. 15/24/2006-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज़ लिमिटेड द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज़ लिमिटेड द्वारा औद्योगिक पार्क की गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज़ लिमिटेड
- (ii) प्रस्तावित स्थान : ग्राम-बन्ताखेड़ी, तहसील-रुड़की, जिला-हरिद्वार, उत्तरांचल-247 667
- (iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल : 4818 एकड़ (1,95,000 वर्ग मीटर)
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी सहित के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी सहित		विवरण		
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी
क	2 एवं 3	—	—	—
				विनिर्माण
	(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत		: 88.75%
	(vi)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत		: 02.77%
	(vii)	औद्योगिक यूनिटों की प्रस्तावित संख्या		: 33 यूनिटें
	(viii)	प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)		: 850.00 लाख
	(ix)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में)		: शून्य
	(x)	अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में)		: 560.00 लाख
	(xi)	औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि		: 1-3-2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित विकास अवसंरचना पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. संरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से निर्धारणीय एवं प्रयुक्त हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण भी शामिल हैं, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध हो जाएगा और मैसर्स दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड ऐसी अवैधता की किसी प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु है जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है।

10. यदि मैसर्स दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स दत्त इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में विहित शर्तों अथवा इस अधिसूचना की किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 73/2007/फा. सं. 178/12/2007-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1006.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Datt Infrastructure & Services Limited, having registered office at B-6, Bhanot Corner, Pamposh Enclave, Greater Kailash, New Delhi, is developing an Industrial Park at Village - Bantakhedi, Tehsil-Roorkee, District-Haridwar, Uttaranchal-247 667;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park *vide* Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/24/2006-IP&ID dated 10-8-2006 (corrected by Ministry of Commerce and Industry on 25-8-2006) subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Datt Infrastructure & Services Limited, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Datt Infrastructure & Services Limited.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Datt Infrastructure & Services Limited.
- (ii) Proposed location : Village-Bantakhedi, Tehsil-Roorkee, District—Haridwar, Uttaranchal-247 667
- (iii) Area of Industrial Park : 4818 Acre (1,95,000 Sqm.)
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code					
NIC Code					Description
S.No.	Section	Division	Group	Class	
A	2 & 3	—	—	—	Manufacturing
(v)	Percentage of allocable area earmarked for Industrial use				88.75%
(vi)	Percentage of allocable area earmarked for commercial use				02.77%
(vii)	Minimum number of industrial units				33 Units
(viii)	Total investments proposed (Amount in Rupees)				850.00 Lakhs
(ix)	Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees)				Nil
(x)	Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees)				560.00 Lakhs
(xi)	Proposed date of commencement of the Industrial Park				1-03-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Datt Infrastructure & Services Limited, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80IA of the Income tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Datt Infrastructure and Services Limited, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the Industrial Park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Datt Infrastructure & Services Limited, transfers the operation and maintenance of the Industrial Park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Datt Infrastructure & Services Limited, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Industrial Park.

[Notification No. 73/2007/F.No. 178/12/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1007.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10^क के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, बेला विस्टा, हैदराबाद-500082” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं है अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 74/2007/फा. सं. 197/26/2007-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1007.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of “Administrative Staff College of India, Bella Vista, Hyderabad-500 082” (hereinafter the “Institution”) shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely :

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub section (2) of section 288 and furnish along with the return of income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2005-2006 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 74/2007/F. No. 197/26/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1008.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110001” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक् रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 1998-99 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 75/2007/फा. सं. 197/20/2002-आयकर नि. I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1008.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Federation House, Tansen Marg, New Delhi-110001" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions :—

- (i) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (ii) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of the Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (iv) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961;

- (v) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (vi) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 1998-99 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 75/2007/F. No. 197/20/2002-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च 2007

(आयकर)

का.आ. 1009.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “महानंदीश्वर स्वामी देवस्थानम् महानंदी कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक दंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और सम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 1994-95 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था में क्रियाकलाप वैध नहीं है अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 76/2007/फा. सं. 197/110/2006-आयकर नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1009.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (v) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of “Mahanandeeswara Swamy Devasthanam, Mahanandi, Kurnool District, A. P.” (hereinafter the “Institution”) shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 1994-95 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 76/2007/F. No. 197/110/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1010.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “श्री कावले मठ संस्थान, 91 बाणगंगा रोड, वाल्हेस्वर, मुम्बई-400006” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;

- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपना आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और सम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था में क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अवकाशों से किन्हीं शर्तों के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 77/2007/फा. सं. 197/129/2005-आयकर नि.]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1010.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (v) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Shree Kavle Math Samsthan, 91, Banganga Road, Walheshwar, Mumbai-400006" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:—

- the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income tax Act, 1961;
- that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2005-06 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 77/2007/F. No. 197/129/2005-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1011.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “आर्म्ड फोर्सिस फ्लैग डे फंड, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वेस्ट ब्लॉक, 4 आर के पुरम, नई दिल्ली” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौतों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 78/2007/फा. सं. 197/8/2007-आयकर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1011.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of Clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of “Armed Forces Flag Day Fund, Kendriya Sainik Board, Ministry of Defence, West Block, 4, R. K. Puram, New Delhi” (hereinafter the “Institution”) shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 1999-2000 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 78/2007/F. No. 197/08/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1012.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि “दि आस्तिक समाज, भंडारकर रोड, माटुंगा, मुम्बई-400019” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी:

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगी;

(ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

(च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2002-03 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 79/2007/फा. सं. 197/11/2007-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1012.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (v) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "The Asthika Samaj, Bhandarkar Road, Matunga, Mumbai-400019" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely :—

- (a) the institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the income tax authority in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives;
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish alongwith the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2002-03 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 79/2007/F.No. 197/11/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1013.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि "ज्वेलर फॉर एडवान्स्ड स्ट्रेटिजिक स्टडीज एम. एम. डी. डब्ल्यू पोटदार कॉम्प्लैक्स, पुणे यूनिवर्सिटी कैम्पस, गणेशखिंड, पुणे-411007" (इसके लिए "संस्था" कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय अप्रैल, 2002 के पहले दिन में या उसके पश्चात् आय एकाग्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2004-05 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था में क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं.80/2007/फा. सं. 197/102/2006-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1013.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Centre for Advanced Strategic Studies, M.M.D. W. Poddar Complex, Pune University Campus, Ganeshkhind, Pune-411007" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:—

- (a) the institution will apply its income, or accumulated for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;

- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the institution will regularly file its return of income before the income tax authority in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The institute will get its accounts audited by an accountant as defined in explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2004-05 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 80/2007/F. No. 197/102/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1014.-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि "श्री मुकाम्बिका टेम्पल, कोल्लूर-576220, उडुपि जिला" (इसके बाद "संस्था" कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी:

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 81/2007/फा. सं. 197/55/2006-आ.क.नि. I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1014.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (v) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Sri Mookambika Temple, Kollur-576220, Udupi District" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:—

- (a) the institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the institution will regularly file its return of income before the income tax authority in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The institute will get its accounts audited by an accountant as defined in explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 1996-1997 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 81/2007/F. No. 197/55/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1015.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि "श्री लक्ष्मी नृसिंह स्वामी टैम्पल निम्बाचलम (जिसे सामान्य रूप से लिम्बादरी

गुट्टा के नाम से जाना जाता है), भीमगेल (पोस्ट एण्ड मंडल) निजामाबाद जिला, आंध्र प्रदेश" (इसके बाद "संस्था" कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 के या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगी;
- (ङ) संस्था के विवरण की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक् रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 82/2007/फा. सं. 197/44/2005-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1015.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (v) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Shri Laxmi Nrusimha Swamy Temple Nimbachalam (Popularly known as Limbadri Gutta), Bheemgel (Post & Mandal), Nizamabad District, Andhra Pradesh" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely :—

- (a) the institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;

- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the institution will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The institute will get its accounts audited by an accountant as defined in explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the institution would be separately considered as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2005-06 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

(Notification No. 82/2007/F. No. 197/44/2005-ITA-I)

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आय कर)

क्र.आ. 1016.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “हरियाणा अमलगेमेटड फण्ड फार दि वेलफेयर आफ एक्स सर्विसमेन, सैनिक भवन, सैक्टर-12, पंचकुला” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगी;
- (ङ) संस्था के विधटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित व्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था में क्रियाकलाप वैध नहीं है अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं.-134/2007/फा. सं. 197/14/2004-आ.क.नि. I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1016.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Haryana Amalgamated Fund for the Welfare of Ex-Servicemen, Sainik Bhawan, Sector-12, Panchkula" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely :—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the institution will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The institute will get its accounts audited by an accountant as defined in explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 1996-1997 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 134/2007/F.No. 197/14/2004-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1017.— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि "नेशनल स्प्रिचुअल एसेम्बली ऑफ दि बेहल्स ऑफ इंडिया, बेहल्स हाउस, नई दिल्ली" (इसके बाद "संस्था" कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होता, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2001-02 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 135/2007/फा. सं. 197/118/2006-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1017.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (v) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "National Spiritual Assembly of the Bahai's of India, Bahai's House, New Delhi" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;

- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2001-02 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 135/2007/F. No. 197/118/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1018.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि "कार्डसिल फार एडवांसमेंट आफ पिपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इंडिया हैबिटेड सेंटर जोन, वी-ए, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003" (इसके बाद "संस्था" कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी;

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने वाली अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;
- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;
- (घ) संस्था आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगी;
- (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
- (च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, बिहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।

2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर संस्था की कराधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक् रूप से विचार किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 एवं आगे के लिए लागू होगी।

4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था में क्रिडाकलाप वैध नहीं है अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 136/2007/फा. सं. 197/124/2006-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1018.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of “Council for Advancement of People’s Action and Rural Technology, India Habitat Centre Zone, V-A Lodhi Road, New Delhi-110003” (hereinafter the “Institution”) shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives;
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub-section (2) of Section 288 and furnish along with the return of income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 1999-2000 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 136/2007/F.No. 197/124/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1019.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि “तमिलनाडु एक्स सर्विसेस पर्सनल बेनीवोलेंट फंड, डायरेक्टोरेट ऑफ एक्स सर्विसेस वेलफेयर, 22 राजा मुथैया सालै, चेन्नई-600003” (इसके बाद “संस्था” कहा गया है) की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई आय निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी :

- (क) संस्था अपनी आय का इस्तेमाल अथवा अपनी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगी जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है तथा उस मामले में जहाँ इसकी पंद्रह प्रतिशत से अधिक आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् आय एकत्र की गई है, इसकी आय के संचयन की राशि के पंद्रह प्रतिशत से अधिक होने की अवधि किसी भी स्थिति में पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;
- (ख) संस्था उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से प्राप्त पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक या अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से अपनी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वीकृत योगदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगी अथवा उसे जमा नहीं करेगी;

- (ग) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
 - (घ) संस्था आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आय कर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगी;
 - (ङ) संस्था के विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।
 - (च) जैसा कि धारा 288 की उप-धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है, संस्था किसी लेखाकार द्वारा अपने खातों की लेखा परीक्षा कराएगी तथा आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी। ऐसी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट, विहित प्रारूप में लेखाकार के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं सत्यापित एवं विहित किए गए यथा अपेक्षित ब्यौरों को प्रेषित करेगी।
2. यह अधिसूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ता पर ही लागू होगी न कि इस तरह के प्राप्तकर्ता द्वारा किसी प्राप्ति अथवा आय पर। संस्था की करधेयता अथवा अन्यथा आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार पृथक रूप से विचार किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2002-03 एवं आगे के लिए लागू होगी।
4. उपर्युक्त अधिसूचना को केन्द्र सरकार के द्वारा निरस्त किया जा सकता है यदि यह बाद में पाया गया कि संस्था के क्रियाकलाप वैध नहीं हैं अथवा यदि उनका अनुपालन उन सभी अथवा उनमें से किन्हीं शर्तों के अनुसार नहीं किया जा रहा है जिनके आधार पर इसे अधिसूचित किया गया था।

[अधिसूचना सं. 137/2007/फा. सं. 197/144/2006-आ.क.नि.1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1019.— In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of the Clause (23C) of Section 10 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that any income received by any person on behalf of "Tamil Nadu Ex-Services Personnel Benevolent Fund, Directorate of Ex-Serviceman's Welfare 22, Raja Muthiah Salai, Chennai-600003" (hereinafter the "Institution") shall not be included in the total income of such person subject to the following conditions, namely:—

- (a) the Institution will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established and in a case where more than fifteen per cent of its income is accumulated on or after the 1st day of April, 2002, the period of the accumulation of the amount exceeding fifteen per cent of its income shall in no case exceed five years;
- (b) the Institution will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture, etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in anyone or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of the Section 11;
- (c) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the Institution and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (d) the Institution will regularly file its return of income before the Income tax authority in accordance with the provisions of the Income tax Act, 1961;
- (e) that in the event of dissolution of the Institution, its surplus and the assets will be given to an organization with similar objectives.
- (f) The Institute will get its accounts audited by an accountant as defined in Explanation below sub section (2) of Section 288 and furnish along with the return of Income. The report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particulars as may be prescribed.

2. This notification is applicable only to the recipients of income on behalf of the Institution and not to any other receipt or income of such recipients. Taxability or, otherwise of the income of the Institution would be separately considered as per the provisions of the Income tax Act, 1961.

3. This notification is applicable for Assessment Year 2002-03 and onwards.

4. The above notification is liable to be rescinded by the Central Government, if it is subsequently found that the activities of the Institution are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it was notified.

[Notification No. 137/2007/F. No. 197/144/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1020.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि, मैसर्स कन्याकुमारी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, रहेजा चैम्बर्स, लिंकिंग रोड एंड मेन एवेन्यू सांताक्रुज (वेस्ट), मुम्बई-400054, प्लॉट नं. 9 एवं 10, ईपीआईपी, फस्ट फेस, सर्वे नं. 146(पी) एवं 149(पी), व्हाइट फील्ड इंडस्ट्रियल एरिया, हूडी विलेज, के.आर.पुरम, तालुका-होबली, जिला-बंगलौर, कर्नाटक-560004 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 5-12-2006 के पत्र सं. 15/10/2006-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स कन्याकुमारी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है ।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स कन्याकुमारी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : कन्याकुमारी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई
- (ii) प्रस्तावित स्थान : प्लॉट नं. 9 एवं 10, ईपीआईपी, फस्ट फेस, सर्वे नं. 146(पी) एवं 149(पी), व्हाइट फील्ड इंडस्ट्रियल एरिया, हूडी विलेज, के.आर.पुरम, तालुका-होबली, जिला-बंगलौर, कर्नाटक-560004
- (iii) औद्योगिक पार्क का कुल क्षेत्रफल : 26,631 वर्ग मीटर
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

		एन आई सी संहिता			विवरण
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी	
क	7	75	--	--	संचार सेवाएं
ख	8	89	892	—	डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर परामर्शदात्री सेवाएं
ग	8	89	893	—	कारोबार और प्रबंधन परामर्शदात्री कार्यकलाप
घ	8	89	894	—	वास्तुकला और इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी परामर्शदात्री सेवाएं
ड	8	89	895	—	तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं

(v) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत	:	90.09%
(vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत	:	9.01%
(vii) औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या	:	03 यूनिटें
(viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपये में)	:	4500 लाख
(ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपये में)	:	1300 लाख
(x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपये में)	:	3900 लाख
(xi) औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की तिथि	:	मार्च, 2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएँ जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो निर्धारणीय हैं एवं वाणिज्यिक दृष्टि से उपलब्ध कराई जाती हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50 से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश भी शामिल हैं, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स कन्याकुमारी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होगा तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स कन्याकुमारी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई ऐसी किसी अवैधता की प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु हो जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया हो।

10. यदि मैसर्स कन्याकुमारी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतर्गती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतर्गती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतर्गती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट को संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स कन्याकुमारी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 138/2007/फा. सं. 178/08/2007-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30 March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1020.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Kanyakumari Builders Private Limited Raheja Chambers, Linking Road & Main Avenue, Santacruz (W), Mumbai-400 054, is developing an Industrial Park at Plot No. 9 & 10, EPIP, First Phase, Survey No. 146(P) & 149(P), White Field Industrial Area, Hoodi Village, K.R. Puram, Taluka-Hobli, District-Bangalore, Karnataka-560 004;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/10/2006-ID dated 5-12-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Kanyakumari Builders Private Limited, Mumbai, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Kanyakumari Builders Private Limited, Mumbai.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Kanyakumari Builders Private Limited
- (ii) Proposed location : Plot No. 9 & 10, EPIP, First Phase, Survey No. 146(P) & 149(P), White Field Industrial Area, Hoodi Village, K.R. Puram, Taluka-Hobli, District-Bangalore, Karnataka-560 004
- (iii) Area of Industrial Park : 26.631 Square Meters
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code					
		NIC Code			Description
S. No.	Section	Division	Group	Class	
A	7	75	—	—	Communication Services.
B	8	89	892	—	Data processing, software development and computer consultancy services.
C	8	89	893	—	Business and management consultancy activities.
D	8	89	894	—	Architectural and engineering and other technical consultancy activities.
E	8	89	895	—	Technical testing and analysis services.

(v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use	:	90.09%
(vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use	:	9.01%
(vii) Minimum number of industrial units	:	03 Units
(viii) Total investments proposed (Amount in Rupees)	:	4500.00 lakhs
(ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees)	:	1300.00 lakhs
(x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees)	:	3900.00 lakhs
(xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park	:	March, 2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian Investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Kanyakumari Builders Private Limited, Mumbai, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80IA of the Income tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Kanyakumari Builders Private Limited, Mumbai, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the Industrial Park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Kanyakumari Builders Private Limited, Mumbai, transfers the operation and maintenance of the Industrial Park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Kanyakumari Builders Private Limited, Mumbai to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Industrial Park.

[Notification No. 138/2007/F. No. 178/08/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1021.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स जी. लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी साइबर सेन्टर, 8-2-682, रोड नं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034, 8-2-682, लक्ष्मी साइबर सेन्टर, रोड नं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500034, में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 5-12-2006 के पत्र सं. 15/167/2005-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स जी. लक्ष्मी देवी, हैदराबाद द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स जी. लक्ष्मी देवी, हैदराबाद द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : मैसर्स जी. लक्ष्मी देवी,
- (ii) प्रस्तावित स्थान : 8-2-682, लक्ष्मी साइबर सेन्टर, रोड नं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500034
- (iii) औद्योगिक पार्क का कुल क्षेत्रफल : 60,167 वर्ग फीट
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी संहिता		विवरण		
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी
क	7	75	--	--
ख	8	89	892	--
ग	8	89	893	--
घ	8	89	894	--
ङ	8	89	895	--

- | | | |
|---|---|--------------|
| (v) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत | : | 90.93% |
| (vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत | : | 9.07% |
| (vii) औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या | : | 03 यूनिटें |
| (viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में) | : | 8.27 करोड़ |
| (ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में) | : | 6.00 करोड़ |
| (x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में) | : | 8.00 करोड़ |
| (xi) औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की तिथि | : | अप्रैल, 2005 |

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएँ जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो निर्धारणीय है एवं वाणिज्यिक दृष्टि से उपलब्ध कराई जाती हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50 से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश भी शामिल है, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स जी. लक्ष्मी देवी, हैदराबाद उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होगा तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन/अवैध रहेगा और मैसर्स जी. लक्ष्मी देवी, हैदराबाद, जयपुर ऐसी किसी अवैधता की प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि :

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना वृद्धिपूर्ण सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु हो जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया हो।

10. यदि मैसर्स जी. लक्ष्मी देवी, हैदराबाद (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुमोदन किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, ब्रह्मगो भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट को संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क योजना, 2002 में शामिल शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाते हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है। यदि मैसर्स जी. लक्ष्मी देवी, हैदराबाद किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किसी एक को भी संशोधन अथवा परिवर्तन में पत्र लगाना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देगा।

[अधिसूचना सं. 139/2007/फा. सं. 178/30/2007-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1021.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for Industrial Park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period

beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and *vide* number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. G. Laxmi Devi, Laxmi Cyber Centre, 8-2-682, Road No. 12, Banjara Hills, Hyderabad-500 034 is developing an Industrial Park at 8-2-682, Laxmi Cyber Centre, Road No. 12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh-500 034.

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park *vide* Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/167/2005-ID dated 5-12-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-1A of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. G. Laxmi Devi, Hyderabad, as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an Industrial Park by M/s. G. Laxmi Devi, Hyderabad

1. (i) Name of the Industrial Undertaking, : M/s. G. Laxmi Devi,
- (ii) Proposed location : 8-2-682, Laxmi Cyber Centre Road No. 12,
Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh-500 034
- (iii) Area of Industrial Park : 60167 Square Feet
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code					
NIC Code					Description
S. No.	Section	Division	Group	Class	
A	7	75	—	—	Communication Services.
B	8	89	892	—	Data processing, software development and computer consultancy services.
C	8	89	893	—	Business and management consultancy activities.
D	8	89	894	—	Architectural and engineering and other technical consultancy activities.
E	8	89	895	—	Technical testing and analysis services.

- (v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use : 90.93%
- (vi) Percentage of allocable area earmarked for Commercial use : 9.07%
- (vii) Minimum number of Industrial Units : 03 Units
- (viii) Total investments proposed (Amount in Rupees) : 8.27 Crore
- (ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees) : 6.00 Crore
- (x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees) : 8.00 Crore
- (xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park : April, 2005

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more State or Central Tax Laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or Non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. G. Laxmi Devi, Hyderabad, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. G. Laxmi Devi, Hyderabad, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the Industrial Park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. G. Laxmi Devi, Hyderabad, transfers the operation and maintenance of the Industrial Park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. G. Laxmi Devi, Hyderabad, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Industrial Park.

[Notification No. 139/2007/F.No. 178/30/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1022.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) दिनांक 1 अप्रैल 2002 के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 में है, ग्रोथ सेंटर पलसाना, जिला-सीकर, राजस्थान-332001 में एक ग्रोथ सेंटर का विकास कर रहा है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 9-5-2006 के पत्र सं. 15/99/2005-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त ग्रोथ सेंटर को अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा गोथ सेंटर गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- (ii) प्रस्तावित स्थान : ग्रोथ सेन्टर पलसाना, जिला-सीकर, राजस्थान-332001
- (iii) ग्रोथ सेन्टर का कुल का क्षेत्रफल : 88.23 एकड़
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी संहिता		विवरण	
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	श्रेणी
क	2 एवं 3	—	—
			विनिर्माण
	(v) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत		: 94.07%
	(vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत		: 05.92%
	(vii) औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या		: 96 यूनिटें
	(viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपये में)		: 5,94,00,000
	(ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपये में)		: शून्य
	(x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपये में)		: 4,69,54,000
	(xi) ग्रोथ सेन्टर के आरंभ होने की तिथि		: 31-03-2006

2. किसी ग्रोथ सेन्टर में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अब, संरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवर, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो निर्धारणीय हैं एवं वाणिज्यिक दृष्टि से उपलब्ध कराई जाती हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी ग्रोथ सेन्टर के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश भी शामिल है, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के ग्रोथ सेन्टर में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान ग्रोथ सेन्टर का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त ग्रोथ सेन्टर के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उपधारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी अवैधता की प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त ग्रोथ सेन्टर की अवस्थिति हेतु हो जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया हो।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) ग्रोथ सेन्टर का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतर्गती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतर्गती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतर्गती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट को संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, ग्रोथ सेन्टर के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 140/07/फा. सं. 178/134/2006-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1022— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193 (E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354 (E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing a Growth Centre at Growth Centre Palsana, District-Sikar, Rajasthan, 332 001;

And whereas the Central Government has approved the said Growth Centre vide Ministry of Commerce and Industry letter no. 15/99/2005-IP&ID dated 9-5-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of a Growth Central M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur.

- | | |
|---|---|
| 1. (i) Name of the Industrial Undertaking | : Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited |
| (ii) Proposed location | : Growth Centre Palsana, District-Sikar, Rajasthan-332 001 |
| (iii) Area of Growth Centre | : 88.23 Acres |

(iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code				
NIC Code				Description
S. No.	Section	Division	Group	Class
A	2&3	—	—	—
				Manufacturing
	(v)	Percentage of allocable area earmarked for Industrial use		: 94.07%
	(vi)	Percentage of allocable area earmarked for commercial use		: 05.92%
	(vii)	Minimum number of industrial units		: 96 Units
	(viii)	Total investments proposed (Amount in Rupees)		: 5,94,00,000
	(ix)	Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees)		: Nil
	(x)	Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees)		: 4,69,54,000
	(xi)	Proposed date of commencement of the Growth Centre		: 31-3-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in a Growth Centre shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of a Growth Centre which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of a Growth Centre. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Growth Centre.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Growth Centre during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Growth Centre is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1(xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80IA of the Income tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the Growth Centre for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the Growth Centre (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may

withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Growth Centre.

[Notification No. 140/07/F. No. 178/134/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1023.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354(अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि, मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 में है, स्पिलिट ग्रोथ सेन्टर, करनी, जिला-बीकानेर, राजस्थान-334001 में एक ग्रोथ सेन्टर का विकास कर रहा है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 24-4-2006 के पत्र सं. 15/212/2005-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त ग्रोथ सेन्टर को अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा ग्रोथ सेन्टर गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- (ii) प्रस्तावित स्थान : एस.जी.सी. करनी, जिला-बीकानेर, राजस्थान-334001
- (iii) ग्रोथ सेन्टर का कुल क्षेत्रफल : 108.00 एकड़
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी संहिता				विवरण
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी
क	2 एवं 3	—	—	—
				विनिर्माण
	(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत	:	90.33%
	(vi)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत	:	09.67%
	(vii)	औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या	:	209 यूनिटें
	(viii)	प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)	:	534.05 लाख
	(ix)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में)	:	शून्य
	(x)	अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में)	:	484.20 लाख
	(xi)	ग्रोथ सेन्टर के आरंभ होने की तिथि	:	31-3-2006

2. किसी ग्रोथ सेन्टर में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेंज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो निर्धारणीय हैं एवं वाणिज्यिक दृष्टि से उपलब्ध कराई जाती हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी ग्रोथ सेन्टर के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50 से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश भी शामिल हैं, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के ग्रोथ सेन्टर में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान ग्रोथ सेन्टर का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त ग्रोथ सेन्टर के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होगा तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी अवैधता की प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त ग्रोथ सेन्टर की अवस्थिति हेतु हो जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया हो।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) ग्रोथ सेन्टर का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट को संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, ग्रोथ सेन्टर के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 141/07/फा. सं. 178/74/2006-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1023.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period

beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing a Growth Centre at Split Growth Centre, Karni, District-Bikaner, Rajasthan-334001;

And whereas the Central Government has approved the said Growth Centre vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/212/2005-IP&ID dated 24-4-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-1A of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of a Growth Centre by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited
- (ii) Proposed location : S.G.C. Karni, District-Bikaner, Rajasthan-334001
- (iii) Area of Growth Centre : 108.00 Acres
- (iv) Proposed activities

Nature of Industrial activity with NIC code					
		NIC Code			Description
S.No.	Section	Division	Group	Class	
A	2&3	—	—	—	Manufacturing
	(v)	Percentage of allocable area earmarked for Industrial use			: 90.33%
	(vi)	Percentage of allocable area earmarked for commercial use			: 09.67%
	(vii)	Minimum number of industrial units			: 209 Units
	(viii)	Total investments proposed (Amount in Rupees)			: 534.05 lakhs
	(ix)	Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees)			: Nil
	(x)	Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees)			: 484.20 lakhs
	(xi)	Proposed date of commencement of the Growth Centre			: 31-3-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Growth Centre shall not be less than 50% of the total project cost, in the case of a Growth Centre which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of a Growth Centre. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Growth Centre.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Growth Centre during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Growth Centre is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80IA of the Income tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the Growth Centre for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the Growth Centre (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Growth Centre.

[Notification No. 141/07/F.No. 178/74/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च 2007

(आयकर)

का.आ. 1024.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि, मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 में है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर खारा, जिला-बीकानेर, राजस्थान-334001 में एक ग्रोथ सेन्टर का विकास कर रहा है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 24-4-2006 के पत्र सं. 15/211/2005-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त ग्रोथ सेन्टर को अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा ग्रोथ सेन्टर गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है, वे हैं—

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- (ii) प्रस्तावित स्थान : इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर खारा, जिला-बीकानेर, राजस्थान-334001
- (iii) ग्रोथ सेन्टर का कुल क्षेत्रफल : 726.91 एकड़
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी संहिता		विवरण		
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी
क	2 और 3	-	-	-
				विनिर्माण
	(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत	:	95.59 %
	(vi)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत	:	02.47%
	(vii)	औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या	:	381 यूनिटें
	(viii)	प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)	:	1209.78 लाख
	(ix)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में)	:	शून्य
	(x)	अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में)	:	1153.31 लाख
	(xi)	ग्रोथ सेन्टर के आरंभ होने की तिथि	:	31-3-2006

2. किसी ग्रोथ सेन्टर में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो निर्धारणीय हैं एवं वाणिज्यिक दृष्टि से उपलब्ध कराई जाती हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी ग्रोथ सेन्टर के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश भी शामिल है, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के ग्रोथ सेन्टर में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान ग्रोथ सेन्टर का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त ग्रोथ सेन्टर के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होगा तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उपधारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी अवैधता की प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

- (i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त ग्रोथ सेन्टर की अवस्थिति हेतु हो जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया हो।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) ग्रोथ सेन्टर का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट को संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, ग्रोथ सेन्टर के अनुमोदन को अवैध बना देगा।

[अधिसूचना सं. 142/07/फा.सं. 178/75/2006-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1024.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of Sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing a Growth Centre at Industrial Growth Centre, Khara, District-Bikaner, Rajasthan-334001;

And whereas the Central Government has approved the said Growth Centre vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/211/2005-IP&ID dated 24-4-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of Sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of a Growth Centre by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur.

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | (i) Name of the Industrial Undertaking | : Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited |
| | (ii) Proposed location | : Industrial Growth Centre, Khara, District-Bikaner, Rajasthan-334001 |
| | (iii) Area of Growth Centre | : 726.91 Acres |
| | (iv) Proposed activities | : |

Nature of Industrial activity with NIC code

NIC Code					Description
S.No.	Section	Division	Group	Class	
A	2&3	—	—	—	Manufacturing

(v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use	:	95.59%
(vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use	:	02.47%
(vii) Minimum number of industrial units	:	381 Units
(viii) Total investments proposed (Amount in Rupees)	:	1209.78 lakhs
(ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees)	:	Nil
(x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees)	:	1153.31 lakhs
(xi) Proposed date of commencement of the Growth Centre	:	31-3-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in a Growth Centre shall not be less than 50% of the total project cost, in the case of a Growth Centre which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of a Growth Centre. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Growth Centre.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Growth Centre during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Growth Centre is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the Growth Centre for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the Growth Centre (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Growth Centre.

[Notification No. 142/07/F. No. 178/75/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1025.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि, मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 में है, ब्रिज इंडस्ट्रियल एरिया भरतपुर, फेस-II, जिला-भरतपुर, राजस्थान-321001 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 22-9-2006 के पत्र सं. 15/119/2005-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- (ii) प्रस्तावित स्थान : ब्रिज इंडस्ट्रियल एरिया भरतपुर, फेस-II, जिला-भरतपुर, राजस्थान-321001
- (iii) औद्योगिक पार्क का कुल क्षेत्रफल : 67.40 एकड़
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप :

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी संहिता		विवरण	
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह
क	2 और 3	—	—
			श्रेणी
			विनिर्माण
	(v) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आर्बटनीय क्षेत्र का प्रतिशत	:	100%
	(vi) वाणिज्य उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत	:	शून्य
	(vii) औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या	:	33 यूनिटें
	(viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)	:	253.02 लाख
	(ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में)	:	शून्य
	(x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में)	:	156.12 लाख
	(xi) औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि	:	31-3-2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरेंज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो निर्धारणीय हैं एवं वाणिज्यिक दृष्टि से उपलब्ध कराई जाती हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश भी शामिल हैं, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होगा तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी अवैधता की प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु हो जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया हो।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट को संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 143/2007/फा. सं. 178/28/2007-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1025.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of Sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for Industrial Park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing an Industrial Park at Brij Industrial Area Bharatpur, Phase IInd, District Bharatpur, Rajasthan-321001;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/119/2005-IP&ID dated 22-9-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of Sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an Industrial Park by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited
- (ii) Proposed Location : Brij Industrial Area Bharatpur, Phase-IIInd, District Bharatpur, Rajasthan-321 001
- (iii) Area of Industrial Park : 67.40 Acres
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code					
NIC Code					Description
S. No.	Section	Division	Group	Class	
A	2&3	—	—	—	Manufacturing

- (v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use : 100%
- (vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use : Nil
- (vii) Minimum number of industrial units : 33 Units
- (viii) Total investments proposed (Amount in Rupees) : 253.02 lakhs
- (ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees) : Nil
- (x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees) : 136.12 lakhs
- (xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park : 31-3-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost, in the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more State or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of Sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the Industrial Park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the Industrial Park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Industrial Park.

[Notification No. 143/07/F.No. 178/28/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1026.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि, मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 में है, इंडस्ट्रियल एरिया अनूपगढ़, फेस-II, जिला-श्रीगंगानगर, राजस्थान-335002 में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 26-10-2006 के पत्र सं. 15/144/2005-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किया है;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- (ii) प्रस्तावित स्थान : इंडस्ट्रियल एरिया अनूपगढ़, फेस-II, जिला-श्रीगंगानगर, राजस्थान-335002
- (iii) औद्योगिक पार्क का कुल क्षेत्रफल : 33.75 एकड़

(iv) प्रस्तावित कार्यकलाप :

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी संहिता		विवरण	
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह
क	2 एवं 3	—	—
			विनिर्माण
	(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत	: 73.90%
	(vi)	वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत	: 4.93%
	(vii)	औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या	: 42 यूनिटें
	(viii)	प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रूप में)	: 193.76 लाख
	(ix)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रूप में)	: शून्य
	(x)	अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रूप में)	: 139.76 लाख
	(xi)	औद्योगिक पार्क के आरंभ होने की प्रस्तावित तिथि	: 31-3-2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा मीवरेज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएँ जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो निर्धारणीय हैं एवं वाणिज्यिक दृष्टि से उपलब्ध कराई जाती हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ (क) के उप-पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50 से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश भी शामिल हैं, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होगा तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप-धारा 4 (iii) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी अवैधता की प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु हो जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया हो।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट को संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देना।

[अधिसूचना सं. 144/2007/फा. सं. 178/27/2007-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1026.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period begin on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing an Industrial Park of Industrial Area Anoopgarh, Phase-II, District, Sriganganagar, Rajasthan-335 002;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/144/2005-IP&ID dated 26-10-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-1A of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an industrial park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited
- (ii) Proposed location : Industrial Area Anoopgarh, Phase-II, District-Sriganganagar, Rajasthan-335 002.
- (iii) Area of Industrial Park : 33.75 Acres
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code

NIC Code					Description
S. No.	Section	Division	Group	Class	
A	2&3	—	—	—	Manufacturing

(v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use : 73.90%

(vi) Percentage of allocable area earmarked for commercial use	:	4.93%
(vii) Minimum number of industrial units	:	42 Units
(viii) Total investments proposed (Amount in Rupees)	:	193.76 lakhs
(ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees)	:	Nil
(x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees)	:	139.76 lakhs
(xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park	:	31-03-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty percent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80IA of the Income tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the Industrial park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 144/2007/F. No. 178/27/2007-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1027.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उप धारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193(अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005 में है, इंडस्ट्रियल एरिया, बिदासर, चुरू राजस्थान में एक औद्योगिक पार्क का विकास कर रहा है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 26-07-2006 के पत्र सं. 15/196/2005-आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किया है;

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुसूचित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा औद्योगिक पार्क गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
- (ii) प्रस्तावित स्थान : इंडस्ट्रियल एरिया, बिदासर, चुरू, राजस्थान
- (iii) औद्योगिक पार्क का कुल क्षेत्रफल : 83.40 एकड़
- (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप					
एन आई सी संहिता					विवरण
क्रम सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी	
क	2 एवं 3	--	--	--	विनिर्माण

- (v) औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत : 87%
- (vi) वाणिज्य उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत : 8%
- (vii) औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या : 24 यूनिटें
- (viii) प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में) : 1,83,21,000
- (ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में) : शून्य
- (x) अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में) : 1,72,40,000
- (xi) औद्योगिक पार्क के अरंभ होने की तिथि : 31-03-2006

2. किसी औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरों, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो निर्धारणीय हैं एवं वाणिज्यिक दृष्टि से उल्लब्ध कराई जाती हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी औद्योगिक पार्क के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50 से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा उस समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण के द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश भी शामिल है, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के औद्योगिक पार्क में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त औद्योगिक पार्क के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी अवैधता की प्रतिक्रिया के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि :

(i) आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।

(ii) यह उक्त औद्योगिक पार्क की अवस्थिति हेतु हो जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया है।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) औद्योगिक पार्क का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपर्युक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार की प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है। यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगाना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, औद्योगिक पार्क के अनुमोदन को अवैध बना देगा।

[अधिसूचना सं. 145/2007/फा. सं. 178/137/2006-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1027.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for Industrial Park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing an Industrial Park at Industrial Area, Bidasar, Churu, Rajasthan;

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park *vide* Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/196/2005-IP&ID dated 26-7-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an Industrial Park by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking : Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited
- (ii) Proposed location : Industrial Area, Bidasar, Churu, Rajasthan
- (iii) Area of Industrial Park : 83.40 Acres
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code					
	NIC Code				Description
S. No.	Section	Division	Group	Class	
A	2 & 3	—	—	—	Manufacturing

- (v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use : 87%
- (vi) Percentage of allocable area earmarked for Commercial use : 8%
- (vii) Minimum number of Industrial Units : 24 Units
- (viii) Total investments proposed (Amount in Rupees) : 1,83,21,000
- (ix) Investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees) : Nil
- (x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for Industrial use (Amount in Rupees) : 1,72,40,000
- (xi) Proposed date of commencement of the Industrial Park : 31-03-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more State or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or Non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Industrial Park.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Industrial Park; during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80 IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Industrial Park is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80 IA of the Income-tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the Industrial Park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the industrial park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 145/2007/F.No. 178/137/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 1028.—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (यहां आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये संख्या का.आ. 193 (अ) दिनांक 30 मार्च, 1999 के जरिए तथा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू होकर तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए संख्या का.आ. 354 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के जरिए भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाओं द्वारा औद्योगिक पार्क की योजना निर्मित और अधिसूचित की है;

और जबकि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005 में है, इंडस्ट्रियल एरिया, चंद्रावती ग्रोथ सेन्टर, झालावाड, राजस्थान-326001 में एक ग्रोथ सेन्टर का विकास कर रहा है;

और जबकि केन्द्र सरकार ने इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के दिनांक 11-05-2006 के पत्र सं. 15/104/2005 आई पी एंड आई डी के अन्तर्गत उक्त ग्रोथ सेन्टर को अनुमोदित किया है;

अब इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 80 झ क की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनार्थ औद्योगिक पार्क के रूप में मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा विकसित तथा अनुरक्षित एवं प्रचालित किए जा रहे उक्त उपक्रम को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

शर्तें जिन पर भारत सरकार ने मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा ग्रोथ सेन्टर गठित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम | : राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| (ii) प्रस्तावित स्थान | : इंडस्ट्रियल एरिया चंद्रावती ग्रोथ सेन्टर, झालावाड, राजस्थान-326001 |
| (iii) ग्रोथ सेन्टर का कुल क्षेत्रफल | : 438.00 एकड़ |

(iv) प्रस्तावित कार्यकलाप

एन आई सी संहिता के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप

एन आई सी संहिता		विवरण
क्रम सं. अनुभाग	प्रभाग	समूह
क	2 एवं 3	विनिर्माण
		श्रेणी
(v)	औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित आबंटनीय क्षेत्र का प्रतिशत	: 77.50%
(vi)	वाणिज्य उपयोग के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत	: 3.30%
(vii)	औद्योगिक यूनिटों की न्यूनतम संख्या	: 148 यूनिटें
(viii)	प्रस्तावित कुल निवेश (राशि रुपए में)	: 1816.70 लाख
(ix)	औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (राशि रुपए में)	: शून्य
(x)	अवसंरचनात्मक विकास पर निवेश जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश भी शामिल है (राशि रुपए में)	: 1744.14 लाख
(xi)	ग्रोथ सेन्टर के आरंभ होने की तिथि	: 31-03-2006

2. किसी ग्रोथ सेन्टर में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50% से कम नहीं होगा। ऐसे औद्योगिक पार्क जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थल प्रदान करता है, के मामले में औद्योगिक स्थल के निर्माण कार्य की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम खर्च कुल परियोजना लागत के 60% से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़क (सम्पर्क सड़क सहित), जलापूर्ति तथा सीवरज, दूषित जल शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, वातानुकूलन तथा ऐसी अन्य सुविधाएं जो औद्योगिक कार्यकलाप हेतु सामान्य उपयोग के लिए हैं जो निर्धारणीय हैं एवं वाणिज्यिक दृष्टि से उलब्ध कराई जाती हैं।

4. दिनांक 1 अप्रैल, 2002 की का.आ. 354(अ) के पैराग्राफ 6 के उप पैराग्राफ (ख) में निर्दिष्ट तालिका के कालम (2) में उल्लिखित कोई भी एकल इकाई किसी ग्रोथ सेन्टर के लिए नियत औद्योगिक क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा धारित नहीं करेगी। इस प्रयोजनार्थ किसी इकाई का आशय एक या एक से अधिक राज्य अथवा केन्द्रीय कर कानून के प्रयोजन के लिए किसी अलग तथा भिन्न कम्पनी से है।

5. आवश्यक अनुमोदनों जिनमें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा यथा समय प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अथवा अनिवासी भारतीय निवेश भी शामिल है, को प्रवृत्त नीति तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. इस अधिसूचना के पैरा 1 (vii) में विनिर्दिष्ट संख्या में इकाइयों के ग्रोथ सेन्टर में अवस्थित होने के उपरान्त ही इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

7. मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर उस अवधि के दौरान ग्रोथ सेन्टर का प्रचालन जारी रखेगा जिस अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप धारा (4) के खंड (iii) के अन्तर्गत लाभ लिए जाने हैं।

8. यदि उक्त ग्रोथ सेन्टर के आरंभ होने में इस अधिसूचना के पैरा 1 (xi) में निर्दिष्ट तिथि से एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब होगा तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप धारा 4 (iii) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 के अन्तर्गत नया अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

9. यह अनुमोदन अवैध रहेगा और मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर ऐसी किसी अवैधता की प्रतिक्रिया लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा, यदि :

- आवेदन पत्र जिसके आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, में गलत सूचना/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा कतिपय तथ्यपरक सूचना न दी गई हो।
- यह उक्त ग्रोथ सेन्टर की अवस्थिति हेतु हो जिसके लिए अनुमोदन किसी अन्य उपक्रम के नाम में पहले ही प्रदान किया गया हो।

10. यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर (अर्थात् अन्तरणकर्ता उपक्रम) ग्रोथ सेन्टर का प्रचालन और अनुरक्षण किसी दूसरे उपक्रम (अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को हस्तांतरित करेगा तो अंतरणकर्ता और अंतरिती उपयुक्त

हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती उपक्रम के बीच निष्पादित करार को प्रति के साथ औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 की उद्यमशीलता सहायता यूनिट को संयुक्त रूप से सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन शर्तों का अनुपालन उस अवधि के दौरान किया जाना चाहिए जिसमें इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हैं। केन्द्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है। यदि मैसर्स राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहता है।

12. केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रोजेक्ट प्लान में किया गया कोई भी संशोधन अथवा भविष्य में पता लगना अथवा किसी ठोस तथ्य का उद्घाटन करने में आवेदक का असफल रहना, ग्रोथ सेन्टर के अनुमोदन को अवैध बना देगा।

[अधिसूचना सं. 146/2007/फा. सं. 178/79/2006-आ.क.नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

New Delhi, the 30th March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 1028.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for Industrial Park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 193(E), dated the 30th March, 1999, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2002 and vide number S.O. 354(E) dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, having registered office at Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 is developing a Growth Centre at Industrial Area Chandrawati Growth Centre, Jhalawar, Rajasthan-326 001;

And whereas the Central Government has approved the said Growth Centre vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/104/2005-IP&ID dated 11-5-2006 subject to the terms and conditions mentioned in the annexure to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii).

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of a Groth Centre by M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur.

1. (i) Name of the Industrial Undertaking, : Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited
- (ii) Proposed location : Industrial Area, Chandrawati Growth Centre, Jhalawar, Rajasthan-326 001
- (iii) Area of Growth Centre : 438.00 Acres
- (iv) Proposed activities :

Nature of Industrial activity with NIC code

NIC Code					Description
S.No.	Section	Division	Group	Class	
A	2 & 3	—	—	—	Manufacturing

(v) Percentage of allocable area earmarked for Industrial use : 77.50%

(vi) Percentage of allocable area earmarked for Commercial use : 3.30%

(vii) Minimum number of Industrial Units	:	148 Units
(viii) Total investments proposed (Amount in Rupees)	:	1816.70 lakhs
(ix) Investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees)	:	Nil
(x) Investment on Infrastructure Development including investment on built up space for industrial use (Amount in Rupees)	:	1744.14 lakhs/-
(xi) Proposed date of commencement of the Growth Centre	:	31-03-2006

2. The minimum investment on infrastructure development in Growth Centre shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of a Growth Centre which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the allocable industrial area of a Growth Centre. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more State or Central Tax Laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or Non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the Growth Centre.

7. M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall continue to operate the Growth Centre during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the commencement of the Growth Centre is delayed by more than one year from the date indicated in Para 1 (xi) of this notification, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2002, for availing benefits under sub-section 4 (iii) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

- (i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.
- (ii) it is for the location of the Growth Centre for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, transfers the operation and maintenance of the Growth Centre (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-11 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited, Jaipur, fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future, or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the Growth Centre.

[Notification No. 146/2007/F. No. 178/79/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

सेलम, 22 मार्च, 2007

संख्या 2/2007-सीमा शुल्क (एन.टी.)

का.आ. 1029.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152 के खंड (क) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. 33/94-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 1-7-1994 के जरिए अधोहस्ताक्षरी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एस. रमेश, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, सेलम पत्रद्वारा सर्वे सं. 131/2जी2, मोलपालयम गांव, रासीपुरम तहसील, नामक्कल जिला, तमिलनाडु को वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, एम ई पी जेड, चेन्नई, अनुमोदितानुसार शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के प्रयोजन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अनुसार भांडागार केन्द्र घोषित करता हूँ।

[फा. सं. सी. VIII/40/02/2007-सी. शु. नीति]

एस रमेश, आयुक्त

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

Salem, the 22nd March, 2007

No. 2/2007-CUSTOMS (NT)

S.O. 1029.—In exercise of the powers delegated to the undersigned, vide Notification No. 33/94-CUS. (NT) dated 1st July, 1994 issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under Clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962 I. S. Ramesh, Commissioner of Customs and Central Excise, Salem, hereby declare Survey No. 131/2G2, Molapalayam Village of Rasipuram Taluk in Namakkal District of Tamil Nadu State, to be a warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962, for the purpose of setting up of 100% Export Oriented Unit as approved by the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Madras Export Processing Zone, Chennai.

[F. No. C. No. VIII/40/02/2007-CUS. POL.]

S. RAMESH, Commissioner

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2007

का.आ. 1030.—केन्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वतंत्रतापूर्व संस्थान प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली को, जिनके 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है।

[फा. सं. 11028/1/2005-(रा.भा.)]

नीलाम्बर पाण्डेय, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 3rd April, 2007

S.O. 1030.—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rule 1976, the Central Government hereby notifies Technology Development Board, New Delhi an autonomous institution under the Administrative Control of Ministry of Science and Technology. 80% staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[F.No. 11028/1/2005-(OL)]

NILAMBAR PANDEY, Jt. Director

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1031.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक में संशोधन किया गया है :-

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और वर्ष	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आई एस 2500 (भाग-1) : 2000/आई एस ओ 2859-1 : 1999 राशि के अनुसार निरीक्षण के लिए स्वीकार्य गुणता स्तर (ए क्यू एल) द्वारा सूचित गुण-दोष मालूम करने के लिए नमूने लेने की योजना (तीसरा पुनरीक्षण)	पहला संशोधन, 2006	दिसम्बर, 2006

इस संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एम एस डी/जी-8]

नरेश कुमार ग्रोवर, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (प्रबन्ध एवं तंत्र)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1031. — In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standards, particulars of which is given in the Schedule hereto annexed has been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Year of the Indian Standards	No. and year of the Amendment	Date from which the Amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IS 2500 (Part 1) : 2000/ISO 2859-1: 1999 Sampling Procedure for Inspection by attributes Part 1 Sampling schemes indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for Lot-by-lot Inspection (Third revision)	Amendment No. 1, 2006	December, 2006

Copy of the Amendment are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and its Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai, and also Branch Offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram.

[Ref : MSD/G-8]

N. K. GROVER, Scientist 'F' & Head (MSD)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1032.— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आई एस 14580 (भाग-2) : 2000 परियोजना प्रबन्ध के लिए नेटवर्क विश्लेषण का प्रयोग भाग-2 रेखीय तकनीक का प्रयोग	—	अक्तूबर, 2006
2	आई एस 14581 : 2006 एक संगठन में सुझाव योजना के निर्धारण और प्रचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत (पहला पुनरीक्षण)	—	दिसम्बर, 2006

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एम एस डी/जी-8]

नरेश कुमार ग्रोवर, वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (प्रबन्ध एवं तंत्र)

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1032. — In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Year of the Indian Standards Established & Title-	No. and year of Indian Standards, if any Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 1458 (Part 2) : 2006 Use of Network Analysis for Project Management Part 2 Use of Graphic Techniques	—	October, 2006
2.	IS 14581 : 2006 Guidelines for Formulation and Operation of a Suggestion Scheme in an Organization (First revision)	—	December, 2006

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai, and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : MSD/G-8]

N. K. GROVER, Scientist 'F' & Head (MSD)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

का.आ. 1033.— भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के नियम (4) के उप-नियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेन्सों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं वे स्वीकृत कर दिये गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस सं.	चालू तिथि	लाइसेंसधारी का नाम व पता	भारतीय मानक का शीर्षक व संबंधित भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फरवरी 2007				
1.	8792507	19-2-2007	मैसर्स भिवाडी सिलिण्डर्स प्रा. लि. ई-925, 1200 एवं 1201, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी-301 019 जिला अलवर	15100 : 2001 मालफंक्शन वाल्व एसेम्बली फॉर परमानेन्टली फिक्स्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कन्टेनर्स फॉर ऑटोमोटिव यूज
2.	8792810	15-2-2007	मैसर्स उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., श्री गंगानगर रोड, बीकानेर-334 002	13334 (भाग-1) : 1998 स्किमड मिल्क पाउडर (स्टैंडर्ड ग्रेड)
3.	8788718	8-2-2007	मैसर्स स्वास्तिका कोनकैब (इण्डिया) प्रा. लि., प्लॉट नं. ए-211(ए), औद्योगिक क्षेत्र बगरू विस्तार, बगरू-302 007, जिला- जयपुर	398 (भाग 4) : 1994 ए ए ए सी
4.	8785409	24-1-2007	मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड, ए-130(ई), रोड नं. 9, डी, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302 013	14333 : 1996 एचडीपीई पाइप्स फॉर सिवरेज
5.	8788314	7-2-2007	मैसर्स पॉवर केबल इण्डस्ट्रीज, जी-1/801, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302 022	1554 (भाग 1) : 1988 पीवीसी इन्सुलेटेड (एचडी) केबल्स
6.	8787413	5-2-2007	मैसर्स खाटू प्लास्ट लिमिटेड, जी-10, 11 एवं 12, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फुलेरा जिला-जयपुर-303 338	12701 : 1996 आरएमपी वॉटर स्टोरेज टैंक्स
7.	8788415	5-2-2007	मैसर्स एग्रोकिंग पेस्टीसाइड्स प्रा. लि., ई-38, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू जिला, जयपुर-303 007	12016 : 1987 साइपरमेथरिन 10% ई सी
8.	8788516	5-2-2007	मैसर्स एग्रोकिंग पेस्टीसाइड्स प्रा. लि., ई-38, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू जिला, जयपुर-303 007	2567 : 1978 मैलाथियान 50% ई सी
9.	8793913	23-2-2007	मैसर्स एम. बी. एण्ड सन्स ज्वैलर्स, पुराना दुजोद गेट के पास, नया शहर, सीकर-332 001	1417 : 1999 हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वैलरी
10.	8793812	23-2-2007	मैसर्स बी. एल. हसरिया ज्वैलर्स, पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, पुराना बाजार, हुनमानगढ़-335 513	1417 : 1999 हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वैलरी
11.	8791707	15-2-2007	मैसर्स एम. बी. ज्वैलर्स, पुराना दुजोद गेट, नया शहर, सीकर-332 001	1417 : 1999 हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वैलरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	8793711	21-2-2007	मैसर्स श्री अग्रसेन इण्डस्ट्रीज, ई-293 (ए), रोड नं. 14, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302 013	398 (भाग 2) : 1976 ए सी एस आर
13.	8784811	25-1-2007	मैसर्स किनु बाबा ज्वैलरी प्रा. लि., के-टावर, 41, महावीर मार्ग, सी स्क्रीम, जयपुर	1417 : 1999 हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वैलरी
14.	8791303	14-2-2007	मैसर्स श्री बेवरेजेस, ई-9, औद्योगिक क्षेत्र, परबतपुर माखपुरा विस्तार, अजमेर-305 002	14543 : 2004 पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर
15.	8791808	15-2-2007	मैसर्स अनमोल जैम्स एण्ड ज्वैलरी, 14-15, सिन्धी बाजार भामाशक्त मार्ग, जयपुर-313 001	1417 : 1999 हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वैलरी

[सं. : सी एम डी/13 : 11]

एस. के. चौधरी, उप-महानिदेशक (मुहर)

New Delhi, the 28th March, 2007

S.O. 1033.— In pursuance of Sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification Regulation, 1988, the Bureau of Indian Standards hereby notifies the grant of licence particulars of which are given in the following schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L-)	Operative Date	Name and Address of the Licensee	Article/Process covered by the licences and the relevant IS : Designation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Feb 2007				
1.	8792507	19-2-2007	M/s. Bhiwadi Cylinders Pvt. Ltd., E-925, 1200 and 1201, Industrial Area, Bhiwadi-301 019 Distt. Alwar (Rajasthan)	15100:2001 Malfunction Valve Assembly for Permanently Fixed Liquefied Petroleum Gas (LPG) Containers for Automotive use.
2.	8792810	15-2-2007	M/s. Uttari Rajasthan Sahakari Dugdh Utpadak Sangh Ltd., Sri Ganganagar Road, Bikaner-334 002 (Rajasthan)	13334 (Part 1) : 1998 Skimmed Milk Powder (Standard Grade)
3.	8788718	8-2-2007	M/s. Swastika Concab (India), Private Limited, Plot No. A-211 (A), Industrial Area, Bagru Extension, Bagru Distt. Jaipur-302 007, (Rajasthan)	398 (Part 4) : 1994 AAAC
4.	8785409	24-1-2007	M/s. Tijaria Polypipes Limited, A-130(E), Road, No. 9D, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302 013 (Rajasthan)	14333 : 1996 HDPE Pipes for Sewerage
5.	8788314	7-2-2007	M/s. Power Cable Industries, G-1/801, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302 022 (Rajasthan)	1554 (Part 1) : 1988 PVC Insulated (HD) Cables
6.	8787413	5-2-2007	M/s. Khatu Plast Ltd., G-10, 11 and 12, Riico Indl. Area, Phulera, Distt. Jaipur-305 338 (Rajasthan)	12701 : 1996 RMP Water Storage Tanks

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	8788415	5-2-2007	M/s. Agroking Pesticides Pvt. Ltd., E-38, RIICO Industrial Area, Bagru, Distt. Jaipur-303 007 (Rajasthan)	12016:1987 Cypermethrin 10% EC
8.	8788516	5-2-2007	M/s. Agroking Pesticides Pvt. Ltd., E-38, RIICO Industrial Area, Bagru, Distt. Jaipur-303 007 (Rajasthan)	2567:1978 Malathion 50% EC
9.	8793913	23-2-2007	M/s. M. B. & Sons Jewellers, Near Old Dujod Gate, Naya Shahar, Sikar-332 001 (Rajasthan)	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery
10.	8793812	23-2-2007	M/s. M. L. Hassaria Jewellers, Near Old Post Office, Purana Bazar, Hanumangarh-335 513 (Rajasthan)	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery
11.	8791707	15-2-2007	M/s. M. B. Jewellers, Old Dujod Gate, Naya Shahar, Sikar-332 001 (Rajasthan)	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery
12.	8793711	21-2-2007	M/s. Shree Agrasen Industries, E-293 (A), Road No. 14, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302 013 (Rajasthan)	398 (Part): 1976 ACSR
13.	8784811	25-1-2007	M/s. Kinu Baba Jewellery Pvt. Ltd., K-Tower, 41, Mahaveer Marg, C-Scheme, Jaipur, (Rajasthan)	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery
14.	8791303	14-2-2007	M/s. Shree Beverages, E 9 Industrial Area, Parbatpura, Makhupura Extension, Ajmer-305 002 (Rajasthan)	14543:2004 Packaged Drinking Water
15.	8791808	15-2-2007	M/s. Anmol Gems & Jewellery, 14-15 Sindhi Bazar, Bhamashah Marg, Udaipur-313001 (Rajasthan)	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery

[No. CMD/13:11]

S. K. CHAUDHURI, Dy. Director General (Marks)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

का.आ. 1034.- भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के नियम 5 के उप-नियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेन्सों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से समाप्त कर दिया गया है :-

अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेन्स नं.	लाइसेन्सधारी का नाम	शीर्षक से संबंधित भारतीय मानक	समाप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5
दिसम्बर 2006				
1.	8643183	मै. ग्रीनप्लाइ इण्डस्ट्रीज लि., ई-176, से 179, फेस-II, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, बेहरोड जिला, अलवर-301701	14587	8-12-2006

[संदर्भ : सीएमडी-1/13:13]

एस. के. चौधरी, उप महानिदेशक (मुहर)

New Delhi, the 28th March, 2007

S. O. 1034.—In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licence(s) particulars of which is/are given below has/have been cancelled with effect from the date indicated.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L-)	Name and Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence cancelled	Date of Cancellation
1	2	3	4	5
December 2006				
1.	8643183	M/s. Greenply Industries Ltd., E-176 to 179, Phase-II, RIICO Industrial Area Behror Distt. Alwar-301701	14587 : 1998 Prelaminates Medium Density Fibre Board	8-12-2006

[Ref. : CMD-1/13:13]

S. K. CHAUDURI, Dy. Director General (Marks)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

का.आ. 1035.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 4 के उपविनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि वे लाइसेंस जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं उनके आगे दर्शाए गई तिथि से जारी किए गए हैं :-

अनुसूची

अनु.क्र.	लाइसेंस संख्या	वैधता	पार्टी का नाम और पता	उत्पादन	भा.भा./भाग/ विभाग/वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	7652886	14/09/2007	केंडीपी एन्टरप्राइजेस, 21/22, निलकंठ इण्डस्ट्रियल इस्टेट संख्या 1, साईबाबा मंदिर के पास, सर्वे संख्या-59/4, सातीवली गाँव, चसई (पूर्व), जिला थाणे-401208	भारतीय राष्ट्रीय झंडा	भामा : 1 : 1968
2.	7657290	26/09/2007	विवर अक्वा एवरफलो गाला संख्या 1 और 2, तलमंजिल, 84 विजयकर वाडी, एस. वि. रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400 064	पैकेजबंद पेयजल	भामा : 14543 : 2004
3.	7658292	27/09/2007	सेन्जेन्टा क्रॉप प्रोटेक्शन प्राईवेट लि. सान्ता मोनिका वर्क्स, कोरलिम. इल्हास, उत्तर गोवा, गोवा-403 110	पेस्टिसाईड	भामा : 14510 : 1997
4.	7659904	04/10/2007	रेक्मी होल्डींग ए/9, चांदिवली, इण्डस्ट्रियल एरिया डियायसी इंडिया लिमिटेड के पीछे, विजय फायर के आगे, चांदिवली फार्म, साकी नाका. मुंबई-400072	पैकेजबंद पेयजल	भामा : 14543 : 2004
5.	7664691	22/01/2007	नेशनल बेनी प्रोडक्ट्स प्लांट संख्या 19, आटगांव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, आटगांव रेलवे स्टेशन के सामने, आटगांव, शहापुर, जिला थाणे-421 601	प्लास्टिक फीडिंग बोतले	भामा : 14625 : 1999

1	2	3	4	5	6
6.	7675090	22/11/2007	बॉम्बे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, कल्पतरू हेरिटेज, 5वा माला, नानिक मोटवाणी लेन, 129, एम. जी. रोड, मुंबई-400 001	पेस्टिसाइड	भामा : 1051 : 1980
7.	7685905	12/12/2007	संकल्प वाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, सीयु-31, विचुर वाइन पार्क, निफाड, नासिक	टेबल वाईन्स	भामा : 7058 : 2005

[सं. सीएमडी/ 13 : 11]

एस.के. चौधरी, उप महानिदेशक (मुहर)

New Delhi, the 29th March, 2007

S. O. 1035.—In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following schedule :

Sl. No.	Licence No.	Validity Date	Name and Address (factory) of the Party	Product	IS No./Part/ Sec. Year
1.	7652886	14/09/2007	KDP Enterprises, 21/22 Neelkanth Indl. Estate No. 1, Near Sai Baba Temple, Sl. No. 59/4, Sativali Village, Vasai (E), Distt. Thane-401 208	National Flag of India (Cotton Khadi)	IS 1 : 1968
2.	7657290	26/09/2007	Weaver Aqua Everflow Gala No. 1 & 2, Ground Floor, 84 Vijaykar Wadi, S. V. Road, Malad (W), Mumbai-400 064	Packaged Drinking Water (Other than packaged Natural Mineral Water)	IS 14543 : 2004
3.	7658292	27/09/2007	Syngenta Crop Protection Pvt. Ltd., Santa Monica Works, Corlim, Ilhas North Goa, Goa-403 110	Lambda-cyhalothrin WP	IS 14510 : 1997
4.	7659904	04/10/2007	Rekmi Holdings A/9 Chandivali Indl. Area Behind Dic India Ltd. Next to Vijay Fire, Chandivali Farm, Saki Naka, Mumbai-400 072	Packaged Drinking Water (Other than packaged Natural Mineral Water)	IS 14543 : 2004
5.	7664691	22/10/2007	National Babay Products Plot No. 19, Atgaon Indl Complex, Opp Atgaon Rly Station, Village Atgaon, Shahpur, Distt. Thane-421 601	Plastic Feeding Bottles	IS 14625 : 1999
6.	7675090	22/11/2007	Bombay Chemicals Pvt. Ltd., Kalpataru Heritage 5th Floor, Nanik Motwane Lane 129 M.G. Road, Mumbai-400001	Pyrethrum Extracts	IS 1051 : 1980
7.	7685905	12/12/2007	Sankalp Winery Pvt. Ltd. Cu-31, Vinchur Wine Park Niphad, Nashik	Table Wines	IS 7058 : 2005

[No. CMD/13 : 11]

S. K. CHAUDHURI, Dy. Director General (Marks)

नई दिल्ली, 29 मार्च 2007

का.आ. 1036.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम संख्या	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हों, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	आईएस 2062 : 2006-तप्त बेल्लित अल्प, मध्यम एवं उच्च तन्यता के संरचना इस्पात (छठा पुनरीक्षण)	आईएस 2062 : 1999	1 जून 2007
----	--	------------------	------------

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तपुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ. एमटीडी 4/टी-74]

Dr. (Mr.) SNEH BHATLA, वैज्ञा.-एफ. एवं प्रमुख (एमटीडी)

New Delhi, the 29th March, 2007

S. O. 1036.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards Established	No. and year of Indian Standards, if any, superseded by the New Indian Standard	Date of Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 2062 : 2006 Hot rolled Low, Medium and High tensile Structural Steel (Sixth Revision)	IS 2062 : 1999	1 June 2007

Copy of this Standards is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram.

[Ref. MTD 4/T-74]

Dr. (Mr.) SNEH BHATLA, Scientist-F & Head (Met Engg)

नई दिल्ली, 29 मार्च 2007

का. आ. 1037.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 15391 : 2003-अतप्त बेल्लित गैर दिशात्मक विद्युत इस्पात की चद्दर एवं भत्ती अर्ध प्रकुमित प्ररूप विशिष्ट	संशोधन संख्या 1 जनवरी 2006	6-2-2006

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ एमटीडी 4/टी-212]

डॉ. (श्रीमति) स्नेह भाटला, वैज्ञा.-एफ. एवं प्रमुख (एमटीडी)

New Delhi, the 29th March, 2007

S. O. 1037.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 15391 : 2003 Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip—Semi-processed type—Specification	Amendment No. 1, January, 2006	6-2-2006

Copy of this Standards is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram.

[Ref. MTD/4T-212]

DR. (MRS.) SNEH BHATLA, Scientist-F & Head (MTD)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

का.आ. 1038.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 2830 : 1992 सामान्य संरचना इस्पात में पुनर्वेल्लन के लिए कार्बन ढलवाँ इस्पात बिलेट इंगट, बिलेट, ब्लूम और स्लैब की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 2, दिसम्बर 2005	13-2-2006

इस भारतीय मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ एमटीडी 4/टी-94]

डॉ. (श्रीमति) स्नेह भाटला, वैज्ञा.-एफ. एवं प्रमुख (एमटीडी)

New Delhi, the 29th March, 2007

S. O. 1038.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 2830 : 1992 Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes—Specification	Amendment No. 2, December 2005	13-2-2006

Copy of these Standards is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram.

[Ref. MTD/4T-94]

DR. (MRS.) SNEH BHATLA, Scientist-F & Head (MTD)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

का.आ. 1039.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानकों में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 6240 : 1999 तप्त बेलित इस्पात प्लेट (6 मिमी तक), चद्दर और पत्ती अल्प दाब द्रवणीय गैस सिलिंडरों के निर्माण के लिए विशिष्ट (तीसरा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 3, जनवरी 2006	28-2-2006

इस भारतीय मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ एमटीडी 4/टी-131]

डॉ. (श्रीमति) स्नेह भाटला, वैज्ञ.-एफ. एवं प्रमुख (एमटीडी)

New Delhi, the 29th March, 2007

S. O. 1039.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 6240 : 1999 Hot rolled steel plate (upto 6 mm), sheet and strip for the manufacture of low pressure liquefiable gas cylinders—specification (third revision)	Amendment No. 3, January 2006	28-2-2006

Copy of these Standards is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. MTD/4T-131]

DR. (MRS.) SNEH BHATLA, Scientist-F & Head (MTD)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

का.आ. 1040.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 277 : 2003 जस्तीकृत इस्पात की चद्दरें सादी तथा नालीदार—विशिष्ट (छठा पुनरीक्षण)	संशोधन संख्या 1, जून 2005	29-7-2005

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ एमटीडी 4/टी-22]

डॉ. (श्रीमति) स्नेह भाटला, वैज्ञ.-एफ. एवं प्रमुख (एमटीडी)

New Delhi, the 29th March, 2007

S. O. 1040.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendments to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 277 : 2003 Galvanized steel sheets (Plain and corrugated)—specification (sixth revision)	Amendment No. 1, June 2005	29-7-2005

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. MTD/4T-22]

DR. (MRS.) SNEH BHATLA, Scientist-F & Head (MTD)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2007

का.आ. 1041.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5509 : 2000	संख्या 2, सितम्बर 2006	19 मार्च, 2007

इस संशोधन की प्रति भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ सीईडी/राजपत्र]

पी. के. सैनी, वैज्ञा.-एफ. एवं प्रमुख (सिविल इंजीनियरी)

New Delhi, the 29th March, 2007

S. O. 1041.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standard, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	5509 : 2000	No. 2, September 2006	19 March, 2007

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. CED/Gazette]

A. K. SAINI, Scientist-F & Head (Civil Engg.)

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

का.आ. 1042.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक (कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 7093 (भाग 3) : 1993 की संशोधन संख्या 2	2, फरवरी 2007	01-05-2007

इस भारतीय संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ इटी 09/टी-57]

पी. के. मुखर्जी, वैज्ञा.-एफ. एवं प्रमुख (तकनीकी)

New Delhi, the 2nd April, 2007

S. O. 1042.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 7098 (Part 3) : 1993 specification for Cross-linked Polyethylene Insulated Thermoplastic Sheathed Cables Part 3 For working voltages from 66 kV up to and including 220 kV	2nd February, 2007	01-05-2007

Copy of this Amendment is available with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref. ET 09/T-57]

P. K. MUKHERJEE, Scientist-F & Head (Electro-Technical)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2007

का.आ. 1043.— भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि वे लाइसेंस जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं उनके आगे दर्शाए गई तिथि से जारी किए गए हैं:

अनुसूची

क्र.सं.	लाइसेंस संख्या	वैधता	पार्टी का नाम और पता	उत्पादन	भा.मा./भाग/विभाग/वर्ष
1.	7692191	30-01-2008	प्रसाद एन्टरप्राइजिस व्हि-122, एमआईडीसी अजंता रोड, जलगाँव-425003	पैकेजबंद पेयजल	भामा : 14543 : 2004
2.	7680992	01-01-2008	के. एम. बेक्करेजेस प्राईवेट लिमिटेड एस. आर. संख्या-94/95/99/96/103, पोस्ट-सासणे, तालुका-मुरबाड, जिला-थाणे, महाराष्ट्र	पैकेजबंद पेयजल	भामा : 14543 : 2004
3.	7697609	21-01-2008	पेंपीलॉन बेक्करेजेस बी-305, कम्लैक्स प्लाजा, ऑफ लिंक रोड, माईड स्पेस, 5-डी होटल के बाजू में, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400064	पैकेजबंद पेयजल	भामा : 14543 : 2004

[संदर्भ सी. एम. डी/13:11]

एस. के. चौधरी, उप महानिदेशक

New Delhi, the 9 April, 2007

S.O. 1043.— In pursuance of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following schedule :

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Validity Date	Name and Address (factory) of the Party	Product	IS No./Part/ Sec Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	7692191	30-01-2008	Prasad Enterprises V-122, MIDC, Ajanta Road, Jalgaon, Maharashtra—425003	Packaged Drinking water (other than Packaged Natural Mineral Water) Specification	IS 14543 : 2004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	7680992	01-01-2008	K.M. Beverages Pvt. Ltd. Sr. No. 94/95/99/96/103 At & Post Sasne Tal. Murba, Dist Thane, Maharashtra	Packaged Drinking water (other than Packaged Natural Mineral Water) Specification	IS 14543 : 2004
3.	7697609	21-01-2008	Pappillon Beverages B-305, Kemps Plaza, off link Road, Mind Space, Near Hotel, S-D, Malad (W), Mumbai, Maharashtra—400064	Packaged Drinking water (other than Packaged Natural Mineral Water) Specification	IS 14543 : 2004

[Ref. CMD/13 : 11]

S. K. CHAUDHURI, Dy. Director General

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2007

का.आ. 1044.—संख्या केन्द्रीय प्रमाणन विभाग/13 : 11 भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन विनियम, 1988 के विनियम 4 के उप विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि वे लाइसेंस जिनके विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं उनके आगे दर्शाए गई तिथि से जारी किए गए हैं:

अनुसूची

जनवरी 2007 में स्वीकृत किये गये अनुज्ञप्ति

क्रम सं.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसी का नाम तथा पता	उत्पादन का नाम तथा आई एस	अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की तिथि
1.	7691189	मैसर्स श्रेया एक्स-टैक लिमिटेड, 102, अश्वामेघ काम्पलैक्स, सयाजी विहार क्लब के सामने, राजमहल रोड	फ्लेमप्रुफ एनकलोसर आई एस 2148 : 2004	22-12-2006
2.	7691593	मैसर्स के झी गोल्ड गार्डन, 2, भदराज चैम्बर, स्वास्तिक चार रस्ता, सी जी रोड, अहमदाबाद-380 009	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकरण आई एस 1417 : 1999	02-01-07
3.	7691694	मैसर्स सोनी सुभाषचंद्र द्वारका दास ज्वैलर्स, हीरालाल भुवन, मोडसा, साबर कांटा-383315	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकरण आई एस 1417 : 1999	02-01-07
4.	7691795	मैसर्स सोनी नितिनकुमार भाईलालभाई तथा कंपनी, जी 47, जय श्यामसुंदर काम्पलैक्स, मोडसा, साबरकांटा-383315	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकरण आई एस 1417 : 1999	02-01-07
5.	7692393	मैसर्स राजरत्न ज्वैलर्स, जी एफ/2, सत्यम काम्पलैक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, मनीनगर, अहमदाबाद-380 008	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकरण आई एस 1417 : 1999	04-01-07
6.	7692494	मैसर्स प्रीती ज्वैलर्स, 4, अक्षरधाम एपार्टमेंट, अंबिका कृपा सोसाइटी के पास, रानिप, अहमदाबाद-382 480	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकरण आई एस 1417 : 1999	04-01-07
7.	7692801	मैसर्स चोकसी नरेंद्रकुमार, धनपतलाल, 209/2/23, 209/2/24, रतनसागर सोसाइटी के पास, न्यू मैटल, मेधानीनगर, अहमदाबाद-380 016	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकरण आई एस 1417 : 1999	05-01-07

क्रम. सं.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसी का नाम तथा पता	उत्पाद का नाम तथा आई एस	अनुज्ञाप्ति स्वीकृत करने की तिथि
8.	7692595	मैसर्स मंगलसूत्र ज्वैलर्स, सी 11, सायोना, सिटी शॉपिंग सेंटर, आर सी टैक्निकल रोड, धाटलोडिया अहमदाबाद-380061	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	04-01-07
9.	7692696	मैसर्स मंगलसूत्र ज्वैलर्स, सी 11, सायोना, सिटी शॉपिंग सेंटर, आर सी टैक्निकल रोड, धाटलोडिया अहमदाबाद 380061	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	04-01-07
10.	7692797	मैसर्स भीखालाल भोगीलाल पटेल तथा कंपनी, 3077, नगीना पोल के पास, रतनपोल, कालूपुर, अहमदाबाद-380 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	04-01-07
11.	7692902	मैसर्स भीखालाल भोगीलाल पटेल तथा कंपनी, 3077, नगीना पोल के पास, रतनपोल, कालूपुर, अहमदाबाद-380 001	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 2112 : 2003	05-01-07
12.	7694603	मैसर्स गुजरात कंटेनर्स लिमिटेड, 201/202, अल्कापुरी आरकडे, बी विंग, वैलकम होटल के सामने, आर सी दत्त रोड, वदोदरा-390 005	ड्रम, लार्ज फिक्सड एंडस पार्ट 1-ग्रेड ए ड्रम, 1783 (पार्ट 1) : 1993	04-01-07
13.	7694704	मैसर्स गुजरात कंटेनर्स लिमिटेड, 201/202, अल्कापुरी आरकडे, बी विंग, वैलकम होटल के सामने, आर सी दत्त रोड, वदोदरा-390 005	ड्रम, लार्ज फिक्सड एंडस पार्ट 1-ग्रेड बी ड्रम, 1783 (पार्ट 2) : 1983	04-01-07
14.	7696809	मैसर्स चिराग इंजीनियर्स, 43, 153, 154, आशीर्वाद इंडस्ट्रियल एस्टेट, फ्रूट मार्केट के सामने, नरोडा रोड, अहमदाबाद-380025	सबमर्सिबल पंपसेट 8034 : 2002	17-01-07
15.	7696708	मैसर्स परीक्षित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 706, सिल्वर ओक, महालक्ष्मी, पालडी, अहमदाबाद-380 007	इरीगेशन इक्वूपमेंट-रोटेटिंग स्पलिंगर पार्ट 1, 12232 (पार्ट 1) : 1996	10-01-07
16.	7696102	मैसर्स हरि ओम गोल्ड पैलेस, 3003, बैंक आफ बड़ोदा, दिल्ली चकला, पी ओ शाहपुर, अहमदाबाद-380 009	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	17-01-07
17.	7696203	मैसर्स मिलाप ज्वैलर्स, 102-103, सी बी देसाई चैम्बर्स, गुंजन सिनेमा के पास, कोपारली रोड, जी आई डी सी, वापी-396 195	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	17-01-07
18.	7696304	मैसर्स महालक्ष्मी ज्वैलर्स, 11, व्हाइट हाऊस, पैलेस रोड, गुरुनानक चौक, पालनपुर-385 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	17-01-07
19.	7696910	मैसर्स योगेशकुमार तथा ब्रदर्स, 3/304, अशोक स्तम्भ टावर बाजार, आनंद-388 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	19-01-07

सं. क्र.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसी का नाम तथा पता	उत्पाद का नाम तथा आई एस	अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की तिथि
20.	7697003	मैसर्स सोना मोहर, 13, व्हाइट हाऊस, पैलेस रोड, पालनपुर, गुजरात-385 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	19-01-07
21.	7697104	मैसर्स न्यू उमिया ज्वैलर्स, शॉप नंबर 3, मनाहरनगर सोसाइटी, पार्ट 1, कृष्णा विद्यालय के सामने, बापूनगर, अहमदाबाद-380 024	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	19-01-07
22.	7697205	मैसर्स न्यू उमिया ज्वैलर्स, शॉप नंबर 3, मनाहरनगर सोसाइटी, पार्ट 1, कृष्णा विद्यालय के सामने, बापूनगर, अहमदाबाद-380 024	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 2112 : 2003	19-01-07
23.	7697306	मैसर्स पुष्पम ज्वैलर्स, 974, सदर बाजार, डोसा, बंसकांटा-385535	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	19-01-07
24.	7697407	मैसर्स नवरंग ज्वैलर्स, 365/16, सरसपुर भित्त के सामने, सरसपुर, अहमदाबाद	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	19-01-07
25.	7698308	मैसर्स वी वी ज्वैलर्स, 28, रतनपोल, गांधी रोड, अहमदाबाद-380 009	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	23-01-07
26.	7698510	मैसर्स जावेरी बाधाजीभाई सुंदरजी भाई ज्वैलर्स, 5, गरडा कालेज शॉपिंग सेंटर, सयाजी रोड, नवसारी-396 445	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	23-01-07
27.	7698409	मैसर्स जावेरी, 24, शांतिनाथ शाह चैम्बर्स, न्याय मंदिर के सामने, डोसा, बंसकांटा-385535	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	23-01-07
28.	7699310	मैसर्स साई इंडस्ट्रीज, एल-104/13, 5, 6, तालजी मुलजी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के सामने, रोड नंबर 1, जी आई डी रोड, सारीगाम-396 115 बलसाद	फ्लेमप्रूफ एनकलॉसर आई एस 2148 : 2004	23-01-07
29.	7699916	मैसर्स जय अंबे ज्वैलर्स, जी-9, दयासागर अपार्टमेंट, दीक्षित स्ट्रीट, आनंद-388 001	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 2112 : 2003	24-01-07
30.	7699815	मैसर्स जय अंबे ज्वैलर्स, जी-9, दयासागर अपार्टमेंट, दीक्षित स्ट्रीट, आनंद-388 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	24-01-07
31.	7699714	मैसर्स ए बी ज्वैलर्स (सत्यमवाला) 3-4, लैंडमार्क, सयाजी लाईब्रेरी के पास, नवसारी-396 445	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	24-01-07
32.	7700366	मैसर्स अंबिका गोल्ड पैलेस, 1/17/36, धीवटा नाका, बाजार, गांधी रोड, पाटन-384265	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 2112 : 2003	24-01-07

सं. क्र.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसी का नाम तथा पता	उत्पाद का नाम तथा आई एस	अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की तिथि
33.	770265	मैसर्स ऑबिका गोल्ड पैलेस, 1/17/36, धीवटा नाका, बाजार, गांधी रोड, पाटन-384265	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	24-01-07
34.	7700164	मैसर्स दीपक ज्वैलर्स, 185/7/1, एफ पी रोहित मिल के सामने, अमीगंगा काम्पलैक्स के पास, खोखरा, अहमदाबाद-380 008	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	24-01-07
35.	7700063	मैसर्स दीपक ज्वैलर्स, 185/7/1, एफ पी रोहित मिल के सामने, अमीगंगा काम्पलैक्स के पास, खोखरा, अहमदाबाद-380 008	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 2112 : 2003	24-01-07
36.	7701873	मैसर्स बिलेट इलैक्ट्रो वर्क लिमिटेड, पहली मंजिल, जगत सतगुरु इंडस्ट्रियल एस्टेट, आफ : एरे रोड, गोरीगांव (ईस्ट), मुंबई-400063	कम्पैशन टाइप ट्यूबलर टर्मिनल एंडस फार एल्यूमिनियम कंडक्टर 8309 : 1993	10-01-07
37.	7702774	मैसर्स श्रीनी लिंक, प्लॉट नंबर 1308/2, जी आई डी सी, अंबरगांव, वलसाद-396171	पी वी सी इंसुलेटिड केबल 694 : 1990	24-01-07

फरवरी 2007 में स्वीकृत किये गये अनुज्ञप्ति

सं. क्र.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसी का नाम तथा पता	उत्पाद का नाम तथा आई एस	अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की तिथि
1.	7703069	सोनी हरीशकुमार कुंदनलाल, धर्मेश्वर महादेअे बाजार के पास, वेजलपुर, पंचमहल	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	05-02-07
2.	7704071	मैसर्स एम डी सोनी, 211, के टी प्लाजा शॉपिंग सेंटर, गांधी रोड, फयूवारा, अहमदाबाद-380 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	05-02-07
3.	7704172	मैसर्स लिबर्टी ज्वैलर्स, 4/766, मोटा बाजार, नवसारी-396 445	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	05-02-07
4.	7704273	किसान ज्वैलर्स, सविता भुवन, ग्राऊंड फ्लोर, नवरंगपुरा बस स्टॉप के पास, अहमदाबाद-380 009	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	05-02-07
5.	7706075	कांतिभाई जावेरी ज्वैलर्स, एफ/6, रतनम बिल्डिंग, सी जी रोड, अहमदाबाद-380 006	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	09-02-07
6.	7706176	मैसर्स अरिहंत ज्वैलर्स, ए/4/1-डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर, सैक्टर-21, गांधीनगर-382021	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	09-02-07

सं. क्र.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसी का नाम तथा पता	उत्पाद का नाम तथा आई एस	अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की तिथि
7.	7706277	कंगन ज्वैलर्स, बी/2/2, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर, सैक्टर-21, गांधीनगर-382021	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	09-02-07
8.	7706378	धरेना, 111, वाईट हाऊस, पैलेस रोड, पालनपुर, बंसकांटा	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	09-02-07
9.	7706883	मैसर्स उमिया ज्वैलर्स, बी/1/18 परकृति काम्पलैक्स, एस जे रोड, सिद्धपुर, पालन-384 151	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	12-02-07
10.	7707077	मैसर्स हीरा पत्रा ज्वैल एक्सपोर्ट प्रा. लि. 2224, ओल्ड शेयर बाजार के सामने, मुहरत पोल, मानेक चौक, अहमदाबाद-380 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	13-02-07
11.	7707178	स्वागत ज्वैलर्स, 207/2, स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	13-02-07
12.	7707279	दीपलता ज्वैलर्स, बी-97, कुबेरनगर, चाकला अस्पताल के पास, अहमदाबाद-382 340	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	12-02-07
13.	7707380	हरसुखलाल तथा बदर्स, पीपलावली खाडकी के सामने, जैन देरासर के पास, नरोडागाम, अहमदाबाद-382 330	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	12-02-07
14.	7707481	गोल्ड पाईट ज्वैलर्स, 221 टर्निंग पाईट काम्पलैक्स, धोड डोड रोड, सूरत-395 007	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	12-02-07
15.	7707582	रूशभ ज्वैलर्स, ए 5, नीलकंठ पैलेस, आनंदनगर, सचिन टावर रोड, सैटेलाइट, अहमदाबाद-380 015	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	12-02-07
16.	7707784	जसूभाई ईश्वरलाल पटेल, 3048, रतन पोल, नगिना पोल के पास, अहमदाबाद-380 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	12-02-07
17.	7708786	तिरूपति ज्वैलर्स, एफ/6, अजंता काम्पलैक्स, बस स्टाप के पीछे, एट तथा पी ओ मोडासा, साबरकांटा-383315	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	13-02-07
18.	7710167	पटेल केशवलाल जोयताराम, 2361, रानी ना हजिरा, मानेक चौक, अहमदाबाद-380 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	19-02-07

अनु. क्र.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसी का नाम तथा पता	उत्पाद का नाम तथा आई एस	अनुज्ञाप्ति स्वीकृत करने की तिथि
19.	7710268	श्री सामोर ज्वैलर्स, ए 43, मुदुलपार्क रा हाऊस पार्ट 3, आर सी टेकनिकल रोड, घाणक्यपुरी, अहमदाबाद-380 061	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	19-02-07
20.	7710369	एम एम ज्वैलर्स, 8-9 राजमंदिर काम्पलेक्स, कोषारली रोड, गुंजन, जी आई डीसी, वापी, वलसाद-396 195	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	19-02-07
21.	7710470	श्री संतोषी ज्वैलर्स सर्वे नंबर 4/756, मेहुज अपार्टमेंट के सामने, कृष्णानगर रोड, कृष्णानगर, अहमदाबाद-380 045	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	19-02-07
22.	7710571	श्री रंग अवधुत ज्वैलर्स, शील काम्पलेक्स, सोनीवाड, गोधरा, पंचमहल-389 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	19-02-07
23.	7711775	न्यू वृंदावन ज्वैलर्स, टावर बाजार, अशोक स्तंभ के पास, आनंद-388001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	22-02-07
24.	7711876	रतिलाल तथा बदर्स, 3/335, नवापुरा, कारवा रोड, सूरत-395 003	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	22-02-07
25.	7711977	घोतीबा ज्वैलर्स, 222-223, टर्निंग पाईट काम्पलेक्स, गोड डोड रोड, बड़ोदा-395 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	22-02-07
26.	7712070	धकाभाई ज्वैलर्स, धाडीअली पोल के सामने, एम जी रोड, मांडवी, बड़ोदा-390 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	22-02-07
27.	7712676	मैसर्स यश ज्वैलर्स, एम 5, अमीधारा शॉपिंग सेंटर, रंगोला रोड, गोड डोड रोड, सूरत-395 001	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	26-02-07
28.	77123577	उमैदभाई ज्वैलर्स, जी 2, मलीनाथ काम्पलेक्स, सुजाता फ्लैट के सामने, राजस्थान अस्पताल रोड, शाहीबाग, अहमदाबाद-380 005	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	26-02-07
29.	7713577	शाह हेमंतकुमार भीखालाल, 1754/55, काण्ड बाजार, काण्डवज, खेडा-387 620	स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	27-02-07
30.	7706974	क्रिष्णन ज्वैलर्स, सविता भुवन, ग्राऊंड फ्लोर, नवरंगपुरा बस स्टॉप के पास, अहमदाबाद-380 009	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 2112 : 2003	05-02-07
31.	7706984	ठमिया ज्वैलर्स, बी/1/18, मारुति काम्पलेक्स, एस जे रोड, सिद्धपुर, पाटन-384 151	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 2112 : 2003	12-02-07

क्रम. सं.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसी का नाम तथा पता	उत्पाद का नाम तथा आई एस	अनुज्ञापित स्वीकृत करने की तिथि
32.	7707683	रुशभ ज्वैलर्स, ए 5, नीलकण्ठ पैलेस, आनंदनगर, सचिन टावर रोड, सैटेलाइट, अहमदाबाद-380 015	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 2112 : 2003	12-02-07
33.	7707885	जसूभाई ईश्वरलाल पटेल, 3048, रतन पोल, नर्मिना पोल के पास, अहमदाबाद-380 001	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 2112 : 2003	13-02-07
34.	7713678	शाह हेमंतकुमार भीखालाल, 1754/55, कापड बाजार, कापडवंज, खेडा-387 620	चांदी एवं चांदी मिश्र धातुओं के आभूषणों/शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 2112 : 2003	27-02-07
35.	7705881	संगम इलैक्ट्रिकल, ई 9, बिरजू अपार्टमेंट, आजाद सोसाइटी के सामने, अंबावाडी, अहमदाबाद-380015	स्टार्टर फार कलॉरीसेंट लैंप 2215 : 1983	09-02-07
36.	7704677	फार्मा स्पोर्ट प्रा लि. प्लॉट नंबर 449, रनोली रेलवे स्टेशन रोड, पदमाला के पास, रनोली, बड़ोदा-391 350	प्रॉटेक्टिव हैलमेट फार स्कूटर तथा मोटर साइकिल राइडर 4151 : 1983	06-02-07
37.	7713375	कन्स्यूमर्स प्लास्टिक प्रा लि., पहली मंजिल, 5 डी, भोगरा गाँव रोड, सबवे के पास, अंधेरी ग्रेटर मुंबई-400069	हार्ड डैसीटी पालीथिलिन पाईप फार पोटेबल वाटर सापलाईस 4984 : 1995	28-02-07
38.	7708281	अर्चना इंजीनियरिंग वर्कर्स, एल 54, जी आई डी सी, ओल्ड वाटर टैंक के पीछे, ओढव, अहमदाबाद	पम्प-रीजैनेरेटिव या क्लीयर, कोल्ड वाटर 8472 : 1998	13-02-07
39.	7708382	शराफ इंजीनियरिंग लिमिटेड, 850/2, जी आई डी सी, मकरपुरा, बड़ोदा-390 010	मोटर्स फार सबमर्सिबल पम्पसेट 9283 : 1995	13-02-07
40.	7707986	भाग्यालक्ष्मी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, 32, अशरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, महालक्ष्मी टैक्सटाईल मिल के पीछे, नारोल इसनपुर रोड, नारोल, अहमदाबाद-382 405	कानडयूटस फार इलैक्ट्रिकल इंस्टालेशन पार्ट 3 रिजिड प्लेन कानडयूटस आफ इनसूलेटिंग मैटिरियल 9537 : पार्ट 3 : 1983	13-02-07
41.	7703574	ए साज एप्रीकेयर प्रा लि. लैंड अपार्टमेंट, पोलीग्राऊंड के सामने, बड़ोदरा	प्रोपोकसर इमलसिफाईएबल कनसनट्रेट 9665 : 1981	06-02-07
42.	7708180	अर्चना इंजीनियरिंग वर्कर्स, एल 54, जी आई डी सी एस्टेट, ओल्ड वाटर टैंक के पीछे, ओढव, अहमदाबाद	ओपनवैल सबमर्सिबल पम्पसेट 14220 : 1994	13-02-07
43.	7705780	नंदीनी बिबरेइज, 13-14, पारेख वाडी हिंदू मिलन मंदिर के सामने, कासानगर के सामने, एसयुएमयुएल डेरी रोड, कट्टरगाम	पैकेजबंद पेयजल 14543 : 2004	12-02-07
44.	7709485	शुद्ध जल बिबरेइज, 19, प्रकाश एस्टेट, रीटानगर, वसंतरल रोड, अहमदाबाद-380 026	पैकेजबंद पेयजल 14543 : 2004	19-02-07

सं. क्र.	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसी का नाम तथा पता	उत्पाद का नाम तथा आई एस	अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की तिथि
45.	7710672	हरि ओम बिबरेइज, 333/334, सुविधानगर, बावड़ी, बजरंग, गोधरा, पंचमहल 389 001	पेकेजबंद पेयजल 14543 : 2004	20-02-07
46.	7708079	क्राम्पटन ग्रीडवस लिमिटेड, सी जी हाऊस, 6 मंजिल, डा एनी बसंत रोड, वरली, मुंबई 400030	सेल्फ बलासिटड लैम्प फार जनरल लाइटिंग सर्विस 15111 : पार्ट 1: 2002	13-02-07
47.	7703271	अपोलो टायर लि., गाँव लिमडा, ता वाबोडिया, बड़ोदा 391 760	ओटोमोटिव विहीकल न्यूमैटिक टायर फार पैसेंजर कार विहीकल 15633 : 2005	10-01-07

[सं. सी एम डी/13 : 11]

एस. के. चौधरी, उप महानिदेशक (मुहर)

New Delhi, the 9 April, 2007

S.O. 1044.— In pursuance of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following schedule :

SCHEDULE

SL No.	Licence No.	Name and Address of the Licensee	Article/process with relevant Indian Standard covered by the Licensee	Date of Grant of licence
1.	7691189	M/s Shreya Ex-Tech Ltd., 102, Ashwamegh Complex, Opp. Sayajivihar Club, Rajmahal Road.	Flameproof enclosures for electrical apparatus IS 2148 : 2004	22-12-2006
2.	7691593	K. G. Gold Garden 2, Bhadraraj Chambers, Swastik Char Rasta, C. G. Road, Ahmedabad-380 009	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	02-01-2007
3.	7691694	Soni Subhaschandra Dwarkadas Jewellers, Hiralal Bhuvan, Modasa Sabarkantha-383 315	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	02-01-2007
4.	7691795	Soni Nitinkumar Bhailalbhai & co., G-47, Jay Shyamsunder Complex, Modasa Sabarkantha-383 315	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	02-01-2007
5.	7692393	Raj Ratn Jewellers GF/2, Satyam Complex, Opp. Railway Station, Maninagar, Ahmedabad-380 008	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	04-01-2007
6.	7692494	Pani Jewellers 4, Akshardham Appartments, Near Ambica Krupa Society, Ranip, Ahmedabad-382 480	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	04-01-2007
7.	7692801	Chokshi Narendrakumar Ganpatlal 209/2/23, 209/2/24, Near Ratnasagar Society, New Mental, Meghaninagar, Ahmedabad-380 016	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	05-01-2007

Sl. No.	Licence No.	Name and Address of the Licensee	Article/process with relevant Indian Standard covered by the Licensee	Date of Grant
8.	7692595	Mangalsutra Jewellers, C-11, Sayona City Shopping Centre, R.C. Technical Road, Ghatlodia, Ahmedabad-380 061	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	04-01-2007
9.	7692696	Mangalsutra Jewellers, C-11, Sayona City Shopping Centre, R.C. Technical Road, Ghatlodia, Ahmedabad-380 061	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 2112 : 2003	04-01-2007
10.	7692797	Bhikalal Bhogilal Patel & Co., 3077, Near Nagina Pole, Ratan Pole, Kalupur, Ahmedabad-380 001	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	04-01-2007
11.	7692902	Bhikalal Bhogilal Patel & Co., 3077, Near Nagina Pole, Ratan Pole, Kalupur, Ahmedabad-380 001	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking— IS 2112 : 2003	05-01-2007
12.	7694603	Gujarat Containers Limited, 201/202, Alkapuri Arcade, B Wing, Opp. Welcome Hotel, R. C. Dutt Road, Vadodara-390 005	Drums, Large, Fixed Ends— Specification—Part 1 : Grade A Drums 1783 (Pt. 1) : 1993	04-01-2007
13.	7694704	Gujarat Containers Limited, 201/202, Alkapuri Arcade, B Wing, Opp. Welcome Hotel, R. C. Dutt Road, Vadodara-390 005	Drums, Large, Fixed Ends— Specification—Part 2 : Grade B Drums 1783 (Pt. 2) : 1998	04-01-2007
14.	7696809	Chirag Engineers 43, 153, 154, Ashirvad Indl. Estate, Opp. Fruit Market, Naroda Road, Ahmedabad-380 025	Submersible Pumpsets IS 8034 : 2002	17-01-2007
15.	7696708	Parixit Ind. Ltd., 706, Silver Oaks, Mahalaxmi. Paldi, Ahmedabad-380 007	Irrigation equipment—Rotating sprinkler : Part 1 Design and operational requirements 12232 (Pt. 1) : 1996	10-01-2007
16.	7696102	Hari Om Gold Palace, 3003, Opp. Bank of Baroda. Delhi Chakla, P. O. Shahpur, Ahmedabad-380 001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	17-01-2007
17.	7696203	Milap Jewellers, 102-102, CB Desai Chambers, Near Gunjan Cinema, Koparli Road, GIDC, Vapi-396 195	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	17-01-2007
18.	7696304	Mahalaxmi Jewellers, 11 White House, Palace Road, Gurunanak Chowk, Palanpur-385 001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking— IS 1417 : 1999	17-01-2007
19.	7696910	Yogeshkumar & Brothers 3/304, N.R. Ashok Stambh Tower, Bazar, Anand 388 001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417 : 1999	19-01-2007

Sl. No.	Licence No.	Name and Address of the Licensee	Article/process with relevant Indian Standard covered by the Licensee	Date of Grant
20.	7697003	Sona Mahor, 13, White House, Palace Road, Palanpur, Gujarat-385 001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	19-01-2007
21.	7697104	New Umiya Jewellers, Shop No. 3, Manaharnagar Soc., Part 1, Opp. Krishna Vidhyalay, Bapunagar Ahmedabad-380 024	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	19-01-2007
22.	7697205	New Umiya Jewellers, Shop No. 3, Manaharnagar Soc., Part 1, Opp. Krishna Vidhyalay, Bapunagar Ahmedabad-380 024	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 2002: 2003	19-01-2007
23.	7697306	Pushpam Jewellers, 974, Sadar Bazar, Deesa Banaskantha-385 535	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	19-01-2007
24.	7697407	Navarang Jewellers, 365/16, Opp. Saraspur Mill, Saraspur: Ahmedabad	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	19-01-2007
25.	7698308	V. V. Jewellers, 28, Ratanpole, Gandhi Road, Ahmedabad-380 001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	23-01-2007
26.	7698510	Zaveri Vaghajibhai Sunderjibhai Jewellers, 5, Garda College Shopping Centre, Sayaji Road, Navsari -396 445	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	23-01-2007
27.	7698409	Zaveri, 24, Shantilal Shah Chambers, Opp. Naya Mandir, Deesa, Banaskantha-385 535	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	23-01-2007
28.	7699310	Sai Industries, L-104/13, 5, 6, Opp. Lalji Mulji Transport Co., Road No. 1 G.I.D.C., Sarigam-396 155, Valsad	Flameproof enclosures for electrical apparatus IS 2148	23-01-2007
29.	7699916	Jay Ambe Jewellers, G-9, Dayasagar Apartment, Dixit Street, Anand-388 001	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking IS 2002: 2003	24-01-2007
30.	7699815	Jay Ambe Jewellers, G-9, Dayasagar Apartment, Dixit Street, Anand-388 001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	24-01-2007
31.	7699714	A. B. Jewellers (Satemwala) 3-4, Landmark Mall, Near Sayaji Library, Navsari-396 445	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	24-01-2007

Sl. No.	Licence No.	Name and Address of the Licensee	Article/process with relevant Indian Standard covered by the Licensee	Date of Grant
32.	7700366	Ambika Gold Palace, 1/17/36, Ghiwta Naka Bazar, Gandhi Road, Patan-384265	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking IS 2002: 2003	24-01-2007
33.	7700265	Ambika Gold Palace, 1/17/36, Ghiwta Naka, Bazar, Gandhi Road, Patan-384265	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	24-01-2007
34.	7700164	Dipak Jewellers, 185/7/1, F.P., Opp., Rohit Mill, Near Amiganga Complex, Khokhara, Mahemdabad Ahmedabad	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	24-01-2007
35.	7700063	Dipak Jewellers, 185/7/1, F.P., Opp., Rohit Mill, Near Amiganga Complex, Khokhara, Mahemdabad Ahmedabad	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking IS 2002: 2003	24-01-2007
36.	7701873	Billeets Electro Wereke Ltd., 1st Floor Jagat Satguru Industrial Estate, Off: Arey Road, Goregaon (East) Mumbai-400063	Compression type tubular terminal ends for aluminum conductors of insulated cables IS 8309: 1993	10-01-2007
37.	7702774	Srini Link Plot No. 1308/2, GIDC, Umbergaon Valsad-396171	PVC Insulated cables for working voltages upto and including 1100 V IS 104: 1990	24-01-2007

Licence Granted for the Month of February, 2007

Sl. No.	Licence No.	Name and Address of the Licensee	Article/process with relevant Indian Standard covered by the Licensee	Date of Grant of licence
1.	7703069	Soni Harishkumar Kundanlal, Near Dharmeshwar Mahadeo Bazar, Vejalpur, Panchmahal-389	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	05-02-07
2.	7704071	M. D. Soni, 211, K. T. Plaza Shopping Centre, Gandhi Road, Fuwara, Ahmedabad-380001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	05-02-07
3.	7704172	Liberty Jewellers, 4/766, Mota Bazar, Navsari-396445	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	05-02-07
4.	7704273	Kisan Jewellers, Savita Bhuvan Ground Floor, Near Navarangpura Bus Stop, Ahmedabad-380009	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	05-02-07
5.	7706075	Kantibhai Zaveri Jewellers, F/6, Ratnam Building, C. G. Road, Ahmedabad-380006	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	09-02-07

Sl. No.	Licence No.	Name and Address of the Licensee	Article/process with relevant Indian Standard covered by the Licensee	Date of Grant of Licence
6.	7706176	Arihant Jewellers, A/4/1-District Shopping Centre, Sector-21, Gandhinagar-382021	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	09-02-07
7.	7706277	Kangan Jewellers, B/2/2-District Shopping Centre, Sector-21, Gandhinagar-382021	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	09-02-07
8.	7706378	Gharena 111, White House, Palace Road, Palanpur Banaskantha-385001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	09-02-07
9.	7706883	Umiya Jewellers, B/1/18, Maruti Complex, S. J. Road, Siddhpur, Patan-384151	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	12-02-07
10.	7707077	Heera Panna Jewel Exporters Pvt. Ltd., 2224, Opp. Old Share Bazaar, N.R. Muharath Pole, Manek Chowk, Ahmedabad-380001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	13-02-07
11.	7707178	Swagat Jewellers, 207/2, District Shopping Centre, Sector-21, Gandhinagar-382021	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	12-02-07
12.	7707279	Deeplata Jewellers, B-97, Kubernagar, N.R. Chawla Hospital, Ahmedabad-382340	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	12-02-07
13.	7707380	Harsukhlal & Brothers Opp. Piplawali Khadki, NR. Jain Derasar, Narodagam, Ahmedabad-382330	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	12-02-07
14.	7707481	Gold Point Jewellers, 221, Turning Point Complex, Ghod Dod Road, Surat-395007	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	12-02-07
15.	7707582	Rushabh Jewellers, A-5, Nilkanth Palace, Anandnagar, Sachin Tower Road, Satellite, Ahmedabad-380015	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	12-02-07
16.	7707784	Jasubhai Ishwarlal Patel 3048, Ratan Pole, Near Nagina Pole, Ahmedabad-380001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	12-02-07

Sl. No.	Licence No.	Name and Address of the Licensee	Article/process with relevant Indian Standard covered by the Licensee	Date of Grant of licence
17.	7708786	Tirupati Jewellers, F/6, Ajanta Complex, Behind Bus Stand, AT & PO Modasa Sabarkantha 383315	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	13-02-07
18.	7710167	Patel Keshavalal Joitaram, 2361, NR. Rani NA Hajira, Manekchowk, Ahmedabad-380001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	19-02-07
19.	7710268	Shri Samor Jewellers, A-43, Mrudulapark Row House Part 3, R. C. Technical Road, Chanakypuri, Ahmedabad-380061	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	19-02-07
20.	7710369	M. M. Jewellers, 8-9, Ranmandir Complex, Koparli Road, Gunjan GIDC, Vapi, Valsad 396195	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	19-02-07
21.	7710470	Shri Santosh Jewellers, Survey No. 4/756, Opp. Mchul Appartment, Krushanagar Road, Krushnanagar, Ahmedabad-380045	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	19-02-07
22.	7710571	Shree Ranmg Avdhut Jewellers, Shil Complex, Soniwad, Godhra, Pancmahal-389001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	19-02-07
23.	7711775	New Vrundavan Jewellers, Tower Bazar, NR. Ashok Stambh, Anand-388001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	22-02-07
24.	7711876	Ratilal & Brothers, 3/335, Navapura, Karwa Road, Surat-395003	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	22-02-07
25.	7711977	Motisha Jewellers, 222-223, Turning Point Complex, Ghod-DOD Road, Surat-395001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	22-02-07
26.	7712070	Chakabhai Jewellers, Opposite Ghadiali Pole, M.G. Road, Mandvi, Vadodara 390001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	22-02-07
27.	7712676	Yash Jewellers, M-5, Amidhara Shopping Centre, Rangila Park, Ghod-Dod Road, Surat-395001	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	26-02-07

Sl. No.	Licence No.	Name and Address of the Licensee	Article/process with relevant Indian Standard covered by the Licensee	Date of Grant of Licence
28.	7712777	Umedbhai Jewellers G-2, Mallinath Complex, Opp. Sujata Flate, Rajasthan Hospital Road, Shahibaug Ahmedabad-380 005	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	26-02-07
29.	7713577	Shah Hemantkumar Bhikhalal 1754/55, Kapad Bazar, Kapadvanj Kheda-387620	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking—Specification IS 1417: 1999	27-02-07
30.	7704374	Kisan Jewellers, Savita Bhuvan Ground Floor, Near Navarangpura Bus Stop, Ahmedabad 380 009	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking IS 2112: 2003	05-02-07
31.	7706984	Umiya Jewellers, B/1/18, Maruti Complex, S. J. Road, Siddhpur, Patan-384151	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking IS 2112: 2003	12-02-07
32.	7707683	Rushabh Jewellers, A-5, Nilkanth Palace, Anandnagar, Sachin Tower Raod, Satellite, Ahmedabad-380015	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking IS 2112: 2003	12-02-07
33.	7707885	Jasubhai Ishwarlal Patel 3048, Ratan Pole, Near Nagina Pole, Ahmedabad-380 001	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking IS 2112: 2003	13-02-07
34.	7713678	Shah Hemantkumar Bhikhalal 1754/55, Kapad Bazar, Kapadvanj Kheda-387620	Silver and Silver Alloys, Jewellery/Artefacts—Fineness and Marking IS 2112: 2003	27-02-07
35.	7705881	Sangam Electricals E/9, Birju Apartments, Opp. Azad Society, Ambawadi, Ahmedabad-380015	Starters for Fluorescent Lamps IS 2215: 1983	09-02-07
36.	7704677	Forma Sports Pvt. Ltd., Plot No. 449, Ranoli Railway Station Road, Near Padmala, Ranoli, Vadodara-391350	IS 4151: 1993	06-02-07
37.	7713375	Consumers Plastics Pvt. Ltd., First Floor, 5-D, Mogra Village Road, Near Subway, Andheri (E), Greater Mumbai-400069	High Density Polyethylene Pipes for Potable Water Supplies 4984: 1995	28-02-07

Sl. No.	Licence No.	Name and Address of the Licensee	Article/process with relevant Indian Standard covered by the Licensee	Date of Grant of Licence
38.	7708281	Archana Engineering Works L-54, GIDC Estate, B/H Old Water Tank, Odhav, Ahmedabad	Pumps—Regenerative or clear, Cold Water 8472 : 1998	13-02-07
39.	7708382	Shroffs Engineering Ltd., 850/2, GIDC, Makarpura, Vadodara-390010	Motors for Submersible Pumpsets IS 9283 : 1995	13-02-07
40.	7707986	Bhagylaxmi Plastic Industries 32, Ashra Industrial Estate, B/H, Mahalaxmi Textile Mills, Narol-Isanpur Road, Narol, Ahmedabad-382405	Conduits for electrical installations : Part 3 Rigid plain conduits of insulating materials (superseding IS 2509) 9537 : Part 3 : 1983	13-02-07
41.	7703574	A Saj Agricare Pvt. Ltd., Lad Appartment, Opp. Pologround, Vadodara	Specification for Propoxur Emulsifiable Concentrates IS 9665 : 1981	06-02-07
42.	7708180	Archana Engineering Works L, 54, GIDC Estate, B/H, Old Water Tank, Odhav, Ahmedabad-382415	Openwell Submersible Pumpsets 14220 : 1994	13-02-07
43.	7705780	Nandini Beverages 13-14, Parakh Wadi, Opp. Hindu Milan Mandir, Opp. Kasanagar, Sumul Dairty Road, Katargam	Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water) 14543 : 2004	12-02-07
44.	7709485	Sudh Jal Beverages 19, Prakash Estate, Ritanagar, Vastral Raod, Ahmedabad-380026	Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water) 14543 : 2004	19-02-07
45.	7710672	Hari Om Beverages 333/334, Suvidhanagar, Vavdi (Bujarg), Godhra Panchmahal-389001	Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water) 14543 : 2004	20-02-07
46.	7708079	Crompton Greaves Limited, CG House, Sixth Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400030	Self Ballasted Lamps for General Lighting Services—Part 1 : Safety Requirements 15111 : Part 1 : 2002	13-02-07
47.	7703271	Apollo Tyres Ltd., Village : Limda, Tal : Waghodia Vadodra 391760	Automotive Vehicles—Pneumatic Tyres for Passenger Car Vehicles— Diagonal and Radial Ply— Specification IS 15633 : 2005	10-01-07

[No. CMD/13 : 11]

S. K. CHAUDHURI, Dy, Director General (Marks)

कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2007

का. आ. 1045.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड - 3, उप खण्ड (ii) तारीख 09 अप्रैल, 2005 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. सं. 1297 तारीख 29 मार्च, 2005 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में, जिसका माप 589.000 हेक्टर (लगभग) या 238.36 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी,

और, केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्त है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में यथावर्णित 509.20 एकड़ (लगभग) या 206.073 हेक्टेयर (लगभग) माप की उक्त भूमि में के सभी अधिकारों को अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती हैं।

टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले रेखांक सं. एमसीएल/ एसबीपी (एल./आर और आर)/पद्यमा/06/158, तारीख 17 जुलाई, 2006 का निरीक्षण, कलेक्टर, अंगुल (उड़ीसा) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता 700001 के कार्यालय में या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (महाप्रबंधक, भूमि/आर.आर.विभाग), जागृति विहार, पोस्ट-जागृति विहार, बुर्ला, जिला संबलपुर (उड़ीसा) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण 2: उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबन्ध है:—

अर्जन की बाबत आपत्तियां :-

- (8) (1) कोई व्यक्ति, किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :- इस धारा के अर्थात्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जायेगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिये स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी का लिखित रूप में की जायेगी और सक्षम अधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह

1113(भाग), 1114(भाग), 1164(भाग), 10/1172, 605/1173, 651/1175, 842/1177, 649/1178, 4/1180, 26/1187, 561/1189, 648/1179(भाग), 179/1181, 176/1182, 216/1183, 15/1184, 99/1185, 99/1186, 572/1188, 880/1193, 875/1194, 815/1195, 851/1196, 851/1197, 851/1198, 273/1199, 235/1200, 440/1201 से 440/1209, 564/1210, 515/1212, 99/1213, 387/1214, 562/1215, 240/1216, 658/1218, 715/1219, 641/1220, 721/1223, 1108/1224, 1108/1225, 732/1226 से 732/1228, 799/1229(भाग), 799/1230, 236/1237 से 236/1240, 850/1241, 856/1242 से 856/1246, 850/1250, 121/1251 से 121/1255, 25/1256 से 25/1265, 29/1266 से 29/1286, 157/1287 से 157/1292, 156/1293 से 156/1295, 427/1296, 367/1297, 367/1298, 348/1299, 348/1300 से 348/1303, 270/1305, 269/1306, 260/1307, 130/1308, 244/1309, 10/1311, 10/1312, 12/1313, 203/1314, 11/1315, 730/1317, 664/1320, 562/1321, 231/1322, 903/1323, 6/1324, 640/1329, 547/1332, 515/1333, 3/1334, 232/1335, 232/1336, 648/1337(भाग), 580/1339, 579/1340, 120/1341, 164/1343, 163/1344, 162/1345, 234/1346, 273/1347, 237/1348, 176/1350, 141/1351, 266/1352, 205/1357, 863/1358, 409/1359, 468/1360, 133/1363 से 133/1366, 285/1267 से 285/1371, 286/1372 से 286/1375, 276/1376 से 276/1379, 480/1392, 772/1393, 72/1394, 39/1422 से 39/1426, 24/1427 से 24/1442, 99/1443 से 99/1447, 179/1448 से 179/1452, 3/1454, 211/1455, 211/1456, 1175/1458, 1175/1459, 99/1463, 177/1468, 165/1469, 517/1471, 197/1472, 183/1473, 358/1474, 850/1475, 627/1479, 197/1480, 198/1481, 808/1482, 411/1487 से 411/1490

3. नकईपासी ग्राम (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सं.

194, 201 से 210, 211(भाग), 212 से 230, 232, 233, 234(भाग), 235(भाग), 264 से 291, 295 से 352, 294(भाग), 353(भाग), 357(भाग), 358 से 360, 361(भाग), 297/1269, 303/2870, 303/2871, 315/2872, 312/2873, 305/2874, 349/2875, 339/2876, 296/2877, 286/2888, 266/2963, 290/2966, 334/2972, 335/2973, 335/2974, 231/3146, 336/3181, 332/3182, 347/3183, 270/3185

4. बृन्दावनपुर ग्राम (पूर्ण) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सं.

1 से 96, 31/97, 6/98, 6/99, 6/100, 6/101, 59/102, 49/103, 48/104, 28/105, 19/106, 19/107, 59/108, 45/109, 11/110, 20/111, 20/112, 18/113, 18/114, 96/115, 94/116, 11/117, 11/118, 11/119, 12/120, 25/121, 31/122, 94/123, 96/124 से 96/126, 10/127, 11/128.

सीमा वर्णन

क-ख-ग- रेखा बिंदु "क" से आरंभ होती है जो ग्राम अल्लाहदनगर और राकस की सम्मिलित सीमाओं से होते हुए बृन्दावनपुर और अल्लाहदनगर की सम्मिलित सीमा के साथ भागतः पूर्व छोर से होते हुए बिंदु "ग" पर पहुंचती है।

ग-घ-ङ-च-छ-ज यह रेखा बांगरू नाला के उत्तरी सीमा के होकर गुजरती है।

ज-झ- रेखा ज बिंदु से आरंभ होकर प्लॉट सं. 0294 से गुजरती हुई प्लॉट सं. 291 के पश्चिमी सीमा से होकर प्लॉट सं. 194 के उत्तरी एवं पश्चिमी सीमा से चलकर प्लॉट सं. 205 के उत्तरी पश्चिमी सीमा के प्लॉट सं. 204 एवं प्लॉट सं. 203, 202, 201 से गुजरती हुई दक्षिणी सीमा के

आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कारबाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट कन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह व्यक्ति किसी भूमि में हितवद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।

टिप्पण 3: - केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700001 को उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचना सं. का.आ.2015 तारीख 10 जुलाई 1995 द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

पदमा ब्लाक

तालचेर कोयला क्षेत्र (तालचेर क्षेत्र)

जिला अंगुल(उड़ीसा)

सभी अधिकार-

प्लान सं. एमसीएल/एसबीपी(एल/आर एंड आर)/पदमा/06/158 तारीख 17.7.2006)

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पुलिस स्टेशन	तहसील	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1	पदमावतीपुर	तालचेर 30	तालचेर	अंगुल	52.28	भाग
2	राकस	कोलियरी81	तालचेर	अंगुल	294.26	भाग
3	नकईपासी	कोलियरी23	तालचेर	अंगुल	57.01	भाग
4	बृंदावनपुर	कोलियरी83	तालचेर	अंगुल	105.65	भाग

योग

509.20(लगभग) या 206.073हेक्टर (लगभग)

1. पदमावतीपुर ग्राम (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याक:

1 से 113, 114(भाग), 115 से 121, 122(भाग), 123, 124, 125(भाग), 132(भाग), 139(भाग), 142(भाग), 47/1170, 27/1208, 3/1214, 25/1216, 24/1217, 26/1221, 10/1222, 10/1225, 51/1230, 86/1233, 85/1234, 10/1235, 101/1236(भाग), 102/1251, 57/1255, 112/1262, 15/1269, 16/1270, 17/1271, 20/1272, 122/1276, 141/1280(भाग), 33/1285, 52/1286, 60/1287, 29/1289, 121/1297, 39/1334, 1255/1390, 18/1434, 18/1444, 18/1455, 33/1463, 39/1464, 33/1468, 33/1469, 39/1470, 33/1473, 38/1474, 39/1475, 59/1476, 33/1477, 33/1480, 39/1481, 48/1482, 119/1483, 38/1488, 39/1489,

2. राकस ग्राम (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सं.

1 से 580, 581(भाग), 582 से 645, 646(भाग), 647(भाग), 648(भाग), 649 से 722, 723(भाग), 729(भाग), 730(भाग), 731 से 798, 799(भाग), 800 से 880, 903(भाग), 904 से 906, 907(भाग), 920 से 925, 950 से 952, 960(भाग), 961(भाग), 962(भाग), 1096(भाग), 1097, 1098, 1107 से 1112,

रेखा बिंदु "ट" से होकर दक्षिणी सीमा के प्लॉट सं. 857, 858, 879, 880/1193 से होकर प्लॉट सं. 903 से गुजरते हुए दक्षिणी सीमा के प्लॉट सं. 905, 903/1323 से होकर प्लॉट सं. 907 से गुजरती है। फिर रेखा दक्षिणी सीमा से होकर प्लॉट सं. 920, 925 से होकर प्लॉट सं. 799 से गुजरते हुए दक्षिणी सीमा के प्लॉट सं. 753, 731 से होकर प्लॉट सं. 730, 729, 723, 1096 से गुजरती है। फिर रेखा दक्षिणी सीमा के प्लॉट सं. 1098, 1107, 1224, 1112 से होकर प्लॉट सं. 1113, 1114, 1179, 1337, 1224, 1112 से होकर प्लॉट सं. 1113, 1114, 1179, 1337, 648, 647, 646, 581, 1164 से गुजरती है और रेखा चलकर प्रारंभिक बिंदु "क" पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/4/2005-पी.आर.आई.डब्ल्यू.]

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

Ministry of Coal

New Delhi, the 19th March, 2007

S. O. 1045.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, S.O. number 1297 dated 29th March, 2005 under sub-section (i) of section-4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957) hereinafter referred to as the said Act. and published in part-II, Section-3, sub-section (ii) of the Gazette of India dated 9th April 2005, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 589.000 acres (approximately) or 238.36 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification.

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section-7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 509.20 acres (approximately) or 206.073 hectares (approximately) in all rights as described in the schedule appended hereto.

1. The Plan bearing NO. MCL/ SBP (L/R&R) /Padma 06 / 158 dated 17th July, 2006 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, Angul, (Orissa) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata, or in the office of the Mahanadi Coalfields Limited (General Manager, Land / R&R Deptt.), Jagriti Vihar, P.O- Jagriti Vihar, Burla, Dist. Sambalpur (Orissa).

2. Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act, which provide as follows:-

Objection to acquisition -

8 (i) - Any person interested in land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or any rights in or over such land.

Explanation

(1) It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operation in the land for the production of coal and that such operation should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of

different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

Note: The Coal Controller, 1, Counsel House Street, Kolkatta -700001 has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act, vide notification number S.O. 2015 dated 10th July, 1995.

SCHEDULE
Padma Block, Talcher Coalfield,
District Angul, (Orissa)

All Rights

(Plan bearing NO. MCL/SBP(L/R&R)/Padma/06/158 dated 17.7.2006)

SL.No.	Village	Police station & No	Tahsil / Sub Div.	District	Area in Acres (approx.)	Remarks
1	Padmabatipur	Talcher - 30	Talcher	Angul	52.28	Part
2	Rakas	Colliery- 81	Talcher	Angul	294.26	Part
3	Nakeipasi	Colliery - 23	Talcher	Angul	57.01	Part
4	Brundabanpur	Colliery - 83	Talcher	Angul	105.65	Full
Total					509.20 acres (approximately or 206.073 hectares (approximately))	

1. Plot numbers to be acquired in village Padmabatipur (Part).

1 to 113,114(P), 115 to 121,122(P), 123,124,125(P), 132(P), 139(P), 142(P),47/1170, 27/1208, 3/1214, 25/1216, 24/1217, 26/1221, 10/1222, 10/1225, 51/1230, 86/1233, 85/1234, 10/1235, 101/1236(P), 102/1251, 57/1255, 112/1262, 15/1269, 16/1270, 17/1271, 20/1272, 122/1276, 141/1280(P), 33/1285, 52/1286, 60/1287, 29/1289, 121/1297, 39/1334, 1255/1390, 18/1434, 18/1444, 18/1455, 33/1463, 39/1464, 33/1468, 33/1469, 39/1470, 33/1473, 38/1474, 39/1475, 59/1476, 33/1477, 33/1480, 39/1481, 48/1482, 119/1483, 38/1488, 39/1489.

2. Plot numbers to be acquired in village Rakas.

1 to 580, 581(p), 582 to 645, 646(p), 647(p), 648(p), 649 to 722, 723(p), 729(p), 730(p), 731 to 798, 799 (p), 800 to 880, 903 (p), 904 to 906, 907 (p), 920 to 925, 950 to 952, 960 (p), 961 (p), 962 (p), 1096 (p), 1097, 1098, 1107 to 1112, 1113(p), 1114(p), 1164 (p), 10/1172, 605/1173, 651/1175, 842/1177, 649/1178, 4/1180, 26/1187, 561/1189, 648/1179(p), 179/1181, 176/1182, 216/1183, 15/1184, 99/1185, 99/1186, 572/1188, 880/1193, 875/1194, 815/1195, 851/1196, 851/1197, 851/1198, 273/1199, 235/1200, 440/1201 to 440/1209, 564/1210, 515/1212, 99/1213, 387/1214, 562/1215, 240/1216, 658/1218, 715/1219, 641/1220, 721/1223, 1108/1224, 1108/1225, 732/1226 to 732/1228, 799/1229 (p), 799/1230, 236/1237 to 236/1240, 850/1241, 856/1242 to 856/1246, 850/1250, 121/1251 to 121/1255, 25/1256 to 25/1265, 29/1266 to 29/1286, 157/1287 to 157/1292, 156/1293 to 156/1295, 427/1296, 367/1297, 367/1298, 348/1299, 348/1300 to 348/1303, 270/1305, 269/1306, 260/1307, 130/1308, 244/1309, 10/1311, 10/1312, 12/1313, 203/1314, 11/1315, 730/1317, 664/1320, 562/1321, 231/1322, 903/1323, 6/1324, 640/1329, 547/1332, 515/1333,

3/1334, 232/1335, 232/1336, 648/1337 (p), 580/1339, 579/1340, 120/1341, 164/1343, 163/1344, 162/1345, 234/1346, 273/1347, 237/1348, 176/1350, 141/1351, 266/1352, 205/1357, 863/1358, 409/1359, 468/1360, 133/1363 to 133/1366, 285/1267 to 285/1371, 286/1372 to 286/1375, 276/1376 to 276/1379, 480/1392, 772/1393, 772/1394, 39/1422 to 39/1426, 24/1427 to 24/1442, 99/1443 to 99/1447, 179/1448 to 179/1452, 3/1454, 211/1455, 211/1456, 1175/1458, 1175/1459, 99/1463, 177/1468, 165/1469, 517/1471, 197/1472, 183/1473, 358/1474, 850/1475, 627/1479, 197/1480, 198/1481, 808/1482, 411/1487 to 411/1490.

3. Plot numbers to be acquired in village Nakeipasi.

194, 201 to 210, 211(p), 212 to 230, 232, 233, 234(p), 235(p), 264 to 291, 295 to 352, 294(p), 353(p), 357(p), 358 to 360, 361(p), 297/1269, 303/2870, 303/2871, 315/2872, 312/2873, 305/2874, 349/2875, 339/2876, 296/2877, 286/2888, 266/2963, 290/2966, 334/2972, 335/2973, 335/2974, 231/3146, 336/3181, 332/3182, 347/3183, 270/3185.

4. Plot numbers to be acquired in village Brundabanpur.

1 to 96, 31/97, 6/98, 6/99, 6/100, 6/101, 59/102, 49/103, 48/104, 28/105, 19/106, 19/107, 59/108, 45/109, 11/110, 20/111, 20/112, 18/113, 18/114, 96/115, 94/116, 11/117, 11/118, 11/119, 12/120, 25/121, 31/122, 94/123, 96/124 to 96/126, 10/127, 11/128.

BOUNDARY DESCRIPTION

A-B-C : Line starts from point 'A' and passes partly along the common boundary of villages Ahladnagar and Rakas and partly along the common boundary of Brundabanpur and Ahladnagar in the Eastern side and meets at point 'C'.

C-D-E-F-G-H-I : This line passes along Bangaru Nalla in the Northern side.

I-J : Line passes through plot Nos. 294, along the Western boundary of plot Nos 291, Northern and Western boundary of plot Nos 194, along Northern boundary of plot No. 205, Northern and Western boundary of plot No. 204, along Western boundary of plot Nos. 203, 202, 201, along Southern boundary of plot No. 206, 207, along Western boundary of plot Nos. 210, 211, 235 of village Nakeipasi and meets at point 'J'.

J-K : The line starts from point 'J' and passes through plot No. 235, 211, along Southern boundary of plot No. 233, 232, 231/3146, 264, 265, 266, 2963, 268, along Eastern boundary of plot No. 269, along Southern boundary of plot No. 351, along Western and Southern boundary of plot No. 352, through plot No 353, along Southern boundary of plot No. 340, 339, through plot Nos 357, 361 of village Nakeipasi and meets at point 'K'.

K-L : The line passes through the plot Nos 122, 125, 132, 114 along Southern boundaries of plot Nos 112/1262, 107, 106, through plot No. 139, 141/1280, 142, 101/1236 and meets at point 'L' on common boundary of village Padmabatipur and Rakas

L-A : The line passes along Southern boundaries of plot Nos 857, 858, 879, 880/1193, through plot No 903, along Southern boundaries of plot Nos 905, 903/1323, through plot Nos 907, along Southern boundaries of plot Nos. 920, 925, through plot Nos 799, along Southern boundary of plot Nos 753, 731, through plot Nos 730, 729, 723; 1096,, along Southern boundary of plot Nos 1098, 1107, 1224, 1112, through plot Nos 1113, 1114, 1179, 1337, 648, 647, 646, 581, 1164, and lastly meets at point 'A'.

[F. No. 43015/4/2005-P.R.I.W.]
H. C. AGARWAL, Director

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

का. आ. 1046.— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 12-08-2006 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. 3121 तारीख 10-08-2006 द्वारा अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची तालुका दाहोद, जिला. दाहोद, राज्य गुजरात में विनिर्दिष्ट भूमि में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन खिड़ाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 26-09-2006 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए ;

अतः अद्ध केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन खिड़ाने के लिए इस अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के ख़ाया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सभी विल्लगमों से मुक्त होकर प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

तालुका : दाहोद	जिला : दाहोद		राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं-खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
खेंग	47		0	46	61
	1	A/2	0	08	10

[फा. सं. आर-25011/6/2006-ओ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 2nd April, 2007

S.O. 1046.—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 3121 dated 10-08-2006 issued under sub section (I) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published in the Gazette of India dated 12-08-2006 the Central Government declared its intention to acquire the right of User in the land specified in the schedule for Tehsil, Dahod District Dahod in the State of Gujarat for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam by Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 26-09-2006 ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (I) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government ;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that right of user in the land specified in the schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of said Act, the Central Government hereby direct that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of the publication of this declaration in Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Shedule

Tehsil:-Dahod	Dist:-Dahod		State:-Gujarat		
Name of village	Survey/Block No.	Sub - Division No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr..
1	2	3	4	5	6
Kheng	47		0	46	61
	1	A/2	0	08	10

[F. No. R-25011/6/2006-O.R.-I]
S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

का. आ. 1047.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 12-08-2006 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. 3122 तारीख 10-08-2006 द्वारा अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची तालुका लीमखेडा, जिला. वाहोद, राज्य गुजरात में विनिर्दिष्ट भूमि में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन द्खाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 26-09-2006 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए ;

अतः : अद्ध केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन द्खाने के लिए इस अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के द्खाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सभी विल्लगमों से मुक्त होकर प्रकाशनी इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

तालुका : लीमखेडा	जिला : दाहोद		राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं-खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
खीरखेरी	86		0	09	21
	236		0	13	79

[फा. सं. आर-25011/6/2006-ओ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2007

S. O. 1047.— Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 3122 dated 10-08-2006 issued under sub section (I) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published in the Gazette of India dated 12-08-2006 the Central Government declared its intention to acquire the right of User in the land specified in the schedule for Tehsil, Limkheda, District Dahod in the State of Gujarat for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam by Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas. the copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 26-09-2006 ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (I) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government ;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that right of user in the land specified in the schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of said Act, the Central Government hereby direct that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of the publication of this declaration in India Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Schedule

Tehsil:-Limkheda	Dist:-Dahod		State:-Gujarat		
Name of village	Survey/Block No.	Sub - Division No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Khirkheri	86		0	09	21
	236		0	13	79

[F. No. R-25011/6/2006-O.R.-I]
S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

का. आ. 1048.— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 12-08-2006 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. 3123 तारीख 10-08-2006 द्वारा अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची तालुका हलोल जिला, पंचमहाल, राज्य गुजरात में विनिर्दिष्ट भूमि में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 26-09-2006 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए ;

अतः ; अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सभी वित्तगतों से मुक्त होकर प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

तालुका : हालोल	जिला : पंचमहाल		राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं-खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
कंजरी (चन्द्रपुरा)	2305		0	02	66
	2304		0	00	20
	2306		0	27	09
	2313	2	0	19	16
	2345		0	51	32
	2354		0	31	36
	2355		0	39	91
	2356		0	35	64
	2357		0	24	23
	1495		0	18	53
	2358		0	21	38
	2360		0	27	08
	2365		0	49	89

[फा. सं. आर-25011/7/2006-ओ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2007

S. O. 1048.— Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 3123 dated 10-08-2006 issued under sub section (I) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published in the Gazette of India dated 12-08-2006, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule for Tehsil, Halol. District Panchmahal in the State of Gujarat for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam by Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 26-09-2006 ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (I) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government ;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that right of user in the land specified in the schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of the publication of this declaration in Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Shedule

Tehsil:-Halol	Dist:-Panchmahal		State:-Gujarat		
Name of village	Survey/Block No.	Sub - Division No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Kanjari(Chandrapura)	2305	2	0	02	66
	2304		0	00	20
	2306		0	27	09
	2313		0	19	16
	2345		0	51	32
	2354		0	31	36
	2355		0	39	91
	2356		0	35	64
	2357		0	24	23
	1495		0	18	53
	2358		0	21	38
	2360		0	27	08
	2365		0	49	89

[F. No. R-25011/7/2006-O.R.-I]

S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

का. आ. 1049.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 12-08-2006 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. 3124 तारीख 10-08-2006 द्वारा अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची तालुका कालोल जिला. पंचमहाल, राज्य गुजरात में विनिर्दिष्ट भूमि में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन खिड़ाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 26-09-2006 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए ;

अतः : अद्ध केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन खिड़ाने के लिए इस अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के त्वाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सभी वित्तगमों से मुक्त होकर प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

तालुका : कालोल	जिला : पंचमहाल		राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं-खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
व्यासडा	1194		0	07	25

[फा. सं. आर-25011/7/2006-ओ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2007

S. O. 1049.— Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 3124 dated 10-08-2006 issued under sub section (I) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published in the Gazette of India dated 12-08-2006, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule for Tehsil, Kalol. District Panchmahal in the State of Gujarat for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam by Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas. the copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 26-09-2006 ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (I) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government ;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that right of user in the land specified in the schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of the publication of this declaration in Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Schedule

Tehsil:-Kalol	Dist:-Panchmahal		State:-Gujarat		
Name of village	Survey/Block No.	Sub - Division No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Vyasda	1194		0	07	25

[F. No. R-25011/7/2006-O.R.-I]
S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

का. आ. 1050.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 12-08-2006 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. 3125 तारीख 10-08-2006 द्वारा अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची तालुका घोघंढा जिला. पंचमहाल, राज्य गुजरात में विनिर्दिष्ट भूमि में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन खिड़ाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 26-09-2006 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए ;

अतः : अद्ध केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन खिड़ाने के लिए इस अधिसूचना से उपाद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के खजाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सभी विल्लगमों से मुक्त होकर प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

तालुका : घोघम्बा	जिला : पंचमहाल		राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण नं.-खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
दामावाव	37		0	31	45

[फा. सं. आर-25011/7/2006-ओ.आर.-1]

एच. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd April, 2007

S. O. 1050.— Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 3125 dated 10-08-2006 issued under sub section (I) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published in the Gazette of India dated 12-08-2006, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule for Tehsil, Ghoghmba District Panchmahal in the State of Gujarat for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam by Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 26-08-2006 ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (I) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government ;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that right of user in the land specified in the schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of the publication of this declaration in Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Schedule

Tehsil:-Ghoghamba	Dist:-Panchmahal		State:-Gujarat		
Name of village	Survey/Block No.	Sub - Division No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Damavav	37		0	31	45

[F. No. R-25011/7/2006-O.R.-I]

S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2007

का. आ. 1051.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 12-08-2006 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. 3117 तारीख 04-08-2006 द्वारा अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची तालुका वडोदरा जिला. वडोदरा राज्य गुजरात में विनिर्दिष्ट भूमि में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 26-09-2006 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूचीमें विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सभी विल्लगमों से मुक्त होकर प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

तालुका : वडोदरा	जिला : वडोदरा		राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं-खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
आसोज	175		0	17	25

[फा. सं. आर 25011/5/2006-ओ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th April, 2007

S. O. 1051.— Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 3117 dated 04-08-2006 issued under sub section (I) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) published in the Gazette of India dated 12-08-2006 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule for Tehsil : Vadodara, District Vadodara in the State of Gujarat for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam by Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 26-09-2006 ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (I) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government ;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that right of user in the land specified in the schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of the publication of this declaration in Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Schedule

Tehsil:-Vadodara	Dist:-Vadodara		State:-Gujarat		
Name of village	Survey/Block No.	Sub - Division No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Asoj	175		0	17	25

[F. No. R-25011/5/2006-O.R.-I]

S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2007

का. आ. 1052.— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 12-08-2006 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. 3118 तारीख 04-08-2006 द्वारा अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची तालुका सावली जिला, खडोदरा राज्य गुजरात में विनिर्दिष्ट भूमि में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 26-09-2006 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सभी विल्लगनों से मुक्त होकर प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

तालुका :सावली	जिला : वडोदरा		राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं-खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
इन्द्राल	1239		0	06	94
खाखरीया	114	106	0	08	85
सींगानीया	31	1	0	09	12

[फा. सं. आर-25011/5/2006-ओ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th April, 2007

S. O. 1052.—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 3118 dated 04-08-2006 issued under sub section (I) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1967 (50 of 1962) published in the Gazette of India dated 12-08-2006 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule for Tehsil : Savali, District Vadodara in the State of Gujarat for the purpose of laying pipeline for transportation of Petroleum Products from Kargali to Ratlam by Indian Oil Corporation Limited ;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 26-09-2006 ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (I) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government ;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that right of user in the land specified in the schedule appended to this notification should be acquired ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of the publication of this declaration in Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Schedule

Tehsil:-Savli	Dist:-Vadodara		State:-Gujarat		
Name of village	Survey/Block No.	Sub - Division No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Indral	1239		0	06	94
Khakhariya	114	10P6	0	08	85
Singaniya	31	1	0	09	12

[F. No. R-25011/5/2006-O.R.-I]

S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2007

का. आ. 1053.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के का. आ. 1293 दिनांक 31.05.2004 द्वारा पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित कर, पारादीप-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना हेतु कच्चे तेल परिवहन करने के प्रयोजन के लिये उड़ीसा राज्य के पारादीप से पश्चिम बंगाल राज्य के हल्दिया तक पाइपलाइन बिछाने हेतु उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट जिला : भद्रक उड़ीसा की भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त अधिसूचना की प्रतियों जनता को उपलब्ध करा दी गई थी :

और उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संबन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिसूचना की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

जिल्हा: भद्रक

राज्य : उड़ीसा

तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
बासुदेबपुर	सुखदेबपुर	33	0	03	83
		37	0	02	34
	सुंगुडा	698	0	06	41
	गुआगन	1535	0	03	03
		1454	0	05	18

[फा. सं. सं. 25011/11/2004-आ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 9th April, 2007

S. O. 1053.— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.1293 dated 31.05.2004 issued under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land in District: Bhadrak, in Orissa State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Crude Oil from Paradip in the State of Orissa to Haldia in the State of West Bengal by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the Paradip Haldia Crude Oil Pipeline Project.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted his report to the Central Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this Notification;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline:

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6, Central Government directs the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest on date of publication of this declaration, in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

Schedule**Dist: Bhadrak****State : Orissa**

Name of Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Basudevpur	Sukdevpur	33	0	03	83
		37	0	02	34
	Sungura	698	0	06	41
	Guagan	1535	0	03	03
		1454	0	05	18

[F. No. R-25011/11/2004-O.R.-I]
S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2007

का. आ. 1054.—केन्द्रीय सरकार को, लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उड़ीसा राज्य पारादीप से पश्चिम बंगाल राज्य में हल्दिया तक कच्चे तेल के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है की ऐसी भूमि जिसके भीतर पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संबंधित अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खानेज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर उपयोग के अधिकार के अर्जन या भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाने के विरोध में श्री. सुकान्त कुमार प्रधान सक्षम प्राधिकारी, पारादीप हल्दिया कृड ऑयल पाइपलाइन परियोजना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मेघदम्बारा, डाकघर - कुरुदा, बालासोर-756056 (उड़ीसा) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला : बालेश्वर

राज्य : उड़ीसा

तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
सोरो	गुड़	1652	00	03	88
		1642	00	00	47
		2628	00	01	42
		676	00	03	22
		95	00	00	71
		626	00	00	38
		1651	00	00	15
		1469	00	00	11
		52	00	00	24
		223	00	01	02
	पाटीमुन्डा	198	00	01	12
		223	00	01	02
	दिनापाही	198	00	01	12
		223	00	01	02
	ब्रह्मपुर	98	00	04	55
		152	00	00	40
		413	00	00	60
		469	00	03	00
		414	00	00	53
		523	00	00	49
	अन्जी	2242	00	00	11
		2407	00	00	10
		2402	00	00	10
		2352	00	04	65
		2236	00	00	47
		2237	00	01	24
	कान्हेओगालपुर	2368	00	00	22
		2245	00	00	75
		853	00	04	77
		1957	00	07	45
	करन्जाबीनधा	1702	00	03	38
		1703	00	06	94
		834	00	02	78
	डोलपुर	834	00	02	78

1	2	3	4	5	6
	फतेहपुर	908	00	07	76
बालेश्वर मण्डल	श्रीजन्ग	4911	00	02	73
	चान्दिपुर	347	00	00	10
	साहाजानगर	9	00	00	80
		23	00	01	95
	गुड्डा	5774	00	11	94
		2254	00	08	00
	हिरीगान	1724	00	07	95
		1719	00	04	64
		1722	00	03	02
	पात्रापाडा	742	00	01	73
		755	00	00	18
	पाखराबाद	831	00	00	10
बस्ता	कडामीदा	463	00	01	89
		431	00	09	64
	गोठोगडिया	328	00	01	51
	बरखुदी	1042	00	07	24
	पोरापाडा	183	00	04	31
		155	00	09	00
		176	00	01	19
		173	00	01	42
		167	00	02	07
	धनाहांडा	29	00	00	80
	दराडा	3108	00	00	10
	दान्डि	93	00	04	93
	बालिसाहि	2267	00	06	85
	गुहालिपडा	480	00	06	35
		478	00	03	67
		474	00	01	35
		468	00	01	39
	अछुयापडा	338	00	00	97
		341	00	02	76
		343	00	05	60
		235	00	00	65
	पथदुर्गा	1305	00	00	47

1	2	3	4	5	6
	त्रैलोकी	356	00	01	31
		325	00	06	50
बालियापाल	रेमु	777	00	00	64
		1526	00	00	10
		1533	00	00	32
		1994	00	01	59
		1564	00	12	02
	धानंदा	335	00	00	24
		336	00	01	16
		260	00	01	34
		338	00	01	77
	निखीरा	1124	00	00	20
		1285	00	00	80
		1187	00	01	00
		1188	00	00	80
		1190	00	00	60
		1193	00	00	51
		2641	00	01	11
		2642	00	01	00
		1280	00	01	22
		1288	00	02	30
		1093	00	01	84
		990	00	01	70
	पालपडा	567	00	00	42
		568	00	03	90
		569	00	00	39
		571	00	00	83
		415	00	00	59
		240	00	00	10
		208	00	02	59
		209	00	02	19
		532	00	02	15
		534	00	00	91
		533	00	06	15
		536	00	04	31

1	2	3	4	5	6
		556	00	03	08
		572	00	01	38
		562	00	03	74
		223	00	00	41
		2344	00	04	11
		787	00	01	72
		1526	00	02	98
		2343	00	01	42
	दखिनपडा	757	00	04	34
जलेश्वर	खालब्रडिया	859	00	00	10
		896	00	01	10
		256	00	00	72
		897	00	03	22
		229	00	00	78
		223	00	03	44
	कसिदा	1167	00	02	28
		1248	00	02	35
		1169	00	03	25
		1184	00	04	48
		1200	00	00	10
		1246	00	00	10
		1182	00	02	59
		1172	00	02	08
		1719	00	03	12
		1174	00	02	37
		1249	00	02	63
		1745	00	03	00
	गौरीबेलदा	544	00	00	17
		524	00	00	10
		525	00	02	21
	घांटियाडी	72	00	01	52
		541	00	01	60
		852	00	01	44
	नुआपली	1623	00	06	82
		1670	00	00	34

1	2	3	4	5	6
	नाचिदा	2408	00	05	41
		1917	00	00	48
		1928	00	02	17
		1837	00	08	35
	देनुअरा	191	00	00	10
		706	00	00	10
		862	00	01	68
	गाबगाँ	1912	00	03	57
		606	00	00	15
		604	00	03	43
		565	00	00	35
		577	00	03	42
		611	00	01	24
		578	00	01	95
		601	00	04	79
		580	00	01	48
		579	00	07	76
		605	00	02	36
		576	00	02	52
		2202	00	02	02
		575	00	02	10
	अलालबिंदा	1931	00	05	86
	रायपुर	1166	00	10	02
	बटग्राम	3388	00	01	68
	कटीसाही	2298	00	03	00
	मोहन्दराजपुर	181	00	00	10
	कुलिदा	1617	00	06	42
		2277	00	00	60
	बलरामपुर	499	00	00	10

[फा. सं. आर-25011/19/2004-ओ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 10th April, 2007

s. o. 1054.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of crude oil from Paradip in the State of Orissa to Haldia in the State of West Bengal, a pipeline should be laid by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the Schedule annexed to this notification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act- 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein under the land to Shri. Sukanta Kumar Pradhan, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Paradip - Haldia Pipeline Project, Indian Oil Corporation Limited, Marketing Housing Complex, Meghadambaru, Post office- Kuruda, Balasore (Orissa).

Schedule					
District :Balasore			State :Orissa		
Name of Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Soro	Gud	1652	00	03	88
		1642	00	00	47
		2628	00	01	42
		676	00	03	22
		95	00	00	71
		626	00	00	38
		1651	00	00	15
		1469	00	00	11
	Patimunda	52	00	00	24
	Dinapahi	223	00	01	02
Brahampur		198	00	01	12
		98	00	04	55
		152	00	00	40
		413	00	00	60

1	2	3	4	5	6
		469	00	03	00
		414	00	00	53
		523	00	00	49
	Anjee	2242	00	00	11
		2407	00	00	10
		2402	00	00	10
		2352	00	04	65
		2236	00	00	47
		2237	00	01	24
		2368	00	00	22
		2245	00	00	75
	Kanheiogolpur	853	00	04	77
	Karanjabindha	1957	00	07	45
		1702	00	03	38
		1703	00	06	94
	Dolpur	834	00	02	78
	Fatehpur	908	00	07	76
Balasore sadar	Srijang	4911	00	02	73
	Chandipur	347	00	00	10
	Sahajanagar	9	00	00	80
		23	00	01	95
	Gudu	5774	00	11	94
		2254	00	08	00
	Hirigan	1724	00	07	95
		1719	00	04	64
		1722	00	03	02
	Patrapada	742	00	01	73
		755	00	00	18
	Pakhrabar	831	00	00	10
Basta	Kadamouda	463	00	01	89
		431	00	09	64
	Gothagaria	328	00	01	51
	Barakhudi	1042	00	07	24
	Porapara	183	00	04	31
		155	00	09	00
		176	00	01	19
		173	00	01	42

1	2	3	4	5	6
		167	00	02	07
	Dhanhanda	29	00	00	80
	Darada	3108	00	00	10
	Dandi	93	00	04	93
	Balisahi	2267	00	06	85
	Guhali pada	480	00	06	35
		478	00	03	67
		474	00	01	35
		468	00	01	39
	Achhuapada	338	00	00	97
		341	00	02	76
		343	00	05	60
		295	00	00	65
	Pathadurga	1305	00	00	47
	Trailoki	356	00	01	31
		325	00	06	50
Baliapal	Remu	777	00	00	64
		1526	00	00	10
		1533	00	00	32
		1994	00	01	59
		1564	00	12	02
	Dhanda	335	00	00	24
		336	00	01	16
		260	00	01	34
		338	00	01	77
	Nikhira	1124	00	00	20
		1285	00	00	80
		1187	00	01	00
		1188	00	00	80
		1190	00	00	60
		1193	00	00	51
		2641	00	01	11
		2642	00	01	00
		1280	00	01	22
		1286	00	02	30
		1093	00	01	84
		990	00	01	70

1	2	3	4	5	6
	Paipada	567	00	00	42
		568	00	03	90
		569	00	00	39
		571	00	00	83
		415	00	00	59
		240	00	00	10
		208	00	02	59
		209	00	02	19
		532	00	02	15
		534	00	00	91
		533	00	06	15
		536	00	04	31
		556	00	03	08
		572	00	01	38
		562	00	03	74
		223	00	00	41
		2344	00	04	11
		787	00	01	72
		1526	00	02	98
		2343	00	01	42
	Dakhinpada	757	00	04	34
Jaleswar	Khalabaria	859	00	00	10
		896	00	01	10
		256	00	00	72
		897	00	03	22
		229	00	00	78
		223	00	03	44
	Kasida	1167	00	02	28
		1248	00	02	35
		1169	00	03	25
		1184	00	04	48
		1200	00	00	10
		1246	00	00	10
		1182	00	02	59
		1172	00	02	08
		1719	00	03	12
		1174	00	02	37

1	2	3	4	5	6
		1249	00	02	63
		1745	00	03	00
	Gauribelda	544	00	00	17
		524	00	00	10
		525	00	02	21
	Ghantiari	72	00	01	52
		541	00	01	60
		852	00	01	44
	Nuapali	1623	00	06	82
		1670	00	00	34
	Nachinda	2408	00	05	41
		1917	00	00	48
		1928	00	02	17
		1837	00	08	35
	Denuara	191	00	00	10
		706	00	00	10
		862	00	01	68
	Gabagan	1912	00	03	57
		606	00	00	15
		604	00	03	43
		565	00	00	35
		577	00	03	42
		611	00	01	24
		578	00	01	95
		601	00	04	79
		580	00	01	48
		579	00	07	76
		605	00	02	36
		576	00	02	52
		2202	00	02	02
		575	00	02	10
	Alalbindha	1931	00	05	86
	Raipur	1166	00	10	02
	Batgram	3388	00	01	68
	Katisahi	2298	00	03	00

1	2	3	4	5	6
	Mohamadrajpur	181	00	00	10
	Kulida	1617	00	06	42
		2277	00	00	60
	Balrampur	499	00	00	10

[F. No. R-25011/19/2004-O.R.-I]
S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2007

का. आ. 1055.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3491 तारीख 31 अगस्त 2006 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के गोवा में उत्तरी/दक्षिणी अपतट में खोज ब्लॉकों और आन्ध्रप्रदेश में संरचनाओं से महाराष्ट्र राज्य में पूर्ण जिले के विभिन्न उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख 11 दिसम्बर 2006 को या उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थी;

और पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुक : खेड		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र		
गांव का नाम	गट नंबर / सब डिविजन नं.	आर ओ यु अंजित करने के लिये क्षेत्रफल				
		हेक्टेयर	एयर	सी-एयर		
1	2	3	4	5		
1) सावळेवाडी	11	00	04	80		
	35	00	00	50		
	210	00	09	10		
	221	00	33	11		
2) बुहुळ	233	00	09	00		
	415	00	11	40		
	1052	00	09	00		
	1058	00	11	73		
	74	00	42	57		
	1057	00	04	00		
	273	00	19	40		
	77	00	20	63		
	1049	00	17	83		
3) पिंपळगांव तर्फ खेड	1865	00	32	56		
	360	00	09	93		
	357	00	35	99		
	387	00	06	00		
	256	00	06	86		
4) काकूस	1141	00	27	53		
	524	00	12	30		
	52	00	17	96		
	1709	00	11	85		
	1985	00	08	46		
	1026	00	19	48		
	864	00	02	95		
5) बाकी बुहुळ	नाला	00	06	60		
	400	00	15	00		
	695	00	01	00		
	629	00	07	98		
	394	00	02	47		
	615	00	05	00		
6) आंबेठाण	686	00	03	00		
मंडल : मायळ	जिला : पुणे	राज्य : महाराष्ट्र				
1) बादलवाडी	516	00	14	42		
	514	00	18	03		
2) नवलाक उम्मे	720	00	02	40		
	465	02	32	36		
3) पवलेवाडी	9	01	01	82		

1	2	3	4	5
4) मालेगाव बुद्रुक	165	00	38	30
5) सावळे	सर्वे नंबर 87/12 और 120/अ में रास्ता 97/4	00 00	03 36	57 00

[फा. सं. एल-14014/52/2006-जी. पी.]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

New Delhi, the 9th April, 2007

S. O. 1055.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 3491 dated the 31st August 2006, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas from the exploration blocks in the Northern / Southern offshore of Goa and structures in Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited by M/s. Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to various consumers of Distric Pune in the State of Maharashtra;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 08 before the 11th December 2006;

And whereas no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired, for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Central Government, vest, on this date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, free from all encumbrances.

Schedule

Mandal/Thesi/Taluk: Khed		District: Pune		State : Maharashtra	
Village	Survey No./Sub-division No.	Area to be acquired for ROU			
		Hectare	Are	C-Are	
1	2	3	4	5	
1) Sablewadi.	11	00	04	80	
	35	00	00	50	
	210	00	09	10	
	221	00	33	11	
2) Bahul	233	00	09	00	
	415	00	11	40	
	1052	00	09	00	
	1058	00	11	73	
	74	00	42	57	
	1057	00	04	00	
	273	00	19	40	
	77	00	20	63	
	1049	00	17	83	
3) Pimpalgaon tarf Khed	1865	00	32	56	
	360	00	09	93	
	357	00	35	99	
	387	00	06	00	
	256	00	06	86	
4) Kalus	1141	00	27	53	
	524	00	12	30	
	52	00	17	96	
	1709	00	11	85	
	1985	00	08	46	
	1026	00	19	48	
	864	00	02	95	
5) Waki budurk	Nala	00	06	60	
	400	00	15	00	
	695	00	01	00	
	629	00	07	98	
	394	00	02	47	
	615	00	05	00	
6) Ambethan	686	00	03	00	
Mandal : Maval		District: Pune		State : Maharashtra	
1) Badalwadi	516	00	14	42	
	514	00	18	03	
2) Navalakh-Umbre	720	00	02	40	
	465	02	32	36	
3) Pawalewadi	9	01	01	92	

1	2	3	4	5
4) Malegaon- budruk	165	00	38	30
5) Savle	Road between Survery No. 87/12 and 120/A	00	03	57
	97/4	00	36	00

[F. No. L-14014/52/2006-G.P.]

S. B. MANDAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2007

क्रा. आ. 1056.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3489 तारीख 31 अगस्त 2006 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के गोवा में उत्तरी/ दक्षिणी अपनट में खोज ब्लॉकों और आन्ध्रप्रदेश में संरचनाओं से महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के विभिन्न उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के लिए अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख 11 दिसम्बर 2006 को व उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थी;

और पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुक : शिरूर		जिला : पुणे		राज्य : महाराष्ट्र	
गांव का नाम	सर्वे नंबर / गट नंबर	आर ओ यु अर्जित करने के लिये क्षेत्रफल			
		हेक्टेयर	एयर	सी एयर	
1	2	3	4	5	
1) इनामगाव	58	00	11	81	
	539	00	02	00	
2) पिंपळसुटी	311	00	09	02	
	128	00	14	94	
	76/1अ/1	00	07	02	
	40/3	00	05	00	
	243/2/1	00	07	23	
3) शिरसगांव काटा	243	00	08	00	
	119/1	00	18	30	
	403	00	32	01	
	151	00	37	59	
4) कोळगाव डोळस	161/1अ	00	06	11	
5) काकडेवाडी	294	00	12	50	
6) न्हावरे	794	00	33	13	
	806	00	10	43	
	808	00	06	49	
	809	00	08	55	
	810	00	09	91	
	811	00	03	76	
	812	00	10	26	
	814	00	05	81	
	815	00	04	10	
	816	00	05	47	
	818	00	04	96	
	819	00	06	49	
	820	00	08	55	
	821	00	22	96	
	453	00	09	60	
	456	00	12	50	
	459	00	08	70	
	460	00	02	10	
	461	00	04	50	
	462	00	04	20	
463	00	03	90		
464	00	10	06		
465	00	08	40		

1	2	3	4	5
6) न्हावरे (निरंतर)	466	00	04	45
	468	00	00	50
	776	00	07	80
	775	00	05	40
	774	00	06	30
	773	00	06	30
	772	00	08	68
	771	00	05	52
	769	00	04	60
	768	00	03	20
	767	00	02	73
	766	00	01	50
	765	00	01	80
	764	00	00	50
	763	00	00	50
	644	00	03	14
	643	00	30	00
7) उरळगाव	464	00	20	76
	177	00	20	36
	365	00	00	50
	109	00	00	50
	222	00	00	50
	217	00	12	03
8) दहिबडी	सर्वे नंबर 315 में नाला	00	06	44
	333	00	03	29
9) पारोडी	31	00	09	95
	30	00	00	50
10) शिवतक्रार म्हाळुंगी	72	00	06	49
11) टाकली भिमा	621	00	41	34
	795	00	02	00
	424	00	06	10
	423	00	03	70
	418	00	03	80
	417	00	05	00
	678	00	22	20
	672	00	06	00
	671	00	07	20
	674	00	19	36
	670	00	07	14
	669	00	00	50
	649	00	21	00

1	2	3	4	5
12) कासरी	690	00	02	60
13) तळेगाव डमढेरे	405	00	01	00
	408	00	00	50
	409	00	00	50
	410	00	01	50
	411	00	00	50
	416	00	03	90
	1805	00	62	34
14) शिक्रापुर	1304	00	15	53
	1592	00	00	76
	1677	00	19	20
	1678	00	07	80
	1288	00	03	00
	1289	00	06	45
	1292	00	03	00
	1607	00	06	10
	1606	00	03	50
	1608	00	03	19
	1609	00	03	30
	1610	00	01	70
	1611	00	01	30
	1614	00	07	20
	1615	00	08	20
	1616	00	08	00
	1619	00	02	40
	1620	00	02	70
	1621	00	04	30
	1625	00	01	30
	1626	00	01	30
	1627	00	08	00
	1628	00	04	70
	1629	00	06	20
	1630	00	04	20
	1631	00	02	00
	1632	00	01	30
	1633	00	02	00
	1634	00	02	00
	1635	00	02	40
	1636	00	02	30
	1637	00	17	00
	1638	00	06	00

1	2	3	4	5
14) शिक्रापुर (निरंतर)	1639	00	07	30
	1640	00	08	41
	1641	00	06	00
	1642	00	06	70
	1643	00	07	30
	1644	00	04	00
	1645	00	04	70
	1646	00	14	09
	1675	00	48	03
	1676	00	21	80
15) करंदी	694	00	20	16
	695	00	22	42
	691	00	63	73
16) वाजेवाडी	414	00	14	48
	411	00	23	60
	410	00	02	00
	367	00	03	00
	382	00	02	53
	354	00	06	00

[फा. सं. एल-14014/51/2006-जी. पी.]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

New Delhi, the 9th April, 2007

S. O. 1056.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 3489 dated the 31st August 2006, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas from the exploration blocks in the Northern / Southern offshore of Goa and structures in Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited by M/s. Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited to various consumers of Distric Pune in the State of Maharashtra;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 08 before the 11th December 2006;

And whereas no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired, for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Central Government, vest, on this date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, free from all encumbrances.

Schedule

Mandal/Thesi/Taluk: Shirur		District: Pune		State : Maharashtra	
Village	Survey/Gat No.	Area to be acquired for ROU			
		Hectare	Are	C-Are	
1	2	3	4	5	
1) Inamgaon	58	00	11	81	
	539	00	02	00	
2) Pimpalsuti	311	00	09	02	
	128	00	14	94	
	76/1A/1	00	07	02	
	40/3	00	05	00	
	243/2/1	00	07	23	
3) Shirasgaon Kata	243	00	08	00	
	119/1	00	18	30	
	403	00	32	01	
	151	00	37	59	
4) Kolagaon Dolas	161/1A	00	06	11	
5) Kakadewadi	294	00	12	50	
6) Nhavare	794	00	33	13	
	806	00	10	43	
	808	00	06	49	
	809	00	08	55	
	810	00	09	91	
	811	00	03	76	
	812	00	10	26	
	814	00	05	81	
	815	00	04	10	
	816	00	05	47	
	818	00	04	96	
	819	00	06	49	
	820	00	08	55	
	821	00	22	96	
	453	00	09	60	
	456	00	12	50	
	459	00	08	70	
	460	00	02	10	
	461	00	04	50	
	462	00	04	20	
	463	00	03	90	
	464	00	10	06	
	465	00	08	40	
	466	00	04	45	

1	2	3	4	5
6) Nhavare (Contd....)	468	00	00	50
	776	00	07	80
	775	00	05	40
	774	00	06	30
	773	00	06	30
	772	00	08	68
	771	00	05	52
	769	00	04	60
	768	00	03	20
	767	00	02	73
	766	00	01	50
	765	00	01	80
	764	00	00	50
	763	00	00	50
	644	00	03	14
	643	00	30	00
7) Uralgaon	464	00	20	76
	177	00	20	36
	365	00	00	50
	109	00	00	50
	222	00	00	50
	217	00	12	03
8) Dahiwadi	Nala between Survey No. 315	00	06	44
	333	00	03	29
9) Parodi	31	00	09	95
	30	00	00	50
10) Shiv takrar Mahalungi	72	00	06	49
11) Takli Bhima	621	00	41	34
	795	00	02	00
	424	00	06	10
	423	00	03	70
	418	00	03	80
	417	00	05	00
	678	00	22	20
	672	00	06	00
	671	00	07	20
	674	00	19	36
	670	00	07	14
	669	00	00	50
	649	00	21	00
12) Kasari	690	00	02	60

1	2	3	4	5
13) Talegaon Dhamdhere	405	00	01	00
	408	00	00	50
	409	00	00	50
	410	00	01	50
	411	00	00	50
	416	00	03	90
	1805	00	62	34
14) Shikrapur	1304	00	15	53
	1592	00	00	76
	1677	00	19	20
	1678	00	07	80
	1288	00	03	00
	1289	00	06	45
	1292	00	03	00
	1607	00	06	10
	1606	00	03	50
	1608	00	03	19
	1609	00	03	30
	1610	00	01	70
	1611	00	01	30
	1614	00	07	20
	1615	00	08	20
	1616	00	08	00
	1619	00	02	40
	1620	00	02	70
	1621	00	04	30
	1625	00	01	30
	1626	00	01	30
	1627	00	08	00
	1628	00	04	70
	1629	00	06	20
	1630	00	04	20
	1631	00	02	00
	1632	00	01	30
	1633	00	02	00
	1634	00	02	00
	1635	00	02	40
	1636	00	02	30
	1637	00	17	00
	1638	00	06	00
	1639	00	07	30

1	2	3	4	5
14) Shikrapur (Contd....)	1640	00	08	41
	1641	00	06	00
	1642	00	06	70
	1643	00	07	30
	1644	00	04	00
	1645	00	04	70
	1646	00	14	09
	1675	00	48	03
	1676	00	21	80
15) Karandi	694	00	20	16
	695	00	22	42
	691	00	63	73
16) Wajewadi	414	00	14	48
	411	00	23	60
	410	00	02	00
	367	00	03	00
	382	00	02	53
	354	00	06	00

[F. No. L-14014/51/2006-G.P.]
S. B. MANDAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2007

का. आ. 1057.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1594 (इ) तारीख 25 सितम्बर 2006 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के गोवा में उत्तरी/दक्षिणी अपतट में खोज ब्लॉकों और आन्ध्रप्रदेश में संरचनाओं से महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले के विभिन्न उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख 09 अक्टूबर 2006 को व उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थी;

और पाइपलाइन बिछाने के संबंध में जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगों से मुक्त, मैसर्स रिलायन्स गैस ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल : कर्जत		जिला : अहमदनगर		राज्य : महाराष्ट्र	
गाँव का नाम	सर्वे नंबर / गट नंबर	आर ओ यु अंजित करने के लिये क्षेत्रफल			
		हेक्टेयर	एकर	सि-एकर	
1	2	3	4	5	
1) राक्षसवाडी बुद्रुक	424	00	73	20	
	425	00	26	40	
	428	00	10	80	
	427	00	21	00	
	410	00	16	20	
	409	00	81	60	
	407	00	64	80	
	406	00	01	00	
	400	00	38	40	
	401	00	20	48	
	402	00	31	20	
	403	00	40	80	

[फा. सं. एल-14014/6/2006-जी. पी.]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

New Delhi, the 9th April, 2007

S. O. 1057.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 1594(E) dated the 25th September 2006, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas from the exploration blocks in the Northern / Southern offshore of Goa and structures in Andhra Pradesh of M/s Reliance Industries Limited, to various consumers of District Ahmednagar in the State of Maharashtra by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before the 09th October 2006;

And whereas no objections from the public to the laying of the pipeline have been received;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired, for laying the pipeline:

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Central Government, vest, on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited, free from all encumbrances.

Schedule

Mandal : Karjat		District: Ahmednagar		State : Maharashtra	
Village	Survey No/Gat No.	Area to be acquired for ROU			
		Hectare	Are	C-Are	
1	2	3	4	5	
Rakshwadi Budruk	424	00	73	20	
	425	00	26	40	
	428	00	10	80	
	427	00	21	00	
	410	00	16	20	
	409	00	81	60	
	407	00	64	80	
	406	00	01	00	
	400	00	38	40	
	401	00	20	48	
	402	00	31	20	
	403	00	40	80	

[F. No. L-14014/6/2006-G.P.]
S. B. MANDAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2007

स. आ. 1058.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में टेप ऑफ पोइंट गवासद से मैसर्स सौराष्ट्र सोलिड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, गवासद पाइपलाइन परियोजना द्वारा प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, श्री एस.के. राठौड़, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, इच्छापुर-मगदल्ला रोड, पुरानी कॉलोनी, ओ.एन.जी.सी. सर्कल के पास, हजीरा, सुरत (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	गाँव	सर्वे न.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
वडोदरा	पादरा	गवासद	132 अ	0-05-85
			130	0-02-00
			कारटेक	0-02-85
			सौराष्ट्र सोलिड	0-00-71
			कुल	0-11-81

[फा. सं. एल-14014/50/2006-जी. पी.]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

New Delhi, the 9th April, 2007

S. O. 1058.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of natural gas through Tap off Point Gavasad to M/s. Saurashtra Solid Industries Pvt Ltd., Gavasad pipeline project in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Shri S.K. Rathod, Competent Authority, GAIL (India) Limited, Ichhapore-Magdalla Road, Old Colony, Near ONGC Circle, Hazira, Surat (Gujarat).

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Survey No.	Area to be acquired for ROU (In Hectare)
Vadodara	Padra	Gavasad	132/A	0-05-85
			130	0-02-00
			Car Tak	0-02-85
			Saurashtra Solid	0-00-71
			Total	0-11-81

[F. No. L-14014/50/2006-G.P.]
S. B. MANDAL, Under Secy.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1059.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक विभाग के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय, सांगली के पंचाट (संदर्भ संख्या 1/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/92/2005-आई आर (डी. यू.)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1059.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1/2006) of the Labour Court, Sangli as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Post and their workman, which was received by the Central Government on 20-03-2007.

[No. L-40012/92/2005-IR(DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

ANNEXURE

Received on : 6-1-2006

Registered on : 6-1-2006

Decided on : 7-3-2007

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, LABOUR COURT AT SANGLI

Ref. (IDA) No. 1/2006

BETWEEN:

The Assistant Superintendent of Post Office,
Sangli Sub-Division,
Sangli-416416 (Maharashtra) ... 1st Party

AND

Shri Rajesh Sadamate,
A/P. Burli, Tal. : Palus,
Dist. Sangli (Maharashtra)
Pin Code-416308 ... 2nd Party

**In the matter of reinstatement with continuity of service
and full back wages**

CORAM:

Shri M. V. Morale, Presiding Officer

APPEARANCES:

1st Party in person : Absent

2nd Party in person : Absent

AWARD

(Delivered on 7-3-2007)

The Desk Officer, Government of India, Ministry of Labour has forwarded this reference under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947) for adjudication over the following demand of the 2nd Party.

"Whether the action of the management of Post Office, Sangli in terminating the services of Shri Rajesh Sadamate w.e.f. 27-2-2002 is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from which date ?"

2. The notice to 2nd party was issued to file Statement of Claim on 22-2-2006 as also notice to 1st party was issued for filing Written Statement on 22-3-2006. The notices at Exs. O-2 and O-3 were duly served on both parties, but parties remained absent. Record shows that the 2nd party and concerned are also absent on several dates and today also. Nobody present for them till 4.30 p.m.

3. Without Statement of Claim, I can't adjudicate the dispute. Hence, I have no other alternative to pass the following order :

ORDER

(1) Reference of 2nd party is hereby rejected.

(2) No order as to cost.

Sangli

Date : 7-3-2007

M. V. MORALE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1060.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी. पी. डब्लू. डी. के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ सं. 133/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/19/2005-आई आर (सी.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1060.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 133/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation

to the management of CPWD and their workman, which was received by the Central Government on 20-3-2007.

[No. L-42012/19/2005-IR(C-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT-II, NEW DELHI

I. D. No. 133/2005

Shri R. N. Rai, Presiding Officer

In the matter of:

Shri Babu Lal,
S/o. Shri Mool Chand, Beldar,
Through All India CPWD (MRM) Karamchari
Sangathan, (Regd.) 4823, Balbir Nagar Extension,
Gali No. 13, Shahdra,
Delhi

Versus

The Executive Engineer,
Parliament Works Division-I,
C. P. W. D., I. P. Bhawan,
New Delhi

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-42012/19/2005 [IR (CM-II)], Central Government, dt. 14-12-2005 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder:

“Whether the demand of the All India CPWD (MRM) Karamchari Sangh in respect of Shri Chandra Mohan, Ex. Beldar to receive benefits of pay scale of Rs. 950-1500 w.e.f. 1-4-1991 and Rs. 3050-4590 w.e.f. 1-1-1996 on in-situ promotion is just fair and legal? If yes, to what relief the workman is entitled and from which date?”

It transpires from perusal of the order sheet that this reference was received on 14-12-2005. The workman was present on 4-7-2006. He has not filed claim statement till date. Last opportunity has been given twice. On 1-3-2007 opportunity for filing claim was closed.

No dispute award is given.

Date: 5-3-2000.

R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1061.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी. पी. डब्ल्यू. डी. के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच,

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ सं: 59/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/168/2004-आई आर (सी.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1061.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 59/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CPWD and their workman, which was received by the Central Government on 20-3-2007.

[No. L-42012/168/2004-IR(C-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT-II, NEW DELHI

I. D. No. 59/2005

Shri R. N. Rai, Presiding Officer.

In the matter of:

Shri Babu Lal,
C/o All India CPWD (MRM) Karamchari
Sanghathan (Regd.);
H. No. 4, Gali No. 1,
Karkardooma Village,
Delhi-110092

Versus

1. The Director General of Works,
CPWD,
Nirman Bhawan,
New Delhi-110011
2. The Executive Engineer,
Parliament Works Division-I,
CPWD, I. P. Bhawan,
New Delhi

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-42012/168/2004 [IR (CM-II)], Central Government, dt. 29-6-2005 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder:

“Whether the action of the Director General of Works, CPWD, Nirman Bhawan, New Delhi/the Executive Engineer, Parliament Works Division No. 1, CPWD, O. P. Bhawan, New Delhi in not granting ACP to

Shri Babu Lal and Shri Chander Mohan, Beldar respectively w.e.f. 9-8-1999 is legal and justified? If not, to what benefits the workmen are entitled and what directions are necessary in the matter.”

It transpires from perusal of the order sheet that the reference was received on 3-11-2005. Several opportunities have been given. Notice has also been served on the workman. Copy of the reference has been given to the workman by the Desk Officer also. No claim has been filed.

No dispute award is given.

Date : 6-3-2007.

R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1062.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी. पी. डब्ल्यू. डी. के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ सं. 131/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/20/2005-आई आर (सी.-II)]
अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1062.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 131/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CPWD and their workman, which was received by the Central Government on 20-3-2007.

[No. L-42012/20/2005-IR(C-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT-II, NEW DELHI

I. D. No. 131/2005

Shri R. N. Rai, Presiding Officer.

In the matter of :

Shri Chandra Mohan,
Through All India CPWD (MRM) Karamchari
Sanghathan, (Regd.)
4823, Balbir Nagar Extension,
Gali No. 13, Shahdra,
Delhi.

Versus

The Executive Engineer,
Parliament Works Division-I,
C. P. W. D., I. P. Bhawan,
New Delhi.

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-42012/20/2005 [IR (C-II)], Central Government, dt. 14-12-2005 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder :

“Whether the demand of the All India CPWD (MRM) Karamchari Sangh in respect of Shri Chandra Mohan, Ex. Beldar to receive benefits of pay scale of Rs. 950-1500 w.e.f. 1-4-1991 and Rs. 3050-4590 w.e.f. 1-1-1996 on in-situ promotion is just, fair and legal? If yes, to what relief the workman is entitled and from which date?”

It transpires from perusal of the order sheet that this reference was received on 14-12-2005. The workman was present on 4-7-2006. He has not filed claim statement till date. Last opportunity has been given twice. On 1-3-2007 opportunity for filing claim was closed.

No dispute award is given.

Date : 5-3-2007.

R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1063.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी. पी. डब्ल्यू. डी. के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ सं. 145/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/234/2003-आई आर (सी.-II)]
अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1063.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 145/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CPWD and their workman, which was received by the Central Government on 20-3-2007.

[No. L-42012/234/2003-IR(C-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT-II, NEW DELHI****I. D. No. 145/2004**

Shri R. N. Rai, Presiding Officer.

In the matter of :

The President,
All India CPWD Karamchhari Union,
Plot No. 1, Udaseen Mandir,
Aram Bagh, Paharganj,
New Delhi-110055.

Versus

The Executive Engineer, T-Division,
C. P. W. D.,
Sarojini Nagar,
New Delhi.

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-42012/234/2003 [IR (C-II)], Central Government, dt. 19-8-2004 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder :

"Whether the contract between the management of CPWD and their contractor is sham and whether the demand of CPWD Karamchhari Union for regularization of the services of Shri Omi and 20 others in the organization of CPWD is legal and justified ? If yes, to what relief they are entitled ?"

It transpires from perusal of the order sheet that the workmen were directed on 6-7-2006 to file rejoinder and affidavit on 14-8-2006. The workmen did not file rejoinder and affidavit on 21-9-2006, 26-10-2006, 11-12-2006, 8-2-2007 and 5-3-2007. Opportunity for filing rejoinder and affidavit was closed on 5-3-2007:

No dispute award is given.

Date: 7-3-2007.

R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1064.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी. पी. डब्ल्यू. डी. के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ सं. 130/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/18/2005-आई आर (सी.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1064.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 130/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CPWD and their workman, which was received by the Central Government on 20-3-2007.

[No. L-42012/18/2005-IR(C-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT-II, NEW DELHI****I. D. No. 130/2005**

Shri R. N. Rai, Presiding Officer.

In the matter of :

Shri Jagdish Kumar,
Through All India CPWD (MRM) Karamchhari
Sangathan, (Regd.),
4823, Balbir Nagar Extension,
Gali No. 13, Shahdra,
Delhi.

Versus

The Executive Engineer,
Parliament Works Division-I,
C. P. W. D.,
I. P. Bhawan,
New Delhi.

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-42012/18/2005 [IR (C-II)], Central Government, dt. 14-12-2005 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder :

"Whether the demand of the union in respect of the workman Shri Jagdish Kumar S/o Shri Jai Narayan, Plumber to grant pay scale of highly skilled category w.e.f. 1-1-1973 by the management of CPWD is just, fair and legal ? If yes, to what relief the workman is entitled and from which date ?"

It transpires from perusal of the order sheet that this reference was received on 14-12-2005. The workman was present on 4-7-2006. He has not filed claim statement till date. Last opportunity has been given twice. On 1-3-2007 opportunity for filing claim was closed.

No dispute award is given.

Date: 7-3-2007.

R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1065.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ. सी. आई. के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ सं. 77/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/330/2005-आई आर (सी.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1065.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 77/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of FCI and their workman, which was received by the Central Government on 20-3-2007.

[No. L-22012/330/2005-IR(C-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

I. D. No. 77/2006

Shri R. N. Rai, Presiding Officer.

In the matter of :

Shri Balwinder Singh,
S/o Shri Fakir.
Vill. : Gumthla Garhu,
Tehsil : Pehowa.
Kurukshetra (Haryana)

Versus

1. Sr. Regional Manager.
Food Corporation of India.
Sector : 17, Chandigarh,
Chandigarh
2. The District Manager.
Food Corporation of India.
Kurukshetra (Haryana).

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-22012/330/2005 [IR(C-II)], Central Government, dt. 5-9-2006 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder :

“Whether the action of the management of Food Corporation of India in terminating the services of

Shri Balwinder Singh S/o Shri Fakir, Labour Sardar w.e.f. 14-07-1999 is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?”

It transpires from perusal of the order sheet that this reference was received on 05-09-2006. Notice was sent to the workman. It has been received back un-served on the address as provided. The Desk Officer has also sent the copy of reference for appearance. No claim has been filed.

No dispute award is given.

Date : 07-03-2007.

R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1066.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. ई. सी. एल. के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 37/1992) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/397/1991-आई आर (सी.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1066.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 37/1992) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of SECL and their workman, which was received by the Central Government on 20-3-2007.

[No. L-22012/397/1991-IR(C-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

No. CGIT/LC/R/37/92

Shri C. M. Singh, Presiding Officer

The President,

M. P. Colliery Shramik Sabha,

P. O. Kotma Colliery,

Distt. Shahdol (M. P.)

... Workman/Union

Versus

The General Manager,

Jamuna and Kotma Area of SECL,

P. O. Jamuna Colliery,

Distt. Shahdol (M. P.)

... Management

AWARD

Passed on this 23rd day of February, 2007

1. The Government of India, Ministry of Labour vide its Notification No. L-22012/397/91-IR (C-II) dated 12-2-92 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal :—

“Whether the action of the General Manager, Jamuna and Kotma Areas of SECL, P. O. Jamuna Colliery, Distt. Shahdol (M. P.) in dismissing Shri N. Gopinathan, Store Keeper from company's services w.e.f. 21-7-1985 is legal and justified. If not to what relief is the workman entitled to?”

2. The case of workman Shri N. Gopinathan in brief is as follows. That he was a permanent employee of the management (Jamuna Collieries Stores, P. O. Jamuna, SECL). He was served with chargesheet issued by the Sub Area Manager, Jamuna Kotma Sub Area vide letter No. WCL/SAM/J & K/5942 dated 9-12-84 for the alleged misconduct for the charge of shortage of diesel 1502 Litres and Patrol 2,530 litres. The workman denied the charges levelled against him and submitted his explanation. An enquiry was conducted against him on the basis of which he was dismissed w.e.f. 21-7-85. The enquiry was not conducted legally and properly against him as the charges levelled against him were totally false and vague. It was conducted by the Enquiry Officer in gross violation of principle of natural justice and no opportunity of hearing was given to him. The findings of enquiry are perverse and contrary to the record. The chargesheet was issued to him without any basis. That considering the charges levelled against the workman, the punishment of dismissal imposed on him is very and harsh and has been imposed in order to harass him. It is prayed that the tribunal would be pleased to hold the enquiry proceedings and the dismissal order dated 21-7-85 is bad in law and direct the management to reinstate him with all consequential benefits.

3. The management filed their Written Statement. Their case in brief is as follows. That Shri N. Gopinathan was working as storekeeper in Jamuna Colliery Stores. During the period from 1-4-80 to December 1983, he was incharge of POL of Jamuna underground and Jamuna OCM. When the accounts of the aforesaid period was checked, a shortage of 2530 litres of petrol and 15021 litres of diesel was detected by the audit party. As the shortage occurred during the period when Shri Gopinathan was incharge of the POL, a chargesheet dated 9-12-84 was issued to him and it was alleged that he had committed the aforesaid act of commission and omission which amounted to misconduct. The workman submitted his reply to the aforesaid chargesheet and since the reply was not found to be satisfactory, a departmental enquiry was ordered and Shri S. P. Jaiswal, the then Sr. P. O. was appointed as Enquiry Officer to conduct DE into the charges against the workman.

The Enquiry Officer conducted a full and fair DE in which the workman participated. He was given full opportunity to defend himself. Therefore after concluding the enquiry, the Enquiry Officer gave his finding holding Shri Gupta guilty of charges levelled against him. On the basis of finding of guilt recorded by the Enquiry Officer, punishment of dismissal from service was imposed upon workman Shri Gopinathan. However if the tribunal comes to the conclusion that the enquiry has not been conducted properly, then the management seeks permission to prove the misconduct of the workman. That taking into consideration the gravity and seriousness of the misconduct committed by the workman, he is not a fit person to be retained in service. Dismissal from service is therefore, the only punishment. The punishment is just and proper and no interference is called for. It is prayed by the management that the reference be answered by holding that the action of the management is legal and proper and the workman concerned is not entitled to any relief whatsoever.

4. Vide order dated 19-9-05 of this tribunal, the following issues were framed upon the pleadings of the parties :—

- (i) Whether the Departmental Enquiry conducted by the management against the workman is proper and legal ?
- (ii) If the finding on issue No. 1 comes into negative, whether the management is entitled to prove the misconduct of the workman ?
- (iii) To what relief, if any, is the workman entitled ?

5. The management filed affidavit of their witness Shri S. P. Jaiswal, the then working as Sr. P. O. in SECL, Jamuna Kotma Area on preliminary issue No. 1.

6. In spite of sufficient service of notice, no body appeared for the workman to cross-examine management's witness Shri S. P. Jaiswal and to adduce evidence on behalf of workman/Union. Therefore the argument proceeded ex parte.

7. I have heard Shri A. K. Shashi, Advocate for the management. I have very carefully gone through the entire evidence on record.

8. The management's witness Shri S. P. Jaiswal stated on oath that the departmental enquiry was conducted against the workman properly and legally and the workman was provided with full opportunities to defend himself. I have very carefully gone through the original record of the enquiry submitted by the management which reveals that the enquiry was conducted properly and legally and the workman was given full opportunity to defend himself. The above evidence adduced by the management's witness Shri S. P. Jaiswal remained uncontroverted and unchallenged because no body put in appearance for the workman/Union. It is, therefore, concluded that the

Departmental Enquiry against the workman was conducted legally and properly. Issue No. 1 is, therefore, decided in the affirmative in favour of the management and against the workman.

9. In view of my findings on Issue No. 1, it is concluded that there is no need for the management to prove the misconduct of the workman. Issue No. 2 is decided accordingly in favour of the management and against the workman/Union.

10. Workman Shri N. Gopinathan was charged that during 1-4-80 to December 83, while he was incharge of POL, Jamuna UG and Jamuna O. C. M., the accounts of that period was checked and a shortage of 2530 litres of petrol and 15,021 litres of diesel was detected by the audit party. The said act of the workman constituted misconduct. This charge levelled against him as store keeper, Jamuna Colliery, Store was proved against him beyond any reasonable doubt. For the said misconduct, his services were terminated by the competent authority vide order dated 21-7-85. I am of the considered opinion that the punishment of dismissal is quite appropriate for the above charge of misconduct committed by the workman and therefore it is concluded that the action of General Manager, Jamuna and Kotma Areas of SECL, PO Jamuna Colliery, Distt. Shahdol (MP) in dismissing Shri N. Gopinathan, Store Keeper from company's services w.e.f. 21-7-1985 is legal and justified. The workman is not entitled to any relief. But having considered the facts and circumstances of this case, I am of the view that the parties be directed to bear their own costs of this reference.

11. In view of the above, it is hereby held that the action of the General Manager, Jamuna and Kotma Areas of SECL, PO Jamuna Colliery, Distt. Shahdol (MP) in dismissing Shri N. Gopinathan, Store Keeper from company's services w.e.f. 21-7-1985 is legal and justified and consequentially the workman is not entitled to any relief. The parties shall bear their own costs of this reference. The reference is answered accordingly in favour of the management and against the workman/Union.

12. Copy of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour as per rules.

C. M. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1067.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूरदर्शन केन्द्र के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. II, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 32/92) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-3-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/78/90-आई आर (डी यू)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1067.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 32/92) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. II, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Doordarshan Kendra and their workmen, which was received by the Central Government on 20-3-2007.

[No. L-42012/78/90-IR(DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

R.N. Rai, Presiding Officer

I. D. No. 32/1992

IN THE MATTER OF:

Shri Suraj Pal Sharma,
S/o Shri Bal Mukund Sharma,
R/o. V. Kaseru, P.O. Khas,
District, Aligarh (UP)

Versus

Doordarshan Kendra,
New Delhi,
Through the Director,
Akashwani Bhawan,
Parliament Street,
New Delhi

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-42012/78/90-IR(DU) Central Government Dt. 18-3-1992 has referred the following points for adjudication.

The point runs as hereunder :

"Whether the action of the management of Doordarshan Kendra, New Delhi in terminating the services of Shri Suraj Pal Sharma w.e.f. 11-9-1989 is justified? If not, what relief the workman concerned is entitled to?"

Award dated 23-2-2004 has been set aside by order dated 22-11-2005 and with a direction to give fresh consideration and pass a detailed and considered award in accordance with law.

The workman has filed statement of claim. In the statement of claim it has been stated that the workman Suraj Pal Sharma joined into the employment of the Doordarshan Kendra w.e.f. 1st September, 1988 as a

General Assistant. He was being treated muster roll worker and was being paid wages @ Rs. 50 per day although he continuously worked for the whole month but he was paid for 10 days only.

That the Officers of the Doordarshan Kendra have been playing a fraud with the workman by paying him only 10 days' wages when actually he was working continuously and regularly from 1st September, 1988 up to date.

That the non-regularization of services of the workman aforesaid in proper pay scale and allowance is wholly illegal, bad, unjust and mala fide for the following amongst other reasons :

1. That after continuously working in each month and showing the workman to have worked only for 10 days and paying him wages for 10 days amounts to unfair labour practice.
2. That the job against which the workman aforesaid was working is of a regular and permanent nature of job which is still continuing with the management.
3. That employing persons on regular nature of jobs and treating them as muster roll workers for indefinite period and paying them lesser remuneration than those who are doing the identical work and the work of the same value amounts to unfair labour practice as provided in Section 2(ra) read with Item No. 10 of the 5th Schedule of the ID Act, 1947.
4. That it amounts to unfair labour practice and sheer exploitation of labour.
5. That as pronounced by the Hon'ble High Court of Delhi a workman is deemed to have been regularized in services after completing 240 days continuous services in a span of 12 calendar months according to which the workman aforesaid has acquired the status of a permanent employee.
6. That a demand notice was served upon the Director of the Doordarshan Kendra by Regd. A/D post vide communication dated 3rd August, 1989 duly received in his office but no reply was received and it was presumed that the demand was rejected. Thereafter, the dispute was raised by filing a statement of claim before the Conciliation Officer, Delhi Administration, Delhi on 22-11-1989 in which the regularization of services of the workman Shri Suraj Pal Sharma was demanded.
7. That after receiving the demand notice on 2nd September, 1989 the management has

terminated the services of the workman Shri Suraj Pal Sharma w.e.f. 11-9-1989.

8. That the termination of services of the workman Shri Suraj Pal Sharma is wholly illegal, bad, unjust and mala fide for the following amongst other reasons :

- (i) That the workman aforesaid has been victimized for raising an industrial dispute for regularization of his services and for that reason the management has terminated the services of the workman aforesaid by way of victimization.
- (ii) That the services of the workman have been terminated during the pendency of an industrial dispute in clear violation of Section 33 of the ID Act, 1947 without obtaining any permission from the Conciliation Officer before whom the dispute was pending.
- (iii) That at the time of termination of services. No seniority list was displayed, no notice was served, no notice pay was either offered or paid a no service compensation was either offered or paid to the workman aforesaid.
- (iv) That the workman aforesaid had acquired the status of a permanent employee after rendering services from 1st September, 1988 to 11th September, 1989. He has unblemished and uninterrupted record of service to his credit.
- (v) That the workman aforesaid has been meted out with hostile discrimination as juniors to him have been retained in services, they have also been regularized in service but the workman aforesaid has been thrown out of job.
- (vi) That during the period from 1-9-1988 to 11-9-1989 he has been treated as muster roll worker. He was being paid his wages as fixed and revised from time to time under the Minimum Wages Act i.e. @ Rs. 50 per day but he was paid only for 10 days in a month although he had to work throughout the month.
- (vii) That even otherwise, the impugned termination of services is violative of Section 25 F, G & H of the ID Act, 1947 read with Rules 76, 77 and 78 of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957.
- (viii) That at the time of termination of services of the workman aforesaid, he was working against permanent and regular nature of job.
- (ix) That no notice was served on the appropriate government for effecting the retrenchment of the workman aforesaid.

That the workman aforesaid is unemployed since 12th September, 1989.

That a demand notice was served upon the Director of Doordarshan Kendra by Regd. A/D post vide communication dated 5th October, 1989 duly received in his office on 7th October, 1989 but no reply was received and it was presumed that the demand has been rejected. Thereafter, the dispute was raised by filing a statement of claim before the Conciliation Officer. The conciliation proceedings were initiated but resulted in failure because of the adamant and non-cooperative attitude of the management.

It is, therefore, prayed that an award be given in favour of the workman holding thereby the termination of services of Shri Suraj Pal Sharma by the management is illegal and unjustified and holding him entitled to reinstatement in services with continuity and full back wages in proper pay scale and allowances and with all consequential benefits thereof either monetary or non-monetary. The cost of litigation as provided in Section 11(7) of the ID Act, 1947 be also allowed.

The management has filed written statement. In the written statement it has been stated that the statement of claim is not maintainable as the workman failed to file the same with the Tribunal within 15 days of receipt of the order of reference and also failed to forward a copy of such statement to the management involved in the dispute as required under rule 10-B of the Industrial Dispute (Central) Rules, 1957.

That there is no retrenchment and the present case falls under exception (bb) of clause (oo) of Section 2 of the ID Act, 1947 and thus the statement of claim is not maintainable.

That the statement of claim is bad for non-joinder of necessary parties. Any decision on the application made by the workman is likely to affect adversely the rights of the alleged junior employees and so the very bias and essential requirement that a person who is going to be adversely affected should be made a party to the proceedings and should alleged juniors being made parties to the proceedings, the statement of claim made by the worker is not maintainable.

That the workman is not entitled to back wages as the judicial pronouncement is in the nature of a fresh rule elaborated by a court in the interest of justice and it can have effect only from the date of pronouncement. It is submitted that in other words it would mean that its effect will be only prospective and not retrospective like any other new rule of law emanating from the parliament of the executive.

That the workman was engaged by Doordarshan Kendra, New Delhi as Artist on assignment basis as General

Assistant on 10 days w.e.f. 21-09-1988 to 30-09-1988 and not from 01-09-1988.

It is submitted that the workman was engaged by Doordarshan Kendra, New Delhi as Artist on assignment basis as General Assistant on 10 days basis w.e.f. 21-09-1988 to 30-09-1988 and not from 01-09-1988 as alleged. Before engagement on assignment basis a contract for 10 days assignment has been signed by him. He did not work for the whole month. It is denied that he was being treated as muster roll worker.

The workman has not worked for the whole month in September, 1988, but he worked for 10 days from 21-09-1988 to 30-09-1988 for which he was signed contract accordingly. As such no fraud has been played with him.

That the question of regularization in proper scale and allowances etc. does not arise at all, as he was engaged for a particular type of job for which before taking assignment he has signed the contract. It was open to him to sign the contract or to refuse to sign the contract.

The workman was engaged for 10 days only in a month and has been paid for 10 days as per the terms of the contract signed by him. The question of unfair labour practice does not arise at all in this case.

To meet urgent programme exigencies Doordarshan Kendra engages Artists on assignment basis. Their engagement depends on the programme requirement. It is denied that the job against which the workman was engaged is of a regular or permanent nature.

The Doordarshan Kendra engages the Artist on assignment basis. The fee for such Artist varies from Rs. 50 to 400 per assignment. Their engagement depends on the programme requirement. As per the scheme approved by the Government, a person can be engaged as Artist on assignment basis maximum for a period of 10 days in a month. A panel of persons is prepared for this purpose and they are booked on rotation basis depending on the programme requirements. The question of unfair labour practice an exploitation does not arise at all.

The pronouncement of the Hon'ble High Court of Delhi is not applicable in the present case. The workman has not been in employment for 12 calendar months and has actually worked for less than 240 days during the said 12 calendar months. Thus both the conditions have not been fulfilled.

It is submitted that the workman left of his own and was not available for further contracts. It is submitted that the workman was engaged on assignment basis for 10 days in a month from 21-9-1988. The workman was engaged on assignment basis for 10 days in a month for which before taking assignment he has signed the contract.

No order of termination was issued as the workman left of his own. It is denied that he was working against permanent and regular nature of job. There is no violation of any sections or rules of the Industrial Disputes Act, 1947.

Once the workman was engaged on assignment basis for a specified period, he signed the contract accordingly question of issue of notice of termination does not arise. Moreover the workman left the job of his own.

In view of the submissions made above the application/statement of claim of the workman may be dismissed with costs.

Heard arguments from both the sides and perused the papers on the record.

From perusal of the pleadings of the parties the following issues arise for adjudication :

1. Whether the workman has completed 120 days work during his tenure of employment i.e. from 21-9-1988 to 30-9-1988 and he is entitled to reinstatement in view of O.M. dated 9-6-1992 ?
2. Whether the management has committed unfair labour practice in engaging temporaries, casuals and badlies again and again ?
3. To what amount of back wages the workman is entitled ?
4. Relief if any other ?

Issue No. 1

Parties have filed documents in support of their respective pleadings. Oral evidence has also been taken from both the sides. Perused the papers on the record.

It is admitted case of the management that the workman has been given 13 appointments for 10 days in each month on Rs. 50 per day. So no further documents are required in view of the admission of the management.

It was argued from the side of the workman that he has been given 10 days appointment whereas he was called everyday in every month. He has filed entry passes. Entry Passes disclosed the period for which they have been issued. The entry passes have been denied by the management but there is signature of the competent authority and it has nowhere been alleged that it has not been signed by the authorised person. So mere denial is not material. The particulars of the entry passes are as under :

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	21-09-1988	to	30-09-1988
2.	01-10-1988	to	10-10-1988
3.	21-11-1988	to	30-11-1988
4.	21-12-1988	to	30-12-1988
5.	22-01-1989	to	31-01-1989

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	19-02-1989	to	28-02-1989
7.	22-03-1989	to	31-03-1989
8.	21-04-1989	to	30-04-1989
9.	22-05-1989	to	31-05-1989
10.	21-06-1989	to	30-06-1989
11.	22-07-1989	to	31-07-1989
12.	21-08-1989	to	30-08-1989
13.	01-09-1989	to	10-09-1989

Total = 130 days (10 days in each period)

The entry passes D-5 and D-6 show that the workman was given entry passes from 1-2-1989 to 15-2-1989 and 16-2-1989 to 28-2-1989. D-7 and D-8 further disclosed that the workman was given entry passes from 1-3-1989 to 15-3-1989 and 16-3-1989 to 31-3-1989. D-5, D-6, D-7, and D-8 prove sufficiently that the presence of the workman was required on everyday of the month.

The entry passes indicates that the workman has been given entry passes for the entire month. In case he was engaged for 10 days in a month he should not have got entry passes from 1-2-1989 to 28-2-1989 and 1-3-1989 to 31-3-1989. It becomes abundantly clear from the entry passes specifically D-5, D-6, D-7 and D-8 that he attended Doordarshan Kendra on everyday in February and March, 1989. The other entry passes also establish the fact that his presence was required on each day of the month.

It becomes quite vivid that the assignment has been given to the workman for 10 days but his presence was required on everyday that is reason that entry passes for entire month have been issued by the management.

It was submitted from the side of the workman that the management should have regularized his services in view of O.M. dated 9-6-1992. O.M. dated 9-6-1992 is reproduced hereunder for clarity's sake.

"Attention is invited to DG : Doordarshan Memo No. 49/9/76-TV(S)/SI, dated 2-8-1977 read with Memo No. 1(2)/85-SI, dated 13-5-1985 containing instructions in regard to engagement of outsiders on short term contract, on assignment basis, as casual artists at various Doordarshan Kendras. The matter regarding regularization of casual artists working in Doordarshan has been under consideration of the Government for quite some time. In pursuance of the directions of the Supreme Court and CAT, particularly, CAT, Principal Bench, New Delhi's Order dated 14-2-1992 in OA No. 563/86 Shri Anil Kumar Mathus Vs. Union of India, it has been decided to consider regularization of casual staff artists category in accordance with the scheme of regularization

approved by the Government, a copy of which is sent herewith. As per the directions of CAT, Principal Bench, New Delhi the process of regularization has to be completed by 14-8-1992.

Since the erstwhile staff artist categories posts have been declared civil posts, reservation of posts for SC/ST would also be applicable while considering regularisation and accordingly 40 points roster of vacancies will be followed.

All the head of the Kendra etc. are requested to kindly initiate action for regularization of casual artists in accordance with the enclosed scheme. The regularisation should be done only in respect of those categories where the head of the Kendra is presently the recruiting authority. In respect of any other categories the cases should be referred with necessary details, to the Directorate for final approval.

In respect of those categories of staff artists, where no casuals were engaged or no casuals are eligible for regularisation, the heads of Kendra may initiate action for regular recruitment, according to the existing Recruitment Rules."

It becomes quite obvious from OM that the cases of those casual employees are to be considered for regularization who have been engaged on assignment basis as casual artists at various Doordarshan Kendras.

It is admitted case of the management that the workman has been engaged on assignment basis. This circular speaks of regularization of those artists also who have been engaged on assignment basis. According to the circular, regularization was to be done by 14-8-1992. The workman was not regularized in view of the above OM, so he has raised Industrial Dispute. It has been mentioned in Para-3 of affidavit of Shri N.N. Jena, Dy. Director (Admn.) as under :

"Since the application did not submit the claim within the stipulated period so the name of applicant remain out of eligible list of category of General Assistant on the ground of non availability of certain information with respect to age, qualification etc. The applicant is still at liberty to furnish his claim as per the scheme of the department."

It becomes quite obvious that the workman was not regularized since he did not file claim within the stipulated period, so his name remained out of eligibility list of category of General Assistant on the ground of non-availability of the certain information. It has been further mentioned that the applicant is still at liberty to furnish his claim as per the scheme of the department.

In view of this categorical admission it was the duty of the management to intimate the workman regarding OM dated 9-6-1992. The workman was discontinued on

30-9-1989, so it cannot be said that he has knowledge of OM dated 9-6-1992. OM dated 9-6-1992 caused duty of the management to give information to the workman in writing for submitting application for consideration of his regularization. There is no proof that the workman was intimated regarding OM dated 9-6-1992. However, when he knew of it he approached the management and he was refused regularization, so he has raised industrial dispute in 1992.

Shri N.N. Jena, Dy. Director (Admn.) has further admitted in Para-9 of his affidavit as under :

"It is reiterated that the applicant can submit the claim aggregate to this scheme."

The department appears to be prepared to consider the case of the workman according to the scheme, but his case has not been considered so far. The workman has undoubtedly raised this industrial dispute and the management should have considered his case for regularization and the management should have settled the matter in the conciliation proceedings but it has not been done so for long 15 years. In view of affidavit of Shri N.N. Jena the case of the workman should have been considered.

The above observation of the affidavit amply prove the fact that there is scheme for regularization. The workman was not aware of the scheme, so he did not submit his claim. In case he submits his claim the management would consider his case for regularization. The management has not considered the case of the workman for regularization and the matter has been contested by the management so, award dated 23-2-2004 was passed in the light of OM dated 9-6-1992.

It was further submitted that the workman has admittedly performed duties for 130 days in a calendar year. As per the scheme of regularization 120 days service is sufficient for regularization. It has been mentioned in the scheme that broken period will not be taken into consideration and the case of the workman on assignment basis will also be considered. This workman has worked on assignment basis and he is covered for regularization under OM dated 9-6-1992.

In the scheme formulated, it has been specifically mentioned in the scheme dated 14-2-1992 as under :

"This scheme would be applicable to all those casual artists who were employed on casual basis on 31-12-1991 including those who were on the rolls of the Doordarshan though they may not be in service now will be eligible for consideration. Those who are engaged on casual basis after 31-12-1991 will not be eligible for consideration."

"Only those casual artists who had been engaged for an aggregate period of 120 days in a year (calendar

year) will be eligible for regularization. The broken period in between the engagement and disengagement will be ignored for the purpose. The number of days is to be computed on the basis of actual working days in the muster rolls or attendance sheets or Q-sheets."

According to this scheme engagement for aggregate period of 120 days is sufficient for eligible for regularization. The broken period in between the engagement and disengagement will be ignored for the purpose. It has been also mentioned in the scheme that casual workman engaged after 31-12-1991 will not be eligible for consideration.

The workman has worked from 21-9-1988 to 30-9-1988, so he has completed at least 130 days actual working days prior to 31-12-1991. So the management should have considered the case of the workman for regularization. I have held in the decision of issue No. 1 that the workman has performed 130 days and in case the broken periods are considered. He has worked for 336 days. The working of 240 days is not essential in this case in view of OM dated 9-6-1992. The workmen who have worked for 120 days are eligible for regularization and broken period will also be considered for this purpose. This workman has worked for 130 days without according for the broken period. So he should have been regularized in view of OM dated 9-6-1992 referred to above.

The management has also admitted that the case of the workman will be considered for regularization when he submits his claim. He has submitted his claim but his case for regularization has not been considered.

It was further submitted from the side of the workman that the post was of regular and permanent nature. The workman was removed whereas another person was taken in his place.

My attention was drawn to D-68 letter dated 31st July, 1989 of the management. It reads as hereunder :

"Permission to book another person in place of Mr. Suraj Pal Sharma may please be given on casual basis as we are facing a lot of difficulties in the evening."

This observation of the management employ proves that the post was of regular nature. The workman was removed and another person was taken at his place. The management cannot do so in view of Section 25 G of the ID Act, 1947. The workman cannot be removed and another person in his place cannot be taken in view of Section 25 G of the ID Act, 1947. The management has acted in violation of the provisions of the ID Act. In view of the above I am of the considered view that the workman deserves regularization.

My attention was drawn to the circular dated 9-6-1992 captioned scheme for regularization of casual artists in Doordarshan. It has been specifically mentioned in this

letter that the casual artists have been given appointment on short term contract, on assignment basis as casual artist at various Doordarshan Kendras. The matter regarding regularization of casual artists working in Doordarshan has been under consideration of the government for quite sometime in pursuance of the direction of the Hon'ble Supreme Court and CAT particularly CAT Principal Bench, New Delhi's order dated 14-2-1992. It has been decided to consider regularization of casual artists against the available vacancy in the erstwhile staff artist category in accordance with the scheme of regularization approved by the government. Usual Artist staff in Doordarshan has been formulated on 13-2-2001 and it has been specifically mentioned that those candidates will be eligible for consideration who have been engaged on casual basis after 31-12-1991.

Thus, as per scheme only those casual artists who have been engaged for aggregate period of 120 days in a year will be eligible for regularization. The broken period in between engagement and dis-engagement will be ignored for the purpose. The number of days is to be computed on the basis of actual working days in the muster-roll, attendance register or Q-sheets. It has been further stipulated in this scheme a minimum of 120 days service in aggregate in one year shall be treated as one year service rendered for this purpose.

It was further submitted that notices have been sent to the workman in view of the scheme of regularization. The case of the workman has not been considered whereas he has performed minimum 120 days work as artist in the department. It has been also mentioned in the circular letter that the broken period will also be taken into consideration. If the broken period are considered this workman has worked for 336 days. In view of this scheme 240 days is not necessary for the purpose of Section 25 F. It was in view of this circular that, I passed award for reinstatement of the workman, whereas he should have been regularized by the management in view of the memo dated 9-6-1992 as he was a casual artist and has worked for 12 calendar months.

According to circular of the management only 120 days work is required for consideration of regularization.

It was submitted from the side of the management that the case of this workman is covered u/s 2 (oo) (bb). He has been given fixed terms appointment for 10 days on 13 occasions and he has worked for only 130 days. He does not deserve regularization as his tenure came to an end on the expiry of fixed tenure appointment.

The work of an artist is a regular nature of work as is evident from memo dated 31st July, 1989. It has been mentioned therein that there is need of casual workman at the place of Shri Suraj Pal Sharma. This memo proves that there is regular requirement for an artist in the evening and someone has been taken at the place of Shri Suraj Pal Sharma to perform his functions.

Circular dated 9-6-1992 stipulates that regularization will be done after considering 120 days work in 12 calendar months. This workman has performed 130 days work, so there is no substance in the contention of the management that the workman has not worked for 240 days and he is not entitled to retrenchment compensation and one month's pay in lieu of notice.

It was submitted from the side of the management that the workman was given fixed term assignment. There was no termination of his services. His services came to an end with the expiry of contracted period of employment. In such case 2(oo) (bb) is applicable.

It was submitted from the side of the workman that there is colourable exercise of powers by the management. The post is of regular and permanent in nature, still 10 days assignments 13 times has been given by the management. Another person has been taken in place of the workman as is evident from order dated 31st July, 1989.

It was further submitted that the OM dated 9-6-1992 specifically stipulates that the case of the workman even given on assignment basis will also be considered and the broken period of the workman will also be considered. The management witness has stated that in case he submits his claim he may be regularized. He has not filed any application for regularization, so his case has not been considered. It implies that the management was willing to consider the case of the workman for regularization on his submission of the claim. Award was given on 23-2-2004 and the management is directed to reinstate the workman but the management approached the Hon'ble High Court instead of considering the case of the workman. It reflects the mala fide attitude of the management. The case of the workman is explicit by the OM dated 9-6-1992 and the management has expressed its willingness to consider the case of the workman for regularization but no such order has been passed. This also reflects the adamant attitude of the management. Grave injustice has been caused to this workman. As the other casual workers of his nature have been regularized.

The management cannot take the plea that the workman was not available and he did not submit the application, so his case of regularization was not considered. It was the duty of the management to inform the workman regarding the OM dated 9-6-1992 and invite application for regularization. The management has not done so. It is not presumed that the workman out of service will be aware of OM dated 9-6-1992. The management has deliberately concealed the OM dated 9-6-1992 so that the workman may not apply. When the workman applied after coming to know of the said OM dated 9-6-1992 his case for regularization was not considered. In the facts and circumstances of the case the management has acted illegally, arbitrarily, capriciously and with mala fide motive. The workman deserves reinstatement.

Section 11 A of the ID Act stipulates that in case the Tribunal is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified, it may, by its award, set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any, as it thinks fit or give such other relief to the workman including the award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstance of the case may require. According to this benign provision this Tribunal has the authority to set aside the order of discharge or dismissal and reinstate the workman on the terms and conditions as it thinks fit.

The Hon'ble Apex Court in 2006 (4) Scale has not annulled Section 11 A of the ID Act and the legislature has authorized this Tribunal to set aside dismissal or discharge on its consideration and direct reinstatement. The judgment cited by the management is not applicable in the facts and circumstances of the case.

A three Judges bench of the Hon'ble Apex Court has held in 1993-II-LLJ that termination of services affects the livelihood of not only of the employee but also of the dependents. So in case of illegal termination of service the workman should be restated.

It was further submitted by the management that the workman has been given fixed term appointment. It has been held in 2006 LLR 68 that termination in terms of appointment letter is justified. The Hon'ble Apex Court has hold that the workman has not proved that the work is of continuing nature and it is still existing. So termination after the period of fixed term engagement has been held valid. In the instant case the work is still continuing. This case law is not applicable in the facts and circumstances of the present case.

My attention was drawn to 2006 LLR 68. The Hon'ble Apex Court has held that engagement and extension of services of the workman was for a specific period and hence termination is not illegal and the termination is in accordance to the provisions of 2(oo) (bb). In this case also the Hon'ble Apex Court found that it is not proved that the work is of existing nature. The case law referred to above is not applicable in view of O.M. dated 9-6-1992.

The workman has submitted the particulars of the work done by him. D-1 (36 pages). These papers have not been denied by the management. This also suggests that the workman visited the respondents on each day in a month during his employment and work was taken by him but he was constrained to receive 10 days appointment letters as he was out of employment. As per admission of the management it is held that the workman has worked for 130 days from 21-9-1988 to 30-9-1988. Thus it stands proved that the workman has worked for 130 days in 12 calendar months and deserves reinstatement. This issue is decided accordingly.

Issue No. 2

It was submitted from the side of the workman that the post of casual artist is a regular nature of post. Artists are always required by Doordarshan Kendra. There is no question of giving fixed term appointment against the post of regular nature. The management was in the habit of giving appointment to casuals and badlis again and again.

The workman has filed D-68 letter dated 31st July, 1989. It reads as hereunder :

"Permission to book another person in place of Mr. Suraj Pal Sharma may please be given on casual basis as we are facing a lot of difficulties in the evening."

This observation indicates that there was a regular need of an artist in the evening. Shri Suraj Pal Sharma was removed and the management engaged another person in his place and for the same sort of work.

Against a post of regular and permanent nature, casual appointment cannot be given. The management has given 13 casual appointment letters to the workman Shri Suraj Pal Sharma. He has been removed and another person has been taken in his place in utter violation of Section 25 G of the ID Act, 1947.

It was further submitted that Section 25 T provides that the management should not indulge in unfair labour practice. Section 25 U provides that a person who commits any unfair labour practice will be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine, which may extend to Rs. 1000 or with both. The intention of the legislature in enacting 25 T & 25 U is obvious. The legislature wanted that in case Casual and Badlis are engaged for a long period, it amounts to unfair labour practice. There is punitive clause for committing unfair labour practice.

It was submitted from the side of the workman that Vth Schedule of the ID Act specifies some practices as unfair labour practice. The Vth Schedule clause 10 provides the criteria for ascertaining unfair labour practice. It is extracted as hereunder :

"To employ workman as Badlis, Casuals or temporaries and to continue them as such for years with the object of depriving them of the status and privilege of a permanent workman."

Clause 10 of the Vth Schedule stipulates that in case the workmen are employed as Casuals, Badlis or Temporaries and they are continued as such for years, it will amount to unfair labour practice. In the instant case the workman has been continued as casual and temporary for 13 months. It establishes to the hilt that the respondent management has committed unfair labour practice. The workman has been engaged on occasions as casual and temporary and thereafter he has been removed. He has not

been paid retrenchment compensation. Another person has been engaged in his place.

It was submitted that Section 25 F, G, T, U and Clause 10 of the Vth Schedule of the ID Act have been deliberately violated. Doordarshan Kendra is not a ticket booking office. An Artist or a workman cannot be booked again and again for a work of regular and perennial nature. The observations of 31st July, 1989 reproduced above amply establish the fact that casuals and badlies have been taken again and again in violation of the provision of ID Act, 1947. Thus, the management has committed unfair labour practice. This issue is decided accordingly.

Issue No. 3

It was submitted from the side of the workman that he should be given 100% back wages. It was the duty of the workman to disclose the means of his subsistence. He has not stated anywhere as to how he survived during this long interregnum. It was his duty to disclose the source of his livelihood, whether he was maintained by his parents or he has some ancestral property. There is nothing of this sort in his affidavit. In such circumstances it is presumed that an artist will not sit idle.

Full back wages cannot be awarded as a natural consequence of reinstatement. Full back wages are not automatic.

It was further submitted that payment of full back wages is not the natural consequence of the order of discharge or dismissal being set aside. It has been held in (2003) 6 SCC 141 that it is incumbent upon the labour court to decide the quantum of back wages.

It has been further held in this case that payment of back wages having discretionary element involved it is to be dealt with the facts and circumstances of the case. No definite formula can be involved.

It has been further held in this case that payment of back wages in its entirety is the statutory sanction. In (2003) 4 SCC 27 the Hon'ble Apex Court held that in view of delay in raising the dispute and initiating the proceedings back wages need not be allowed. In the instant case there is no delay at least on the part of the workman in raising the dispute.

In 2004 VIII AD SC 444 the Hon'ble Apex Court upheld the order or reinstatement with 25% back wages.

In 1978 Lab IC 1968—three Judges Bench of the Hon'ble Apex Court held that payment of full back wages is the normal rule. In case services have been illegally terminated either by dismissal or discharge or retrenchment, in such circumstance the workman is entitled to full back wages except to the extent he was gainfully employed during the enforced idleness. In the instant case the workman was always ready to work but he was not permitted on account of invalid act of the employer.

In AIR 2002 SC 1313 the Hon'ble Apex Court reduced the back wages to 25%.

It was submitted from the side of the management that reinstatement is not the only remedy. In such cases the workman may be given compensation. Section 11 A of the ID Act, 1947 provides that in case dismissal or discharge is found illegal reinstatement should be ordered. It has been held in a catena of cases by the Hon'ble Apex Court that reinstatement with full back wages is the normal rule. The statute provides for compensation. In certain exceptional cases where the undertaking has been closed down or it has become sick there may be order for payment of compensation.

It was submitted from the side of the workman that he should be given 100% back wages. The workman has worked for 130 days only. He has not disclosed the sources of income from which he survived. It was his duty to give evidence regarding the same. In such circumstances it may be presumed that being an Artist he must be doing some work off and on. The period of his employment is only for one year, so he is entitled to 25% back wages. This issue is decided accordingly.

Issue No. 4

It has been held above that the workman is entitled to reinstatement and regularization. He is entitled to 25% back wages. The management should reinstate the workman with 25% back wages and consider his case for regularization. This issue is decided accordingly.

The reference is replied thus :

The action of the management of Doordarshan Kendra, New Delhi in terminating the services of Shri Suraj Pal Sharma w.e.f. 11-9-1989 is not justified. The respondents are directed to reinstate the workman applicant along with 25% back wages w.e.f. 11-9-1989 within two months from the date of the award and consider his case for regularization in the light of Office Memo dated 9-6-1992.

Award is given accordingly.

Date : 9-3-2007

R.N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1068. -- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नागपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी जी आई टी/एन जी पी/49/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-3-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/97/89-डी-2 (बी)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1068.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT/NGP/49/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Telecom Department and their workman, which was received by the Central Government on 20-03-2007.

[No. L-40012/97/89-D-2 (B)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI A. N. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR

Case No. CGIT/NGP/49/2003

Date : 06-03-2007

Petitioner/Party No. 1 :

Shri M. B. Godghate, Through M. P. Kale, N-2T, Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur-440 012

Versus

Respondent/Party No. 2 :

B.S.N.L., Through District Manager, Telecommunication, Saraf Chamber, Nagpur-440 001.

AWARD

[Dated : 6th March, 2007]

1. The Central Government after satisfying the existence of disputes between Shri M. B. Godghate, Through M. P. Kale, N-2T, Sneh Nagar, Wardha Road, Nagpur-440 012 Party No. 1 and B.S.N.L., Through District Manager, Telecommunication, Saraf Chamber, Nagpur-440 001 Party No.2 referred the same for adjudication to this Tribunal vide its Letter No. L-40012/97/89-D-2(B) dt. 30-01-1990 under clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) with the following schedule :

"Whether the action of the Management of Telecommunication, Nagpur by terminating the services of Shri M. B. Godghate, w.e.f. 03-05-1989 is justified ? If not, to what relief the said workman concerned is entitled to ?"

2. The reference was referred for adjudication to the CGIT Jabalpur in the year 1990. It seems that nobody appeared on behalf of the petitioner on 18-05-1990, which was a first date of the court before CGIT Jabalpur. However, Advocate Kohli for the management appeared before it. Later on the next date was given. The P.O. has directed to inform the workman. Accordingly a notice was issued to

one Shri Kale. Despite of the notice nobody appeared before CGIT Jabalpur and nobody has even filed the Statement of Claim till 13-09-1996. Subsequently the case was transferred to this court again a notice was issued as per address given in the reference, they were sent to Management BSNL and to one Shri M. P. Kale. Perhaps office bearer of the union or in whose care Shri Godghate might be residing. The reference does not disclose any address of Godghate. Hence the notice was sent to Kale. Nobody appeared right from the beginning i.e. from the date of receipt of reference. On behalf of management Shri Kohli appeared but nobody appeared for petitioner. Consequently though the reference is of the year 1990 the Statement of Claim is not filed. On transfer to this tribunal i.e. CGIT Nagpur again a notice was issued on the same address of Mr. Kale but the notice was issued unserved with the remark that he has left and he has left the address. Hence no purpose would have served even continuing the reference. It is therefore, dismissed for default as nobody is appearing either for the management or for the petitioner. Its stands as dismissed for default of the petitioner.

Hence this award.

Dated: 06-03-2007 A. N. YADAV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007

का.आ. 1069.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी. एम. पी. डी. आई. के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 244/1992) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-3-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/221/1992-आई आर (सी-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th March, 2007

S.O. 1069.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.244/1992) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CMPDI and their workman, which was received by the Central Government on 20-03-2007.

[No. L-22012/221/1992-IR (C-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
JABALPUR**

NO. CGIT/LC/R/244/92

Shri C. M. Singh, Presiding Officer

President,
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh,
Branch CMPDIL (RI-V),
M. V. Market,
Bilaspur (MP) Workman/Union

Versus

President,
National Coal Organisation Employees
Association,
Branch CMPDIL (RI-V),
M. V. Market,
Bilaspur (MP) Management

AWARD

Passed on this 26th day of February, 2007

1. The Government of India, Ministry of Labour vide its Notification No. L-22012/221/92-IR (C-II) dated 10-12-92 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal :

“Whether the management of CMPDI Ltd., Bilaspur (Region-V) is justified in changing the Rules of Medical Reimbursement of employees prevailing prior to 6-6-92 ? If not, to what relief, the workmen concerned are entitled to ?”

2. The case of Workmen/Union in brief is as follows. That the workmen concerned are represented by the President, NCOEA, Bilaspur and President RCMS, Bilaspur. All the employees of CMPDI, RI-V, Bilaspur MP have been entitled to free medical treatment as per paras 2.8 & 4 of the standing orders and the CIL Medical Treatment rules which were in effect w.e.f. 26th Dec. 1981. The CMPDI, RI-V, Bilaspur was established on 23-12-1985. This establishment came into existence by the division of RI-IV (Construction), Nagpur and the medical facilities which were available to the employees of RI-IV, Nagpur were made available to the employees of RI-V also and in this respect, Shri D.P. Choudhary the then Regional Director issued a circular dated 15-3-86 for providing free medical treatment to the employees. The said medical facilities remained continued from 1986 to 1992. The management in order to harass the employees, began curtailing the medical facilities available to the employees and from 1st Feb. 1992, the management began demanding Income Certificate of the parents of the employees though before it, simple declaration made by the employees was taken as sufficient. On opposing by the employees, the status ante was maintained by the management. But thereafter vide circular No. R. V/Medical/92/96 dated 6-4-92, the management began curtailing medical facilities available to the employees for causing harassment to them. The said circular could not come into effect due to opposition raised by Union. Thereafter the Regional Director issued another circular No. RD-V/Medical/Faci/92/366 dated 29-5-92, whereby the panels of

the chemist in existence till then, were discontinued from 1-6-92 and vide circular No. RD-V/Medical/Faci/92/173 dated 30-5-92 medical committee was constituted in which employees were also given representation, but the jurisdiction of the said committee was limited. Thereafter on 30-6-92, a circular order regarding medical facilities without any legal authority was issued whereby it was directed to prepare a list of 10 columns. The Union opposed the said act of management and a letter of protest was handed over to the Regional Director on 1-6-92 but the management turned deaf ears towards the protest letter and did not do anything till date. The management from 1-6-92 deprived the employees of free medical treatment facilities except of providing free medical advice. The management ordered the employees to purchase medicines themselves and the money spent thereon would be paid after 20 days of submitting the bill after recovery from the ailment and in this manner, the management caused harassment to the employees. The employees for getting medical treatment had to take loan. In case the medical prescription is lost, they are deprived of the payment spent on the medical treatment by them. Thus the employees are facing great difficulty in getting the money reimbursed spend on the medical treatment. It is proved by the employees that the tribunal be pleased to hold that the management of CMPDI Ltd., Bilaspur (Region-V) is not justified in changing the Rules of Medical Reimbursement of employees prevailing prior to 6-6-92.

3. The management filed their Written Statement. Their case in brief is as follows. The CMPDI, RI-V, Bilaspur was established in 1986 at the HQ of CMPDI, which is a subsidiary of Coal India Ltd. situated at Ranchi. All the employees of Coal India Ltd. and its subsidiary companies get medical treatment facilities as per Medical Attendance Rules (MAR) of Coal India Limited as amended from time to time. In terms of Chapter-VI of MAR, all employees governed by NCWA are entitled to free medical treatment only to the extent available at the Company's hospitals/dispensaries. If the medicines prescribed by Medical Officers of the company, hospitals/dispensaries are not available in the dispensaries, nor purchased and supplied by the company management and have to be procured by the workmen themselves, the cost of the same will be reimbursed on presentation of the cash memo. In places where CMPDI do not have their own company hospital/dispensary, company has made arrangements with panel of General Practitioners & Specialists for treatment of their employees and their dependents. After establishment of CMPDI, RI-V, Bilaspur in 1986 the employees of CMPDI, Bilaspur were getting medical facilities from panel of Doctors/Pathologists/Radiologists and medicines prescribed by the panel doctors were purchased from a panel of chemist. The CMPDI management made direct payments to the Doctors, Radiologists, Pathologists and Chemists. In addition to the above panel doctors, CMPDI,

RI-V, Bilaspur is also having five Nursing Homes. Besides the above, Jackman Memorial Hospital is in the panel of CMPDI, Bilaspur since 1986-87 and is treated as company hospital by CMPDI, Bilaspur in the absence of a company hospital at Bilaspur. Panel Doctors/Pathologists/Radiologists and Chemists etc. submitted their bills to CMPDI management for audit and payment once in a period of one or two months. The above system of medical treatment facilities and payment of panel doctors, chemists etc. seemed to work without attracting any suspicion till the year 1991. However, in the year 1991 misuse of these medical facilities were suspected. The vigilance department of CMPDI (HQ), Ranchi carried out a study of medical reimbursement in CMPDI, RI-V, Bilaspur for the period from April 1991 to 15-11-91 (7½ months) which revealed that total expenditure for this period was approximately Rs. 6,05,692 for 167 employees and some employees had even spent more than 10,000 without any major illness. In view of the above findings of Vigilance Department, Director (O), CMPDI (HQ), Ranchi appointed an audit team on 15-1-92 consisting of one officer each from finance department, medical department of CMPDI (HQ), Ranchi and Medical Department of SECL (HQ), Bilaspur. Meanwhile the case of high expenditure on medical treatment was discussed in the Welfare Committee meeting held on 29-1-92 at RI-V and the workers representative agreed to contribute their services for reducing expenditure. As decided in the meeting, a Committee consisting of Shri S. K. Basu, Finance Manager and workmen represented by Shri N. Gosh, Secretary, National Coal Organisation (Govt. of India) Employees Association, Bilaspur and Shri A. S. Qureshi, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Bilaspur was constituted vide order dated 10-2-92 for taking appropriate steps for controlling the increasing trend in medical expenses and they were advised to submit their report by 15-4-92. The committee did not submit any report. The committee appointed by Director (O), CMPDI (HQ), Ranchi as already stated in Para-12 above, submitted its report on 4-3-92 and the same was received by the management on 25-3-92. The audit team during verification of bills pertaining to medical treatment of employees, observed the following :—

- (a) That many of the employees directly consult specialists without reference made by General Practitioner. As per Medical Attendance Rules, the employees should take treatment from specialists only on reference from a General Practitioner.
- (b) That the employees consult various doctors in a month.
- (c) That some employees go very frequently to more than one doctor before completion of treatment of earlier disease.

- (d) That instead of continuing the treatment, the employees discontinue the treatment with one doctor and consults another doctor again for either the same disease or some other illness as a result of which it is difficult to trace the nature of the illness. This suggests that they are not serious about the treatment and simply use the facilities available for no fruitful purpose.
- (e) That in one case employees has purchased medicine after a lapse of 6 days whereas the medicine prescribed by the doctors should have been started immediately. This gives rise to certain doubts as to whether the medicines purchased have been used at all.
- (f) That since the employees have been changing doctors frequently, no doctor is able to know whether the treatment/medicine prescribed by him is being followed properly.
- (g) That the mandays lost is remarkably less in comparison to the illness of the employees based on the prescription.
- (h) That in large number of cases, empanelled doctors have often prescribed costly medicines for more than 5 to 7 days at a stretch in the very beginning of the treatment.
- (i) That though the company has made available to the employees all medical facilities like outdoor and indoor treatments, General Practitioner, specialist and Nursing Homes, a right direction is not being followed to avail this facilities in a proper way.

3. The committee recommended certain recommendations mentioned in Para-16 of the Written Statement to reduce the misuse that were observed during their verification on the medical bills of the employees during audit. To implement the recommendations of the Committee, circulars were issued vide office order Nos. 111 & 112 both dated 15-4-92 by which prevailing system of medical treatment/reimbursement facilities were modified and new system was to come into effect from 30-4-92. The salient features of the amended system were as follows :—

- (a) Payment to Doctors/Chemists directly by the Company was discontinued. The employees will pay the consultation fee directly to the doctors and purchase medicines from chemists and submit their bills for reimbursement.
- (b) Panel of Pathologists and Radiologists were discontinued.

After the issue of the above circulars, the workmen/ Union approached the management and expressed their

desire to meet the CMD, CMPDI to discuss the matter. They also requested the management to keep the implementation of the above circulars in abeyance till they discuss the matter with the CMD, CMPDI, Ranchi. As requested by the workman/Union, the implementation of the circulars were kept in abeyance till 31-5-92. As desired by the Union, a meeting was held on 16-5-92 at Ranchi with Director (O), CMPDI, Ranchi. In the meeting which was attended by workmen represented by NCOEA, Bilaspur/ Ranchi and RCMS, Bilaspur, the management agreed that the panel doctors will be paid by the management directly as per old practice. However reimbursement of cost of medicines will be claimed by the employee as was done in CMPDI (HQ). In the functional Director's meeting held on 30-4-92, it was decided that in order to have uniformity in medical reimbursement procedure in all the Regional Institutes as well as in CMPDI(HQ), all the Regional Institutes were advised to adopt the practice that is followed at CMPDI (HQ). In order to implement the decision taken in the Functional Director's meeting held on 30-4-92 and the meeting between the management and the Unions on 16-5-92, a circular dated 29-5-92 was issued abolishing the panel of chemists and the new system of medical reimbursement was introduced w.e.f. 1-6-92. Further as decided in the meeting held on 16-5-92, a committee consisting of Shri K. A. Pant, Addl. CME, Shri B. K. Das, Finance Manager, Shri M. Ashok Kumar, Personnel Officer, Shri N. Gosh, Secretary, NCOEA, Bilaspur and Shri A. S. Qureshi, Secretary, RCMS, Bilaspur was constituted for recommending fresh panel doctors (both General Practitioners and Specialists). The above committee met on 21-7-92 and 29-7-92 and submitted their recommendations for a revised panel of doctors and on acceptance of the recommendations, a new panel of doctors for treatment of CMPDI, Bilaspur employees were formed w.e.f. 17-8-92. By introduction of the new system of medical reimbursement as decided in the meeting held by Union representative with Director (O) on 16-5-92 and approved by the Functional Directors of CMPDI in their meeting held on 30-4-92, there was no reduction in the medical facilities extended to the employees as provided in the Medical Attendance Rules of Coal India Limited. To effectively verify and check the expenditure incurred towards medical treatment, the management of CMPDI, Bilaspur issued a circular dated 3-6-92 to all the Head of Departments in CMPDI, Bilaspur for submission of medical reimbursement bills in a particular format so that in all the departments, the medical bills submitted by employees for reimbursement are processed uniformly. It is prayed by the management that this tribunal be pleased to hold that the action of management is fully justified in the circumstances of the case and workmen are not entitled to any relief whatsoever.

4. Vide order dated 6-3-06, the reference proceeded ex parte against the workmen/Union.

5. The management in order to prove their case filed affidavit of Shri M. Ashok Kumar, the then working as Personnel Manager, CMPDIL, Bilaspur.

6. I have heard Shri A. K. Shashi, Advocate, the learned counsel for the management. I have very carefully gone through the evidence on record.

7. As the case proceeded ex parte against the workman/Union there is no evidence on record from the side of workmen/Union. The case of the management stands fully proved from the affidavit of management's witness Shri M. Ashok Kumar, the then working as Personnel Manager, CMPDIL, Bilaspur as his affidavit has remained uncontroverted and unchallenged.

8. In view of the above, it is hereby held that the management of CMPDI Ltd., Bilaspur (Region-V) is justified in changing the Rules of Medical Reimbursement of employees prevailing prior to 6-6-92 and therefore the workmen/Union are not entitled to any relief. Considering the facts and circumstances of the case, I am of the view that the parties be directed to bear their own costs of this reference. Therefore in answer to the reference order, it is held that the management of CMPDIL, Bilaspur (Region-V) is justified in changing the Rules of Medical Reimbursement of employees prevailing prior to 6-6-92 and the workmen concerned are not entitled to any relief. The parties shall bear their own costs of this reference.

9. Copy of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour as per rules.

C. M. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2007

का.आ. 1070.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नार्दन रेलवे के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 44/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41011/08/1999-आइ आर (बी-1)]

राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st March, 2007

S.O. 1070.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.44/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, II New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial dispute between the management of Northern Railway and their workmen, received by the Central Government on 21-03-2007.

[No. L-41011/08/1999-IR (B-1)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

Presiding Officer : R. N. Rai

I.D. No. 44/2003

IN THE MATTER OF:—

Shri V. S. Tyagi,
S/o Late Shri B. S. Tyagi,
R/o 10/12, Railway Colony,
Sewa Nagar,
New Delhi.

Versus

The General Manager,
Northern Railway,
Baroda House,
New Delhi.

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-41011/08/1999-IR (B-1) Central Government dt. 31-03-2003 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder :—

"Whether the action of the management of Northern Railway, New Delhi in transferring Shri V. S. Tyagi from Anand Vihar Health unit to Delhi Main Hospital in 1997 and subsequently issuing order of compulsory retirement from service is justified ? If not, what relief the applicant is entitled to ?"

The workman applicant has filed statement of claim. In the statement of claim it has been stated that the applicant is a workman of the Railway Industry. He joined his services in the Railway as Pharmacist on 11-02-1974 in scale Rs. 130-240 (A.S) and his service was regularized by GM (P) vide letter No. E-33/1/ES/CH dated 18-12-1975 and further promoted in scale Rs. 455-700 w.e.f. 01-01-1984 and Rs. 550-750 w.e.f. 03-10-1986 respectively by GM (P) with the approval of CMO now called CMD, vide letter No. 751/E/S-VIII/E/II dated 26-05-1993 and was posted H.E. Pharmacist, Anand Vihar, N. Railway Dispensary, Delhi.

That the applicant has been exposing the cause of workers and with the result he was disliked by some of the bureaucrats and he was made target and he was victimized of his trade union activities and under one pretext or the other he is being harassed at present. The applicant is the General Secretary of the Northern Railway Union registered. The copy of the registration of the union and the copy of the protected workman is attached herewith and marked as Annexure A-1 and A-2 respectively.

That an Industrial Dispute between the management of Northern Railway and their workman including applicant, represented by Northern Railway Labour Union (Regd. and Protected) was initiated by the applicant on 09-08-1995 being General Secretary of Northern Railway Labour Union with the connected dispute of the applicant.

That in connection with ID dated 09-08-1995, it is submitted that as personal allegations were made in the industrial dispute dated 09-08-1995 against Dr. Deepali Gupta/Management then they became very angry with the applicant and threatened him for dire consequences.

That as sequel to their personal grudge for the reason stated above against the management, they have passed the transfer order at the instances of Officer Dr. Deepali Gupta, Sr. DMO, Anand Vihar, transferring the applicant on 25-09-1995 from the Anand Vihar Dispensary to Delhi Division Hospital, Delhi illegally. However, the applicant challenged the transfer order in the Hon'ble CAT in O.A. No. 2035/1995 and transfer order was quashed vide judgment dated 03-10-1996.

The operative part of the judgment dated 03-10-1996 is reproduced below for perusal :—

"The respondents have not produced any material on record to show that the impugned transfer order has been passed with the approval of the competent authority as per the rule, from perusal of the relevant file, it is also seen that the matter of approval adopted in this case by the DPO is contrary to establishment procedure. It is, therefore, to be rejected on both counts namely as contrary to law and normal practice and procedure.

In the facts and circumstances of the case impugned transfer order dated 25-09-1995 is quashed and set aside accordingly, the application succeeds no order as to costs."

It transpires from perusal of the order sheet that the management was represented by Shri Kali Raj Singh while dispute was pending before the CGIT-I. It has subsequently been transferred to this Tribunal. Registered notice to the management was sent on 6th June, 2006 for appearance on 25-07-2006 but the management has not turned up till date.

The case proceeded ex parte on 25-07-2006. Affidavit of the workman has been taken.

Heard arguments from the workman and perused the papers on the record.

It was submitted that the applicant is General Secretary of a Registered Trade Union namely N. Railway Trade Union and he was declared a protected workman by the order of the ALC dated 23-02-1984. He was working as Chief Pharmacist and was posted at Anand Vihar Dispensary.

It was further submitted that the workman was illegally transferred and the CAT quashed the transfer order but it was not complied with. The management filed a writ against this order but the same was dismissed. The order of transfer was not modified and the workman was not permitted to resume his duties at the previous place of his posting.

It was further submitted that notice dated 11-06-1997 was served on the management for resuming duty on his transferred post and he remained unauthorized absent w.e.f. 12-06-1997 and failed to intimate the reason for his unauthorized absence till the date of issuance of chargesheet dated 18-05-1998. The workman has all along been requesting the management to allow him to join the post of Anand Vihar Health Unit. The respondents on 4 occasions agreed to restore the applicant to his original place of posting before the RLC but the order of RLC was not complied with on the other hand the management illegally served chargesheet regarding unauthorized absence.

It is pertinent to refer here that this dispute is against illegal transfer for Anand Vihar Health Unit to Delhi Main Hospital in 1997 and order of compulsory retirement from service.

So far as the order of transfer is concerned the management has agreed before the RLC to restore the workman by retransferring the workman to his previous place of posting. The transfer order has been quashed by the CAT still the management did not refuse the transfer and instead issued a chargesheet alleging therein of unauthorized absence.

Since the transfer order has been quashed by the CAT, it no longer stood as order of transfer. The respondents were duty bound to revise their order and transfer him again to Anand Vihar Health Unit. The respondents did not do so despite their willingness to recall the order of transfer before the RLC and despite the fact that the order of transfer has been quashed by the CAT. In the circumstances the workman shall be deemed to be posted at his previous place of posting i.e. Anand Vihar Health Unit. No chargesheet can be issued from Delhi Main Hospital regarding his unauthorized absence.

It was the duty of the management to comply with the orders of the CAT and the settlement reached between the parties before the RLC. In the circumstances the chargesheet is illegal and void in the eye of law. An employee cannot be said to be unauthorizedly absent when the order of transfer has been quashed. The chargesheet in the circumstances is absolutely illegal.

It was further submitted that the departmental inquiry was not held in accordance with the due procedure established by law and principles of natural justice. The workman was never served with a copy of the chargesheet.

It was further submitted that the workman has filed application u/s 33 (a) of the ID Act, 1947 before the RLC. Dr. A. K. Sangar requested the applicant to collect the copy of the charge on 15-11-1998. This falsifies the case of the management that charge-sheet was duly served on the workman.

It was further submitted that charge-sheet dated 18-05-1998 was not issued by the competent authority as per prescribed railway rules. The workman was in a scale of Rs. 5500—9000. The authority who acted as DA was an authority subordinate to the rank of appointing authority and was incompetent to initiate the inquiry proceedings against the workman in view of rule 6 of disciplinary appeal rules 1968. The DA was also incompetent to order punishment of compulsory retirement on the workman. The order of the D.A. and A.A. is arbitrary, mala fide and illegal.

It was submitted that the order passed by incompetent DA is no order in the eye of law. The workman can be removed by the appointing authority or any authority above the rank of the appointing authority.

It was further submitted that in view of Section 33(1) (b) no proceedings can be initiated against a protracted workman. The workman has raised industrial dispute in 1995 and while the dispute was pending he was served with a charge-sheet and order of compulsory retirement was passed. The provisions of 33 are mandatory in nature.

The workman is a protracted workman so he cannot be dismissed or discharged or compulsorily retired while pendency of industrial dispute even not connected with the matter. It has been observed by the Hon'ble Supreme Court in *ILLJ Bhawnagar Municipality's case* as under :—

"To permit rupture in employment, in this case, without the prior sanction of the Tribunal will be to set at naught the avowed object of S.33 which is principally directed to preserve the status quo under specified circumstances in the interest of industrial peace during the adjudication."

"Section 33 of the Act makes provision for ensuring that the conditions of service remain unchanged during pendency of certain proceedings. In sub-section (1) is incorporated the bar that no employer shall, during pendency of any conciliation proceedings before a conciliation officer or a board or any proceeding before an Arbitrator or Labour Court or Tribunal irrespective of an industrial dispute in regard to any matter connected with the dispute, alter to the prejudice of the workman concerned with such dispute, condition of service applicable to them immediately before commencement of the proceedings."

"The purpose of the prohibitions contained in Section 33 is two-fold. On the one hand, they are designed to

protect the workmen concerned during the course of industrial conciliation, arbitration and adjudication, against employer's harassment and victimization, on account of their having raised the industrial dispute or their continuing the pending proceedings, on the other they seek to maintain status quo by prescribing management conduct which may give rise to fresh disputes which further exacerbate the already strained relation between the employer and the workman."

The workman is protracted workman and his case is covered u/s 33 (3) (a & b). It has been observed as under :—

33 (a) alter, in regard to any matter not connected with the dispute the conditions of service applicable to that workman immediately before the commencement of such proceedings; or

(b) for any misconduct not connected with the dispute, discharge or punish, whether by dismissal or otherwise, the workman :

Provided that no such workman shall be discharged or dismissed, unless he has been paid wages for one month and an application has been made by the employer to the authority before which the proceeding is pending for approval of the action taken by the employer "

It becomes quite vivid that inquiry has been initiated against the workman by incompetent authority and it has been initiated from the place to which the workman was illegally transferred. The CAT has quashed the order of transfer, so it shall be deemed in the eye of law that there is no transfer. In the circumstances the workman shall be deemed to be posted at Anand Vihar Health Unit and the Officers in Delhi Division Hospital, Delhi cannot deem him unauthorisedly absent. The order of CAT was to be complied with by the management but the management has arbitrarily overlooked the order of CAT by which transfer of the workman from Anand Vihar Health Unit has been made. The CAT has specifically observed that the order of transfer is against the rules, is contrary to law and normal practice and procedure. The only option opened to the management was to revise the order of transfer and to post him in his previous place of posting i.e. Anand Vihar Health Unit. Despite obeying the order of CAT the management treated him on duty in Delhi Division Hospital and issued him charge-sheet of unauthorized absence. This smacks of a sense of disobedience and disrespect on the part of the management against the well reasoned order of the CAT. The management has invoked writ jurisdiction but the writ has also been dismissed. The order of the CAT regarding quashing of transfer has become final, but overruling the order of the CAT the respondents constrained the workman to resume his duties in his transferred place i.e. Delhi Main Hospital and treated him

unauthorized absent. The management has compulsorily retired the workman. It appears from perusal of the record that the sole mala fide intention of the management was to sit in appeal over the orders of the CAT and the settlement even in conciliation proceedings. Such action is absolutely mala fide, arbitrary and unjust.

It also becomes quite vivid from the record that the workman was a protracted workman and his service condition cannot be terminated without prior approval in conciliation proceedings and proceedings of Tribunal/Court but the management has deliberately contravened the provisions of Section 31 (1)(b) of the ID Act, 1947.

It also becomes apparent that the punishing authority is not competent authority. He was an authority lower in rank, so the order of punishment is absolutely illegal and arbitrary. The charge-sheet has not been served on the workman and he has been proceeded against. The order of compulsory retirement has been passed illegally and arbitrarily. The transfer order dated 25-09-1995 has been quashed by the Court and it is quashed hereby also. The order of compulsory retirement dated 16-09-2000 is liable to be set aside and it is hereby set aside.

It appears that the workman has been driven to forced litigation. In the facts and circumstances of the case the workman is entitled to get a cost of Rs. 25,000 (Rs. Twenty Five Thousand) from the management. Costs however, may be recovered from the erring officers after payment to the workman. The workman is entitled to an interest of 6% p.a. over the entire amount of back wages.

The workman is entitled to be reinstated w.e.f. 16-09-2000 alongwith 100% back wages and continuity of service and consequential benefits and an interest of 6% p.a. on the entire amount of back wages and a cost of Rs. 25,000 (Rs. Twenty Five Thousand).

The reference is replied thus :—

The action of the management of the Northern Railway, New Delhi in transferring Shri V. S. Tyagi from Anand Vihar Health Unit to Delhi Main Hospital in 1997 and subsequently issuing order of compulsory retirement from service is not justified. The workman applicant is entitled to be reinstated w.e.f. 16-09-2000 along with 100% back wages and continuity of service and consequential benefits. The workman is further entitled to an interest of 6% p.a. on the entire back wages and a cost of Rs. 25,000 (Rs. Twenty Five Thousand). The management is directed to reinstate the workman and pay him the entire back wages and costs within two months from the date of publication of the award.

Award is given accordingly.

Date: 12-03-2007

R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

का.आ. 1071.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नागपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 208/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-3-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/81/2003-आई.आर. (बी-II)]

राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd March, 2007

S.O. 1071.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 208/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workman, which was received by the Central Government on 19-03-2007.

[No. L-12012/81/2003-IR (B-II)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI A. N. YADAV, PRESIDING OFFICER,
CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR**

Case No. CGIT/NGP/208/2003

Date: 06-03-2007

Petitioner/Party No. 1:

Shri Sarat Rout, Plot No. B-2, Rasulgarh Industrial Estate, P.O. Bomikhal, Bhubneshwar [Orissa]

Versus

Respondent/Party No. 2:

Bank of Baroda, Through Regional Manager, Regional Office, Masjid Building Unit-IV, Sachivalaya Marg, Bhubneshwar [Orissa]

AWARD

[Dated : 6th March 2007]

1. The Central Government after satisfying the existence of disputes between Shri Sarat Rout, Plot No. B-2, Rasulgarh Industrial Estate, P.O. Bomikhal, Bhubneshwar [Orissa] Party No. 1, Bank of Baroda, Through Regional Manager, Regional Office, Masjid Building Unit-IV, Sachivalaya Marg, Bhubneshwar [Orissa] Party No. 2 referred the same for adjudication to this Tribunal vide its Letter no. L-12012/81/2003-IR-[B-II] Dt. 31-07-2003 under clause (d) of sub Section (1) and sub Section (2A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) with the following schedule.

2. "Whether the action of the Management of Bank of Baroda in relation to their Main Branch,

193145107-25

Bapuji Nagar, Bhubaneswar in terminating the service of Shri Sarat Rout w.e.f. 25-02-2002 without following due procedure of law as required under Section-25 of the Industrial Disputes Act, 1947 and payment of wages less than the minimum wages since 1-1-1989 is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

3. The reference came up for hearing on 06-03-2007 before the Tribunal on which neither petitioner nor his counsel was present. Similarly nobody appeared for the management. I have gone through the record, which indicates that the notices were sent to the petitioner as well as to the Manager and the ministry might have also sent the copy of reference with the notice directing him to file their Statement of Claim within a prescribed period. Despite of it nobody appeared right from the date of receipt of the reference. It appears that since 2nd of June 1995 nobody had appeared before the court. This indicates that the petitioner or the workman has no interest in continuing the case. Even the Statement of Claim has not filed. The reference indicates that he has challenged the order Dt. 25-02-2002 of the management terminating his services without following the procedure under Section 25 of the Industrial Disputes Act, 1947. However, since he has not attended the case and not filed any Statement of Claim nothing can be gathered exactly what the petitioner wants and relief is claimed by him. It appears that he is not interested. Since he is not attending the court it is dismissed for his default. The reference is answered that he is not entitled for any relief and its stands for dismissal of default.

Hence this award.

Dated: 06-03-2007 A. N. YADAV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

का.आ. 1072. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कमकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. I, नई दिल्ली के पंचाद (संदर्भ संख्या 44/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 21-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/16/2002-आई आर (बी-II)]
राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd March, 2007

S.O. 1072.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 44/2002) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. I, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen,

which was received by the Central Government on 21-03-2007.

[No. L-12012/16/2002-IR(B-II)]
RAJINDER KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI SANT SINGH BAL, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, NEW DELHI

I. D. No. 44/2002

IN THE MATTER OF DISPUTE BETWEEN:

Smt. Maya W/o Shri Karan Singh,
RZ-21, Nallaha Par Basti,
Gali No. 1, East Sagar Pur,
New Delhi

... Workman

Versus

The Regional Manager,
Punjab National Bank,
Regional Office,
PNB, Atma Ram House,
Behind Super Bazar,
Connaught Place,
New Delhi-110001

... Management

APPEARANCES:

None for the workman.

Shri Ashwani Sharma A/R for management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/16/2002-IR(B-II) dated 18-6-2002 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Punjab National Bank in terminating/discontinuing Smt. Maya W/o Shri Karan Singh from service as part time Safai Karamchari w.e.f. 12-12-2000 is justified and legal? If not, what relief is the disputant concerned entitled to?"

2. Brief facts of the case as culled from record are that workman was appointed as part time sweeper by the management and was posted at Punjab National Bank, Branch Office Gopinath Bazar, Delhi Cantt. w.e.f. February, 1992 and she had been discharging duty with full sincerity, honesty and devotion and never afforded any opportunity of complaint of any nature whatsoever. She requested the management for regularization of her services and to promote her as full time sweeper from time to time through the branch manager and also made a number of the representations in this regard. Her case had been referred to Senior Manager (Personnel), Regional Office, South Delhi.

Region, New Delhi to promote her as permanent sweeper and sanction her full scale. Her services were terminated for no fault of her in gross violation of relevant rules and labour laws applicable and in principles of natural justice and without prior notice. Order of termination is liable to be set aside and she is entitled to reinstatement with full back wages and continuity of service with other benefits.

3. The case has been contested by the management by filing written statement raising preliminary objection that there does not exist any relationship of employer and employee between the petitioner and the management and she is not entitled to regularization and she was engaged for limited period by way of Section 2(oo)(bb). Heard. The non-continuance in the stop gap arrangement does not constitute retrenchment.

4. On merits it is stated that she has been engaged as part time sweeper at Gopinath Bazar Branch of the bank, Delhi Cantt. for specific period as and when regular sweeper absented from office and her disengagement does not amount to retrenchment. The claim is sought to be dismissed.

5. Perusal of record shows that the workman last appeared on 2-11-05. After completion of pleadings claim was fixed for evidence/cross-examination of the workman on 29-3-06, 20-6-06, 6-9-06, 7-12-06 and today also but she has failed to appear for cross-examination. It seems that she is not interested in the prosecution of this reference which gives rise to the presumption that she does not dispute the action of the management under reference between her and the management.

Hence No Dispute Award is passed accordingly. File be consigned to record room.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

Dated : 8-3-07 SANT SINGH BAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

का.आ. 1073.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अजमेर के पंचाट (संदर्भ संख्या 5/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-03-2007 को प्राप्त हुआ था।

[नं. एल-12011/6/2000-आई आर (बी-II)]

राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd March, 2007

S.O. 1073.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 5/2001)

of the Labour Court and Industrial Tribunal, Ajmer as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 21-03-2007.

[No. L-12011/6/2000-IR(B-II)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer

अनुबन्ध

न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण,
अजमेर

सी. आई. टी. आर. नं. 5/01

[रेफरेंस संख्या एल-12011(6)2000/आई. आर./
(बी. द्वितीय)/दि. 12-6-2000]

दी एसिसटेंट जनरल सेक्रेटरी, बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ यूनियन
द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय रोड,
शाखा, अजमेर ... प्रार्थी

बनाम

बैंक ऑफ बड़ौदा, दी रीजनल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा,
क्षेत्रीय कार्यालय, रेलवे कैम्पस, पोस्ट बैग नं. 164, स्टेशन रोड,
अजमेर (राज.) ... अप्रार्थी

समक्ष :

श्री गंगासिंह शेखावत, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री एस. के. भार्गव, अधिवक्ता

अप्रार्थी की ओर से : श्री बी. डी. भार्गव, अधिवक्ता

अवार्ड

दि. 24-2-07

श्रम मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त रेफरेंस इस प्रकार है :

"Whether the demand of the Bank of Baroda Staff Union, Rajasthan for transfer of Shri K. H. Sethi from Nasirabad to Ajmer and payment of all allowances as per Bank Rules during the temporary posting of workman from January 1997 to April 1999 is legal and justified ? If not what relief the concerned workman is entitled to ?"

प्रार्थी ने अपने क्लेम के विवरण में अंकित किया है कि प्रार्थी प्रतिपक्षी की शाखा नसीराबाद में स्थाई रूप से कैशियर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी के स्वयं के प्रार्थना-पत्र पर उसका स्थानान्तरण अम्बाजी गुजरात से अजमेर क्षेत्र राजस्थान जोन में आदेश दि. 14-12-96 के द्वारा किया गया था। उसकी अनुपालना में प्रार्थी ने अजमेर क्षेत्रीय कार्यालय में अपना पद ग्रहण किया। प्रार्थी को अस्थायी रूप से नसीराबाद शाखा में आदेश दि. 17-1-97 के द्वारा पदस्थापित किया जिसकी अनुपालना में

18-1-97 को प्रार्थी ने नसीराबाद में कार्यग्रहण किया। प्रार्थी का नसीराबाद में पद स्थापन प्रतिपक्षी के हित के लिये किया गया था। प्रार्थी ने 20-5-98 को 3 पत्र अजमेर में पदस्थापित करने हेतु लिखे लेकिन प्रतिपक्षी ने कोई कार्यवाही नहीं की। श्रीमती सरिता लोहिया को कनिष्ठ होते हुए भी गुजरात से अजमेर में पदस्थापित कर दिया जबकि प्रार्थी वरिष्ठ होने के आधार पर अजमेर में पहले पदस्थापित होने योग्य है। प्रार्थी ने 11-12-97 से 29-12-97 के मध्य टी. ए. बिल्स की राशि की भी मांग की किन्तु प्रतिपक्षी द्वारा देय नहीं मानी। अंत में प्रार्थी को अजमेर में स्थाई रूप से कैशियर के रूप में पदस्थापित करने और बाई पार्ट सेटलमेंट के अनुसार 18-1-97 से 6-4-99 तक टी. ए., डी. ए. की राशि मय ब्याज दिलाने का अवार्ड पारित करने की प्रार्थना की।

प्रतिपक्षी ने उत्तर में अंकित किया है कि प्रार्थी का स्थानान्तरण अम्बाजी से अजमेर क्षेत्र में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर किया गया था। बैंक की आवश्यकता तथा हित को ध्यान में रखते हुए और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् क्षेत्रीय प्रबंधक अजमेर ने प्रार्थी का पदस्थापन अस्थायी रूप से बैंक की नसीराबाद शाखा में किया। नसीराबाद अजमेर से 22 कि. मी. दूर स्थित है। प्रार्थी अजमेर के नजदीक पोस्टिंग चाहता था अतः उसने लिखित में यह अण्डरटेकिंग दी कि वह टी. ए., डी. ए. का क्लेम नहीं करेगा। अतः प्रार्थी को टी. ए., डी. ए. देय नहीं है। श्रीमती सरिता गोयल का स्थानान्तरण विवाह के आधार पर उसके पति के पारिवारिक न्यायालय अजमेर में कार्यरत होने के कारण अजमेर में किया गया था। प्रतिपक्षी ने पत्र दि. 6-4-99 के द्वारा प्रार्थी को नसीराबाद शाखा में दिनांक 1-1-99 से नियमित किया है। अंत में क्लेम निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थी ने अपने क्लेम की सम्पुष्टि में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपरीक्षण करवाया है। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-20 प्रलेखों की प्रतियां प्रदर्शित करवाकर प्रस्तुत की हैं। प्रतिपक्षी ने मनोज कुमार बक्षी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रतिपरीक्षण करवाया है और प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श एम-1 से 6 की प्रतियां प्रदर्शित करवाकर प्रस्तुत की हैं।

उभय पक्ष का श्रवण किया और पत्रावली का अवलोकन किया।

जहां तक प्रार्थी के नसीराबाद से अजमेर स्थानान्तरण की मांग का प्रश्न है प्रार्थी का स्थानान्तरण अम्बाजी से राजस्थान जोन के अजमेर क्षेत्र में प्रार्थी के आवेदन पर प्रदर्श एम-1 के अनुसार किया था। जिसमें प्रार्थी ने स्पेशल पे छोड़ने की अण्डरटेकिंग भी दी थी। एम-1 में यह भी अंकित है कि बैंक के प्रार्थी को भारत की किसी भी शाखा में स्थानान्तरण करने के अधिकार का इससे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वयं प्रार्थी ने भी प्रदर्श एम-2 पत्र द्वारा अजमेर या अजमेर से नजदीक स्थानान्तरण की मांग की थी। प्रदर्श एम-3 के अनुसार भी प्रार्थी ने राजस्थान जोन के किसी भी कार्यालय या शाखा में स्थानान्तरण करने की मांग की थी। इसी प्रकार प्रतिपक्षी ने भी प्रदर्श एम-4 पत्र के द्वारा राजस्थान जोन की किसी भी शाखा में स्थानान्तरण पर विचार करने का प्रार्थी को लिखा था। प्रदर्श एम-5 के द्वारा प्रार्थी ने राजस्थान क्षेत्र में किसी भी शाखा में स्थानान्तरण करने हेतु अपनी सहमति दी थी। इस प्रकार प्रार्थी ने स्वयं के आवेदन पर और उसके अण्डरटेकिंग के आधार पर उसका स्थानान्तरण अजमेर क्षेत्र

में अम्बाजी से किया गया था न कि अजमेर शहर में। प्रार्थी के कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही उसका अस्थायी रूप से पदस्थापन नसीराबाद शाखा में कर दिया और उसके बाद स्थाई रूप से नियमित कर दिया गया था। श्रीमती सरिता गोयल का पदस्थापन अजमेर में उसके विवाह के पश्चात् पति के निवास करने के कारण उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पेशल केस मानकर किया गया था। स्वयं प्रार्थी ने नसीराबाद पदस्थापन पर टी. ए., डी. ए. नहीं लेने की अण्डरटेकिंग प्रदर्श एम-6 के द्वारा दी है। प्रार्थी का अजमेर पदस्थापन करवाने का कोई अधिकार नहीं बनता। अतः यह मांग अवैध एवं अनुचित है।

जहां तक जनवरी 97 से अप्रैल 99 तक टी. ए., डी. ए. प्रार्थी को दिलाने की मांग का सम्बन्ध है स्वयं प्रार्थी ने अपने हित को ध्यान में रखते हुए अम्बाजी से अजमेर क्षेत्र के स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करते हुए तथा अजमेर क्षेत्र में स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करते हुए नसीराबाद शाखा में पदस्थापन पर टी. ए., डी. ए. क्लेम नहीं करने का अण्डरटेकिंग प्रदर्श एम-6 दी है। जो प्रार्थी ने अस्थायी पदस्थापन पर अपने टी. ए., डी. ए. के अधिकार को छोड़ दिया है एवं इस सम्बन्ध में विद्यमान नियम और समझौता निरर्थक हो जाता है। अतः प्रार्थी की यह मांग भी अनुचित है।

आदेश

फलतः इस विवाद का उत्तर इस प्रकार से दिया जाता है कि बड़ौदा बैंक के स्टाफ यूनियन के के. एच. सेठी का स्थानान्तरण नसीराबाद से अजमेर करने और जनवरी 1997 से अप्रैल 1999 तक के टी. ए., डी. ए. के भुगतान की मांग अवैध एवं अनुचित है। प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अवार्ड की प्रति नियमानुसार केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भिजवा दी जावे।

अवार्ड आज दि. 24-2-07 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

जी. एल. शेखावत, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

का.आ. 1074.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ई. सी. एल. के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 04/1994) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-3-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/285/1993-आई आर (सी-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd March, 2007

S.O. 1074.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 04/1994) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour

Court, Asansol now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of E.C.L. and their workmen, which was received by the Central Government on 22-3-2007.

[No. L-22012/285/1993-IR(C-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT:

Sri Md. Sarfaraz Khan, Presiding Officer

Reference No. 4 of 1994

PARTIES:

The Agent,
Naba Kajora Colliery of E.C.L.,
Burdwan

Versus

The Working President,
Colliery Mazdoor Union,
Ukhra, Burdwan.

REPRESENTATIVES:

For the Management : Sri P.K. Das, Advocate

For the Union (Workman) : Sri M. Mukherjee, Advocate

Industry : Coal State : West Bengal

Dated the 4-5-2005

AWARD

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section(1) and Sub-Section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter No. L-22012/285/93-IR(C-II) dated 21-1-1994 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Naba Kajora Colliery PO : Kajoragram, Distt. : Burdwan, under Kajora Area of M/s E.C. Ltd., in dismissing Shri Ramchandra Behara, Wagon Loader, Naba Kajora Colliery vide their letter No. KA/PM/C-6/10/3369 dated 31-3-92 is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. After having received the order of aforesaid reference bearing No. L-22012/285/93-IR(C-II) dated 21-1-94 from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi, a reference case No. 04 of 1994 was registered and an order to issue notices to the respective parties through

the registered post was passed which was accordingly issued with a direction to appear in the court and file their respective written statements along with the documents in support of their claims fixing on 12-8-96. In pursuance to the notices issued Sri P.K. Das, Advocate for the management and Sri M. Mukherjee, Advocate for the union appeared in the court and filed their respective written statements in support of their case.

3. In brief compass the case of the union as set forth in its written statement is that Ramchandra Behara was permanent employee as Wagon Loader in Naba Kajora Colliery.

4. The main case of the union is that the delinquent employee Ramachandra Behara could not attend his duty from 13-11-90 on account of illness. Thereafter for better treatment and nursing he left for his home as he had none to take care of him at his residence. After becoming fit he reported for duty on 3-3-92 but he was not allowed to join his duty. On the other hand he was given a charge sheet dated 30-1-92 for his absence till w.e.f. 13-11-90 to 30-1-92. He duly relied the charge sheet but the management not being satisfied with the reply proceeded to hold enquiry in to the said charge and subsequently the workman was dismissed from service on 31-3-92.

5. It is also the case of the union that no enquiry was held before dismissing the said employee or if held, the workman was not given any opportunity to defend himself before the enquiry nor he was intimated that enquiry is going to be held against him. As such the dismissal order is illegal, arbitrary whimsical, colourable exercise of powers and violation of principle of natural justice.

6. The further case of the union is that before issuing dismissal order the management having not supplied copy of enquiry proceeding, enquiry report and proposed punishment to the workman. So the illegal order is void ab-initio and fit to be set aside on the sole score alone. Besides this the management has snatched away bread of the concerned workman by awarding capital punishment in this day of acute unemployment.

7. It is also the claim of the union that the quantum of punishment is too harsh and disproportionate to the quantum of offence if any. The union has sought a relief for setting aside the said order of dismissal with the direction to the management to reinstate the delinquent employee in service with full back wages.

8. On the other hand the defence case of the management as per the averments made in his written statement in short is that the instant reference as referred by the Ministry of Labour is entirely misconceived and the same is not maintainable in law and there is no valid reasons or ground for initiating any Industrial Dispute on the terms of reference as referred to by the appropriate Govt. for adjudication before the Tribunal.

9. The main defence case of the management is that the concerned workman was chargesheeted by the management for act of misconduct as per the provisions of model standing orders applicable to the establishment. The delinquent employee submitted his explanation in reply to the chargesheet which was found to be not satisfactory by the management and an independent enquiry officer was appointed by the management for enquiry into the chargesheet. The said enquiry officer conducted the enquiry proceeding in presence of the parties and all reasonable opportunities were given to the concerned workman in accordance with the principle of natural justice. The said enquiry officer submitted its enquiry report before the competent authority as the charges framed against the workman concerned was duly established and proved. The competent authority having considered carefully the chargesheet, enquiry proceedings along with its report was pleased to pass an order of dismissal against the workman concerned and the said order of dismissal was duly served upon him. The management has claimed that the order of dismissal has been rightly passed by the competent authority in accordance with the gravity of the misconduct which is quite proportionate in accordance with the gravity of the misconduct. So the action of the management in dismissing the concerned workman be held to be quite justified and the union is not entitled to any relief as claimed in his pleading.

10. In view of the pleadings of both the parties and the materials available on the record I find certain facts which are admitted by the respective parties. So before entering into the discussion of the merit of the case I would like to mention the facts which are admitted one.

11. It is the admitted fact that Sh. Ramchandra Behara, Wagon Loader, was the permanent employee of Naba Kajora Colliery of M/s. Eastern Coalified Ltd.

12. It is the further admitted that the delinquent workman was absented from his duty w.e.f. 13-11-90 to 30-1-92 without any prior permission and information of the management.

13. It is also admitted fact that the workman concerned was chargesheeted on 30-1-92 for his unauthorized absence from duty w.e.f. 13-11-90 and explanation to that effect was submitted by the delinquent employee.

14. It is the next admitted fact that a domestic enquiry was conducted by an enquiry officer and the workman had duly participated in the enquiry proceeding and sufficient opportunity was given to defend himself and in the domestic enquiry he was held guilty for the only charge of unauthorized absence for the said relevant period. It is also admitted fact that there is no chargesheet against the workman for being habitual absentee.

15. It is the settled principle of law that the facts admitted need not be proved. Since these all aforesaid facts

are admitted one so I do not think proper to discuss the same in detail.

16. On perusal of the record it transpires that on 1-10-97 a hearing on the preliminary point was made by the then Presiding Officer. The validity and fairness of the enquiry proceedings was not challenged by the union, so the enquiry proceeding was held to be fair and valid and accordingly the date for final hearing on merit was fixed on 4-5-05 and the award was kept reserved for order.

17. From the side of the management in para 1 and 2 of its written statement a plea has been taken that the instant reference is bad in the eye of law as the same is not legally maintainable. It is also claimed that in view of the facts and circumstances of the case the dispute is misconceived one. But aforesaid issue was neither raised nor pressed by the side of the management during the course of the final hearing of the reference. The management has neither examined any oral witness nor tendered even a chit of paper in support of its plea. As such I do not find any defect in the maintainability of this reference and the facts of this case very well comes under the purview of Industrial Disputes Act, 1947. The Govt. of India, through the Ministry of Labour has rightly referred the dispute to this Tribunal for its adjudication and as such the issue is decided against the management and in favour of the union.

18. On perusal of the record it transpires that none of the parties has examined any oral witness in support of their case rather they have filed some Xerox copies of the documents. The management has filed the Xerox copy of the enquiry proceeding along with the enquiry reports of the enquiry officer. These all documents are admitted one as the genuineness of the same has not been challenged by the union. Like wise the union has also filed some copy of the documents in support of its claim. Xerox copy of the chargesheet, order of the dismissal, explanation to the chargesheet given by the workman and the Medical Certificate along with the prescription have been filed on behalf of the union. Most of the documents filed by the union are admitted as they have been issued by the management itself. The explanation submitted by the workman is also admitted one. So far the medical certificates and the prescription filed by the union are concerned, they are also relevant and admissible as their contents and genuineness have not been challenged by the management either in its written statement or during the course of argument.

19. From perusal of the enquiry proceedings and its report it is clear that the delinquent employee had participated in the enquiry proceedings. He has categorically stated that he had reported sick to the colliery dispensary on 13-11-90 and thereafter he went to his father-in-law at Kumardubhi Colliery where he resides as employed there. He has also admitted that he was absent from his duty since 13-11-90 to 14-2-92 due to his illness

and during the said relevant period he was undergoing the treatment of T.B. at Kamla Sewasadan, Nirsa, Dhanbad. He has admitted in his statement before the enquiry officer that he did not send any information to the management about his illness and treatment due to his being ignorant of the circular or procedure of the colliery. The witness of the management have also admitted before the enquiry officer that the workman concerned had reported sick to the colliery dispensary on 13-11-90 and did not continue his treatment at the colliery dispensary since 15-11-90.

20. Having gone through the entire facts, circumstances, enquiry proceedings along with the findings of the enquiry officer I find that the delinquent workman was admittedly absent from his duty w.e.f. 13-11-90 to 30-1-92 i.e. about one year and three months continuously without any prior permission and information to the management. The enquiry officer has rightly held him guilty for an unauthorized absence and in view of the aforesaid prevailing facts the delinquent workman deserves some suitable punishment for the alleged misconduct as per the provision prescribed in the Model Standing Order applicable to the establishment.

21. Now the only main point for consideration before the court is to see as to how far the punishment of dismissal awarded to the workman by the management is just, proper and proportionate to the alleged nature of misconduct proved.

22. Heard both the representatives of the parties on the aforesaid points in question in detail. It was argued by the side of the union that it is a simple case of an unauthorized absence and the absence from the duty during the relevant period is duly explained and the reasons of absence supported with the prescription and the medical certificate have been found to be sufficient and relevant one as the enquiry officer in his finding has not whispered even a word that the unauthorized absence was without any sufficient cause. The medical certificate and the prescription granted by the Doctor S.K. Mondal of Kamla Sewasadan, Nirsa, Dhanbad go to show that the delinquent employee was suffering from acute Hilliary Tuberculosis along with severe anemia and was under his treatment for the said disease w.e.f. 13-11-90 to 14-2-93. I find sufficient force in the argument of the union side. Besides this it is admitted by the witnesses of the management side during the enquiry proceeding that the workman had already reported sick to the colliery dispensary on 13-11-90 and did not continue his treatment in the colliery dispensary since 15-11-90. Such sick leave is not posted in Form still he did not obtain fitness certificate by the colliery dispensary. The workman has also clearly stated before the enquiry officer during the enquiry proceeding that he had reported sick to the colliery dispensary but he went to Kumardubhi to his father-in-law's house who is employed there in the colliery because he was vomiting blood. In

view of the prevailing facts and circumstance I am convinced to hold that the workman was absent during the relevant period under the compelling circumstance beyond his control.

23. It was further argued that the workman concerned has got unblemish record during his service tenure and there has not been any complain of any misconduct either by unauthorized absence or any other nature of misconduct so far. The management has also not charged sheeted him for habitual absence nor any chit of paper in this context has been filed in the court nor there is any pleading in this respect as well. So it can very well be easily concluded that it is the first offence of the workman which has been sufficiently explained and supported by the medical certificate and the prescriptions which remain unchallenged, relevant and admissible. These documents indicate the compelling circumstance prevailing during the relevant period of absence from duty of the workman which were beyond his control.

24. It was also submitted during the course of argument by the union that it is a simple case of unauthorized absence sufficiently explained with convincing reasons which can not be said to be a gross misconduct. The attention of the court was drawn towards the provisions of the Model Standing Order where the extreme punishment prescribed is dismissal as per the gravity of the misconduct and it was claimed that the extreme penalty can not be imposed upon the workman in such a minor case of alleged misconduct of unauthorized absence. The argument of the union side on this point has got much force.

25. It has been several times clearly observed by the different Hon'ble High Courts and the Apex Court as well that before imposing a punishment of dismissal it is necessary for the disciplinary authority to consider socio-economic background of the workman, his family background, length of service put in by the employee, his past record and other surrounding circumstances including the nature of the misconduct and lastly the compelling circumstance to commit the misconduct. These are the relevant factors which must have to be kept in mind by the authority at the time of imposing the punishment which obviously not been done by the competent authority in this case.

26. The next vital point taken by the union during the course of argument is that no second show cause notice was ever issued or served upon the workman concerned before passing the order of punishment of dismissal which is the direct and deliberate violation of the mandate of the Hon'ble Apex Court. The management is silent on this point in its written statement and during the course of hearing. The circular in this regard has already been issued and circulated by the office of the highest authority of the Coal India Limited to all its concern together with the reference

of the judgement of the Apex Court in this regard but the same has not been complied which is admittedly the utter violation of the mandate of the Apex Court and the principles of natural justice as well.

27. Admittedly the workman is an illiterate man of Behara by caste who is the member of Scheduled Caste and the member of the weaker section of the society. He is undoubtedly financially weak and poor who had suffered a lot for ten years. The attention of the court was drawn by the union towards the provision of the Model Standing Order laid down under clause 27(1) (page 15) where various minor punishment have been prescribed to be awarded to the workman according to the gravity of the misconduct. I fail to appropriate why only maximum punishment available be awarded in the facts of the present case. It has been observed by the Hon'ble Apex Court that justice must be tempered with mercy and that the delinquent workman should be given an opportunity to reform himself and to be loyal and disciplinary employee of the management. However I am of the considered view that the punishment of dismissal for an unauthorized absence under the compelling circumstances and without any mala fide intention is not just. proper rather it is too harsh a punishment which is totally disproportionate to the misconduct alleged and the same certainly shocks the judicial conscience of the court. Such a simple case of unauthorized absence under the compelling circumstance beyond the control of the workman should have been dealt with leniently by the management. In this view of the matter in order to avoid further prolonged litigation and it would be appropriate if I modify and substitute the punishment myself by exercising the power under Section 11(A) of the Industrial Disputes Act, 1947 to meet the ends of justice and as such the impugned order of dismissal of the concerned workman is hereby set aside and he is directed to be reinstated with the continuity of the service and in the light of the facts, circumstances and the misconduct for which the punishment of dismissal was imposed on the workman concerned. I think it appropriate that the concerned workman be imposed a punishment of withholding two consecutive increments without any cumulative effect. It is further directed that the delinquent workman will not be entitled to any back wages for the period of dismissal accordingly it is hereby

ORDERED

that let and "Award" be and the same is passed. Send the copies of the award to the Ministry of labour, Govt. of India, New Delhi for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

MD. SARFARAZ KHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2007

का.आ. 1075.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ई. सी. एल. के

प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 118/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-3-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/79/1999-आई आर (सी-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd March, 2007

S.O. 1075.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 118/1999) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of E.C.L. and their workmen, which was received by the Central Government on 22-3-2007.

[No. L-22012/79/1999-IR(C-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT:

Sri Md. Sarfaraz Khan, Presiding Officer

Reference No. 118 of 1999

PARTIES:

Amritnagar Colliery

Versus

Sri Sunder Singh.

REPRESENTATIVES:

For the Management : Sri P.K. Goswami, Advocate

For the Union (Workman) : None

Industry : Coal

State : West Bengal

Dated : 6-2-2007.

AWARD

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section(1) and Sub-Section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, Govt. of India through the Ministry of Labour vide its order No. L-22012/79/99-IR (CM-II) dated 3-8-1999 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this tribunal :

"Whether the action of the management of Amrit Nagar Colliery in refusing the employment of Sh. Sunder Singh as dependent of Late Hardoyal

Singh after attainment of adulthood i.e. 18 years is justified ? If not, to what relief Sh. Sunder Singh, a dependent of Hardoyal Singh is entitled ?”

On having received the Order No. L-22012/79/99-IR (CM-II) dated 3-8-99 of the said reference from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute a reference case No. 118 of 1999 was registered on 18-8-99/3-1-01 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices to the parties concerned through the registered post directly them to appear in the court on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said orders notices by the registered post were sent to the respective parties.

On perusal of the record it transpires that Sri P.K. Goswami, Advocate had appeared in the court to represent the management and had filed written statement in support of its claim. It is further clear from the record that due to non-appearance of the union a no dispute award was passed

on 9-5-02 by my predecessor against which a Misc. case No. 10 of 2002 was preferred for restoration of the same which was allowed to be restored to its original file and parties were directed to take a suitable step on their behalf. The order sheet of the record further go to show that several adjournment was granted to the Union to file its written statement right from 4-5-06 to 10-8-06 even by way of last chance, but the union did not care to appear and file written statement in support of its case w.e.f. 10-8-06 to 6-2-07. These all facts and circumstance indicate that the Union is not at all interested to contest the dispute and henceforth it is not proper, just and advisable to keep the old reference pending any more as no useful purpose is to be served. As such it is hereby

ORDERED

that let a “No dispute Award” be and the same is passed. Send the copies of the order to the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

MD. SARFARAZ KHAN, Presiding Officer.